RNI No : MPHIN/2022/82783
कुल पृष्ठ : 52, मूल्य : 50 रुपए
वर्ष 03, अंक 6 मासिक पत्रिका
25 जून 2024

हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

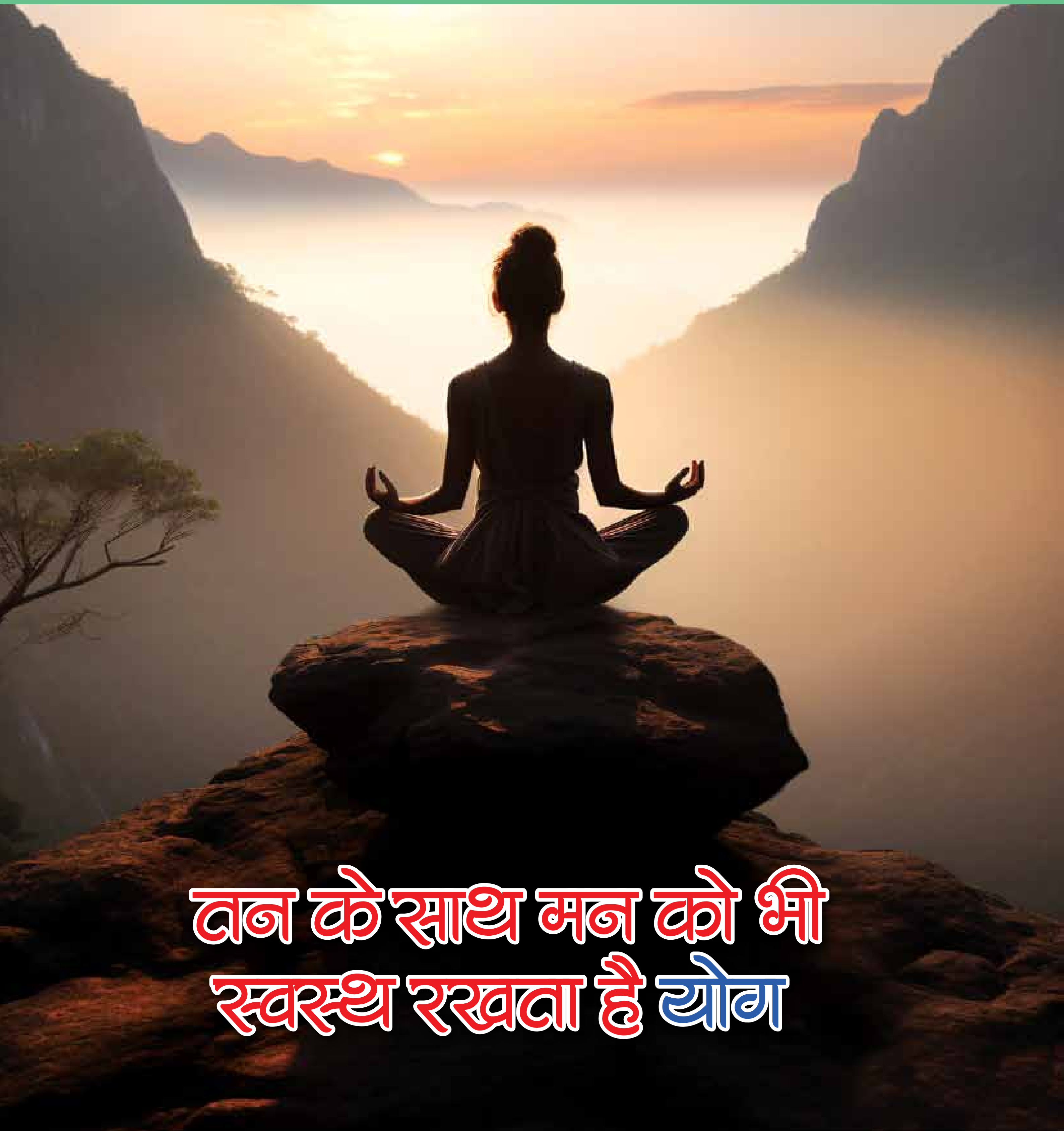

तन के साथ मन को भी स्वस्थ रखता है योग

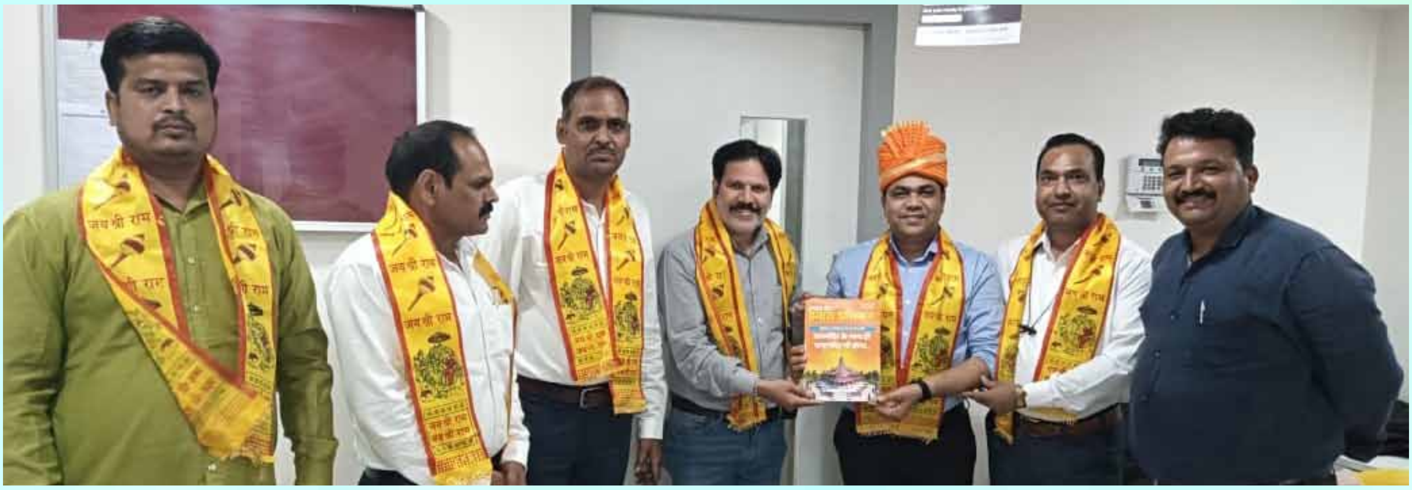

टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के रीवा क्लस्टर के मुख्य अधिकारी राजेश वर्मा एवं अन्य पदाधिकारी, उदयवीर सिंह, ग्वालियर ब्रांच हेड अनिल शर्मा के साथ मिलकर जीवन बीमा क्यों महत्वपूर्ण है और किसलिए कराना चाहिए पर विशेष सेमिनार किया गया यह सेमिनार टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस रीवा क्लस्टर और हमारा देश हमारा अभियान के सयुक्त प्रयास से संपन्न हुआ इसमें संपादक मनोज चतुर्वेदी ने हमारा देश हमारा अभिमान पत्रिका की ओर से नेतृत्व किया तथा इसमें अर्चना बाजपेई, अर्चना खन्ना, अशोक गोयल, रवि परिहार आदि एडवाइजर भी शामिल हुए। और इन्होंने अपना अपना पक्ष रखा।

हमारा देश
हमारा अभिमान

25 जून 2024

वरिष्ठ संरक्षक मंडल

- अनन्त श्री विभूषित श्रीमद जगद्गुरु श्री राम स्वरूपचार्य जी महाराज कामदगिरि पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम
- श्री महामंडलेश्वर रामप्रिय दास
- श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनिरुद वन जी, श्री धूमेस्वर धाम
- श्री डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
- डॉ. श्रीमती शालिनी कौशिक
- श्री नागेंद्रनाथ सुरेंद्र नाथ चौबे

संरक्षक मंडल

- श्री लोकेश चतुर्वेदी
- श्री डॉ. दिनेश उपाध्याय
- श्री अरविंद जैन
- श्री प्रदीप कुमार शर्मा
- श्री शिवदयाल धाकड़
- श्री अरुण कांत शर्मा
- श्री महेश पुरोहित
- श्री विनोद भारद्वाज, अधिवक्ता ग्वालियर हाईकोर्ट,
- श्री मनोज भारद्वाज
- श्री अनिल जैन
- श्री निर्मल वासवानी
- श्री विद्याभूषण शर्मा
- श्रीमती अर्चना बाजपेयी
- एडवोकेट श्रीमती रिचा पांडेय (सुप्रीम कोर्ट)
- श्री के.एल.दलवानी
- श्री राकेश कुमार सगर
- श्री जयराज कुबेर
- श्री अभिनव पल्लव
- श्री बृजेश श्रीवास्तव
- श्री दीपक कुमार शुक्ला
- श्रीमति निवेदिता गुप्ता
- श्री विनोद कुमार बांगडे
- श्री विनायक शर्मा
- कमांडों कमल किशोर (पूर्व सांसद)
- श्री के. कान्याल

संपादक : मनोज चतुर्वेदी

पंकज दीक्षित
प्रमुख परामर्शदाता

कानूनी सलाहकार
- एडवोकेट अनिल शुक्ला शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर हाईकोर्ट
- एडवोकेट एस.के. पाठक, ग्वालियर
- दीपेंद्र कुमार पाण्डेय, एडवोकेट, उच्च न्यायालय

विशेष संवाददाता
- रवि परिहार • रविकांत शर्मा

ब्यूरो : अविनाश (उज्जैन संभाग)
छिंदवाड़ा ब्यूरो : जितेंद्र चौरे
मुम्बई ब्यूरो (महाराष्ट्र)
सचिंदर शर्मा (फ़िल्म डायरेक्टर)

सलाहकार

- डॉ सुनील शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ
- श्री डॉ. मुकेश चतुर्वेदी
- डॉ. दिनेश प्रसाद (हड्डी रोग सर्जन)
- श्री अनिल दुबे
- श्री विकास चतुर्वेदी
- श्री सुरेश शर्मा
- श्री नारायणदास गुप्ता
- श्री पीयूष श्रीवास्तव
- पंडित श्री चंद्रशेखर शास्त्री
- श्री बृज मोहन आर्य
- श्री विवेक शर्मा
- श्री अशोक कुमार वर्मा
- श्री आनंद कुमार
- श्रीमती रितु मुदगल
- श्री कुंज बिहारी शर्मा
- सुश्री पूजा मावई
- श्री संदीप कुमार पांडेय
- श्री मनोज सिंह
- प्रदीप यादव
- निरंजन शर्मा
- विनीत गोयल
- डॉ. सुधीर राजौरिया, हड्डी रोग विशेषज्ञ
- आशीष त्रिवेदी
- डॉक्टर अशोक राजौरिया
- हेमाटोलाजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट
- डॉक्टर कमल कटारिया
- यशवंत गोयल
- दीपक भार्गव
- अमित जैन इंदौर
- सुरजीत परमार
- संजू जादौन
- डॉक्टर हिमांशु डेंटिस्ट
- रागिनी चतुर्वेदी
- प्रवेंद्र चतुर्वेदी
- प्रखर सिंह

ब्यूरो राजस्थान
सुभाष सोरल (फ़िल्म निर्माता) कोटा
ब्रजेश जैन साक्षात्कार व्यवस्थापक और विज्ञापन संवाददाता इंदौर

संवाददाता : संदीप पाटिल, इंदौर
मार्केटिंग प्रमुख : शैलेन्द्र जैन
मार्केटिंग मैनेजर
- सुनील • हरशूल

डिजाइन : मनोज पंवार

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक मनोज कुमार चतुर्वेदी द्वारा कंचन ऑफसेट डी-1/63, सेक्टर-4, विनय नगर ग्वालियर- फोन नं. 0751-2481433, (म. प्र.) से मुद्रित एवं शिव कॉलोनी गली नं. 4 , रेलवे स्टेशन के पीछे, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, (मध्यप्रदेश) प्रकाशित। संपादक-मनोज कुमार चतुर्वेदी । (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र ग्वालियर रहेगा।)

विवरणिका

संपादकीय	....	02
शुभाशीष	....	03
कवर स्टोरी	....	04-05
योग	....	06
सरहद पार	....	07
देश	....	08
प्रदेश	....	09
देश	....	10
विदेश	....	11
देश	....	12-13
देश	....	16-17
विडंबना	....	18
देश	....	20-21
राजनीति	....	22-23
प्रदेश	....	24-25
इन्दौर	....	26-27
वित्त	....	28-29
देश-प्रदेश	....	30-31
देश	....	32-33
देश-विदेश	....	34-35
देश	....	36-37
प्रदेश	....	38
धर्म	....	41
स्वास्थ्य	....	42
धर्म	....	43
महिला	....	46
खेल	....	47
ग्लैमर	....	48

48
तेजस्वी ने अपनी ताजा तस्वीरों से फैंस को कर दिया पानी-पानी...

संपादकीय

देश की महत्वाकांक्षाओं को कुचल सकता है जल संकट, प्रबंधन का भी अभाव...

जो लोग पर्यावरण कार्यकर्ताओं को 'झोलावाला' या भारत के आर्थिक विकास को पटरी से उतारने वाला मानते हैं, और जो भारत में बढ़ते जल संकट के संबंध में दी जा रही चेतावनियों को नजर अंदाज करते हैं, उन्हें ध्यान देने की जरुरत है। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न जल संकट, जो पानी के अंधाधुंध उपयोग के कारण और गहरा गया है, जिसके प्रति भारतीय पर्यावरणविद लगातार चेताते रहे हैं, सिर्फ पर्यावरण या स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक गंभीर आर्थिक मुद्दा भी है, जो 1.4 अरब की आबादी वाले इस देश की महत्वाकांक्षाओं को कुचल सकता है। अभी भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और 2024 में भी इसके तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन भारत की आकांक्षाएं कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें पानी भी एक है। मूडीज रेटिंग की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 'भारत में जल संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तेज आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के बीच पानी की खपत बढ़ रही है। यह सॉवरेन क्रेडिट के साथ-साथ कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों एवं इस्पात निर्माण जैसे पानी की भारी खपत वाले क्षेत्रों के लिए भी नुकसानदेह है।' 'सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग' किसी देश या संप्रभु इकाई की ऋण पाने की क्षमता का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है, जो यह भी बताता है कि उस देश में निवेश करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के समय में जल संकट जैसे कारक, इससे होने वाली भारी मानवीय पीड़ा के अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। तीव्र औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के साथ भारत का तेज आर्थिक विकास दुनिया की इस सबसे बड़ी आबादी वाले देश में पानी की उपलब्धता को कम कर रहा है। जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता 2031 तक घटकर 1,367 क्यूबिक मीटर रह जाने की आशंका है, जो 2021 में पहले से ही कम 1,486 क्यूबिक मीटर थी। 1,700 क्यूबिक मीटर से कम का स्तर जल संकट को ही दर्शाता है, जिसमें पानी की कमी की सीमा 1,000 क्यूबिक मीटर है।

मनोज चतुर्वेदी
संपादक

शुभाशीष

अभयारण्यों के भीतर जल स्रोतों का निर्माण और रखरखाव जरूरी

वैश्विक स्तर पर वर्ष 2023 तो सबसे गर्म वर्ष माना ही गया, मगर 2024 में स्थितियां और भी विकट लग रही हैं। भारतीय मौसम विभाग की पूर्व में दी गई चेतावनी सच साबित हो रही है और चरम हीटवेव या गर्म लहरों से भारत का अधिकांश हिस्सा झुलस रहा है। इस साल दिल्ली कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजस्थान में बीएसएफ के एक जवान द्वारा रेत में पापड़ तलने का वायरल वीडियो सारे देश ने देखा। सेंटर फॉर सांइस ऐंड एन्वॉयरनमेंट(सीएसई) के अनुमान के अनुसार, गर्मी से जून की शुरुआत तक देश में कम से कम 219 लोगों की मौत हो गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ये गर्म लहरें अब लंबी, तीव्र और लगातार होती जाएंगी। ये विकट परिस्थितियां वन्यजीवों तथा पादप प्रजातियों के लिए भी समान रुप से घातक हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है, जहां जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह स्थिति निरंतर गहरा रही है। असहनीय गर्मी से मनुष्यों के साथ ही जीव-जंतुओं की मौतें भी बढ़ रही हैं। हिमालय से लेकर महासागर तक विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की जीव और पादप प्रजातियां रहती हैं। इनमें कुछ जीव और पादप ऐसे हैं, जो अत्यंत ठंडे या बर्फीले इलाके में रहते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं, जो गर्म इलाकों में जीवित रह सकते हैं। लेकिन गर्मी और ठंड के संतुलन की जो प्राकृतिक व्यवस्था है, उसमें गड़बड़ी या असंतुलन हो जाने से जीवधारियों के साथ ही पादपों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। गर्मी बेजुबान वन्यजीवों के लिए गंभीर संकट पैदा करती है। कई जानवर, विशेष रुप से वे, जो अत्यधिक गर्मी के अनुकूल नहीं हैं, अधिक गर्मी से पीड़ित होते हैं। अत्यधिक गर्मी से निर्जलीकरण और हाइपरथर्मिया जैसी समस्याओं से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। वन्यजीव अक्सर गर्मी से बचने के लिए रात में अधिक सक्रिय हो जाते हैं, जिससे उनके भोजन और सहवास का पैटर्न बाधित हो सकता है। जल स्रोत सूखने से उनके लिए पानी की कमी होती है, जिस कारण जानवरों को पानी की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
संरक्षक

तन के साथ मन को भी स्वस्थ रखता है योग

योग न केवल कई गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित होता है बल्कि मानसिक तनाव को खत्म कर आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। दरअसल यह एक ऐसी साधना, ऐसी दवा है, जो बिना किसी लागत के शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है।

प्रतिवर्ष 21 जून को दुनियाभर के 170 से भी ज्यादा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखे गए प्रस्ताव के जवाब में 11 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना की थी और वैश्विक स्तर पर पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस वर्ष पूरी दुनिया 'स्वयं और समाज के लिए योग' थीम के साथ 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। प्रतिवर्ष यह दिवस मनाने का उद्देश्य योग को एक ऐसे आंदोलन के रूप में बढ़ावा देना है, जो व्यक्ति की तन्यकता को उन्नत करता है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कल्याण को बढ़ावा देता है। वैसे तो योग को विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत प्रयासों के चलते वर्ष 2015 में अपनाया गया था किंतु भारत में योग का इतिहास सदियों पुराना है। माना जाता रहा है कि पृथ्वी पर सभ्यता की शुरुआत से ही योग किया जा रहा है लेकिन साक्ष्यों की बात करें तो योग करीब पांच हजार वर्ष पुरानी भारतीय परंपरा है। करीब 2700 ईसा पूर्व वैदिक काल में और उसके बाद पतंजलि काल तक योग की मौजूदगी के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं।

महर्षि पतंजलि ने अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करने को ही योग बताया था। हिंदू धर्म शास्त्रों में भी योग का व्यापक उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतया मिलन ही अद्वेतानुभूति योग कहलाता है। इसी प्रकार भगवद्गीता बोध में वर्णित है कि दुःख-सुख, पाप-पुण्य, शत्रु-मित्र, शीत-उष्ण आदि द्वंदों से अतीतय मुक्त होकर सर्वत्र समभाव से व्यवहार करना ही योग है। भारत में योग को निरोगी रहने की करीब पांच हजार वर्ष पुरानी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो भारतीयों की जीवनचर्या का अहम हिस्सा है। सही मायनों में योग भारत के पास प्रकृति प्रदत्त ऐसी अमूल्य धरोहर है, जिसका भारत सदियों से शारीरिक और मानसिक लाभ उठाता रहा है, लेकिन कालांतर में इस दुर्लभ धरोहर की अनदेखी का ही नतीजा है कि लोग तरह-तरह की बीमारियों के मकड़जाल में जकड़ते गए। वैसे तो स्वामी विवेकानंद ने भी अपने शिकागो सम्मेलन के भाषण में सम्पूर्ण विश्व को योग का संदेश दिया था लेकिन कुछ वर्षों पूर्व योग गुरु स्वामी रामदेव द्वारा योग विद्या को घर-घर तक पहुंचाने के बाद ही इसका व्यापक प्रचार-प्रसार संभव हो सका और आमजन योग की ओर आकर्षित होते गए। देखते ही देखते कई देशों में लोगों ने इसे अपनाना शुरू किया। आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में योग का महत्व कई गुना बढ़ गया है।

योग न केवल कई गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित होता है बल्कि मानसिक तनाव को खत्म कर आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। दरअसल यह एक ऐसी साधना, ऐसी दवा है, जो बिना किसी लागत के शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। यह मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ाकर दिनभर शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। यही कारण है कि अब युवा एरोबिक्स व जिम छोड़कर योग अपनाने लगे हैं। माना गया है कि योग तथा प्राणायाम से जीवनभर दवाओं से भी ठीक न होने मधुमेह रोग का भी इलाज संभव है। यह वजन घटाने में भी सहायक माना गया है। योग की इन्हीं महत्ताओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा से आह्वान किया था कि दुनियाभर में प्रतिवर्ष योग दिवस मनाया जाए ताकि प्रकृति प्रदत्त भारत की इस अमूल्य पद्धति का लाभ पूरी दुनिया उठा सके। यह भारत के बेहद गर्व भरी उपलब्धि रही कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव के महज तीन माह के भीतर 177 देशों ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति की मोहर लगा दी, जिसके उपरांत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसम्बर 2014 को घोषणा कर दी गई कि प्रतिवर्ष 21 जून का दिन दुनियाभर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए 21 जून का ही दिन निर्धारित किए जाने की भी खास वजह रही। दरअसल यह दिन उत्तरी गोलार्ध का पूरे कैलेंडर वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन की तिथि को ग्रीष्म संक्रांति के साथ मेल खाने के लिए बनाया गया था, जो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और प्रकाश और स्वास्थ्य का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति के नजरिये से देखें तो ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तथा यह समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने में लाभकारी माना गया है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी योग के महत्व को स्वीकारने लगा है। इसलिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी है कि योग को अपनी दिनचर्या का अटूट हिस्सा बनाया जाए। बहरहाल, योग केवल एक व्यायाम नहीं है बल्कि यह शरीर और मन के साथ-साथ स्वयं को सशक्त बनाने का एक बेहतरीन तरीका है।

21 जून को क्यों मनाते हैं योग दिवस

भारत के विश्व गुरु बनने का समय आ गया है। योग के मामले में भारत विश्व गुरु है। भारत ने योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और योग के जरिए सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग लाभकारी है। यह शरीर को रोगमुक्त रखता है और मन को शांति प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति से जुड़ी ये क्रिया अब विदेशों तक फैल चुकी है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस दौरान दुनियाभर के लोग सामूहिक रूप से योगाभ्यास करते हैं।

कब मनाया जाता है योग दिवस

प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य योग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक स्तर पर योग के अभ्यास को प्रोत्साहित करना है।

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य

योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। शरीर स्वस्थ रहता है और रोगों की चपेट में आने से बच जाता है। वहीं अगर कोई रोग से ग्रस्त हैं तो उसके निवारण के लिए भी नियमित योग असरदार होता है।

सकारात्मक जीवनशैली

योग एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। ध्यान व योग मानसिक शांति देता है, जिससे सकारात्मक विचार आते हैं और लोग स्वस्थ जीवनशैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

सांस्कृतिक एकता

योग एक प्राचीन भारतीय परंपरा है, जो अब वैश्विक संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। योग से परस्पर देश विदेश के योगी एक दूसरे से जुड़ते हैं और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देते हैं पहली बार 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। उसी वर्ष 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस प्रस्ताव को 177 देशों का समर्थन मिला। पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस दिन विश्व के लाखों लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। वहीं भारत में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के राजपथ पर हुआ, जिसमें 35000 से अधिक लोग शामिल हुए।

योग दिवस मनाने के लिए 21 जून का ही दिन निर्धारित करने की एक खास वजह है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। यह दिन साल का सबसे लंबा दिन मना जाता है। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है जिसे योग और अध्यात्म के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया।

योग... व्यवसाय और राजनीति से न जोड़ें

जानकार बताते हैं कि अंग्रेजी दवाइयां तुरंत असर तो करती हैं। पर, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता हिला देती हैं। शायद, इस सच्चाई से आम लोग अनभिज्ञ होते हैं कि बड़ी-बड़ी फार्मा कंपनियों के मालिक भी नियमित योगासन करते हैं।

योग की आड़ में देश के भीतर बड़ा धंधा पनप गया है। महानगरों से लेकर कस्बों-गांवों में भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट, प्रशिक्षण केंद्र, योग टीचरों की फौज तैयार हो गई है। योग पर किसी का पेटेंट नहीं होना चाहिए और न ही कोई इसकी किसी को ठेकेदारी करनी चाहिए। योग शरीर को चंगा रखने का मजबूत हथियार है और सदैव रहेगा। देखकर दुख होता है जब योग का शारीरिक जरूरतों से कहीं ज्यादा मौजूदा समय में उसका व्यावसायिक, धार्मिक और सियासत में इस्तेमाल होता है। योग को मात्र स्वस्थ काया तक ही सीमित रखना चाहिए। उसकी आड़ में राजनीतिक जरूरतें पूरी नहीं करनी चाहिए। योग गुरू कहलाकर समूचे संसार में प्रसिद्धि पा चुके बाबा रामदेव ने निश्चित रूप से योग का प्रचार जबरदस्त तरीके से किया। इस दरम्यान उन्होंने बड़ा व्यवसाय भी स्थापित किया। बाजार में हजारों प्रोड्क्टस उतारकर उनकी कंपनी का टर्नओवर लाखों-करोड़ों में नहीं, बल्कि अरबों में पहुंच गया है।

विवादों के इतर देखें तो बाबा रामदेव की कोशिशों की बदौलत ही योग को वैश्विक मान्यताएं मिली। केंद्र सरकार ने भी प्रचार-प्रसार में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। उसके बदले सरकार ने भी उनका फायदा चुनावों में जमकर उठाया। इस सच्चाई से भी इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे योग विज्ञान का कुछ समय बीतने के बाद नुकसान हुआ। योग सत्ता पक्ष और विपक्ष में बंटकर भाजपा और कांग्रेस हो गया। जब पहला योग दिवस मना, तो कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने आयोजन का वॉकआउट किया। यहां तक उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने भी योग नहीं किया। लेकिन भाजपा ने हर्षोल्लास से मनाया। दरअसल, उनके मनाने का कारण क्या था, सभी को पता था। ठीक है, अगर विपक्षी दलों को बाबा रामदेव से कोई आपत्ति या ना-खुशी है, तो उनको योग को विरोध की केटेगरी में नहीं रखना चाहिए।

बहरहाल, कोई कहे बेशक कुछ न, पर सियासत ने योग को धर्म से छोड़ने की भी कोशिशें की। योगासनों में भी धर्मों की एबीसीडी खोजी जाती है। दूसरा, सबसे दुःखद पहलू योग के साथ ये जुड़ा, योग का व्यावसायिकरण कर दिया गया। कईयों की दुकानें योग की आड़ में चल पड़ी हैं। बड़े-बड़े प्रतिष्ठान, कॉलेज, स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो गए हैं, जहां योग सीखाने के नाम पर मोटा माल काटा जा रहा है। योग गुरूओं, एक्सपर्टस व प्रशिक्षकों की तो फौज ही खड़ी हो गई है। बड़े-बड़े नेताओं ने अपने लिए पर्मानेंट योग प्रशिक्षक हायर किए हुए हैं। कुल मिलाकर योग को लोगां ने अब पूरी तरह से स्टेटस सिंबल बना डाला है। यानी मध्यम वर्ग और गरीबों की पहुंच से बहुत दूर कर दिया गया है।

योग विधा नई नहीं है, पांच हजार पूर्व ऋषि परंपराओं से मिली अनमोल धरोहर जैसी है। ज्यादा पुराने समय की बात न करें, सिर्फ आजादी तक का इतिहास खंगाले तो पता चलता है कि उस वक्त तक भी चिकित्सा विज्ञान ने उतनी सफलता नहीं पाई थी जिससे अचानक उत्पन्न होने वाली बीमारियों से तुरंत इलाज कराया जाए। उस वक्त भी जड़ी-बुटियों और नियमित योगासन पर ही समूचा संसार निर्भर हुआ करता था। अंग्रेजी दवाओं का विस्तार कोई चालीस-पचास के दशक से जोर पकड़ा है। तब मात्र एकाध ही फार्मा कंपनियां हुआ करती थी, जो अंग्रेजी दवाइयों का निर्माण करती थीं। विस्तार अस्सी के दशक के बाद आरंभ हुआ। आज तीन से चार हजार के करीब फार्मा कंपनियां अंग्रेजी दवा बनाने में लगी हैं। बावजूद इसके योग का बोलबाला दिनों दिन बढ़ रहा है।

जानकार बताते हैं कि अंग्रेजी दवाइयां तुरंत असर तो करती हैं। पर, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता हिला देती हैं। शायद, इस सच्चाई से आम लोग अनभिज्ञ होते हैं कि बड़ी-बड़ी फार्मा कंपनियों के मालिक भी नियमित योगासन करते हैं। क्योंकि उनको योग के फायदे पता होते हैं। योग को एक नहीं, बल्कि हजारों बड़ी और गंभीर बीमारियों से लड़ने का हथियार माना गया है। वक्त फिर से पल्टा है, इसलिए लोग धीर-धीरे पुरानी दवा पद्धितियों की ओर लौटने लगे हैं। सालों पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मरीज योग की मदद लेने लगे हैं। अनुभवी डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट को डेली रूटीन में योग शामिल करने की सलाह देते हैं। योग चिकित्सक मंगेश त्रिवेदी की माने तो ऐसे कई केस सामने आए हैं, जिसमें 15-20 साल पुरानी बीमारी को खत्म करने के लिए लोगों ने पहले योग की मदद ली और 3 से 4 महीने में इसका असर भी देखा है।

बहरहाल, जरूरत इस बात की है कि योग को राजनीति और धर्म के मैदान में ना घसीटा जाए। कुछ राजनीतिक दल योग और योग को नियमित अपनाने वालों को अपना वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग योग पर एक छत्र राज और अपनी ठेकेदारी भी जमाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, योग सबके लिए है और वह भी निःशुल्क। योग हमें ऋषियों-मुनियों द्वारा दी गई बेशकीमती सौगात है। हमारी धरोहर है जिसे हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़कर गए हैं। इसे सजोकर रखना हम सबका परमदायित्व बनता है। योग के फायदों से हम परिचित हैं। योग को लेकर हमें किसी लोभ-लालच में नहीं पड़ना चाहिए। योग करने वालों को भाजपा का कार्यकर्ता, रामदेव का अनुयायी या आरएसएस का शुभचिंतक नहीं समझना चाहिए। हालांकि, ऐसी मिथ्या अब लोगों से दूर हुई है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सभी अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हुए योग को अपनाएं। 'विश्व योग दिवस' का मकसद हममें योगासन के प्रति ललक पैदा करना और दूसरों को योग के लिए जागरूकता करना मात्र होता है। योग स्वस्थ शरीर का मुख्य सारथी है, इसे दूर न करें, नियमित अपनाएं।

गधों के भरोसे चल रही है पाक की अर्थव्यवस्था... !

पाकिस्तान आतंकी पालने, गरीबी, कंगाली के लिए विश्व में बदनाम है। गरीबी की हालत यह है कि पाकिस्तान को कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। इस हालत में गधे पाक की अर्थव्यवस्था का सहारा बने हुए हैं। पाक में गधा पालन प्रमुख मवेशी पालन बना हुआ है।

भारत नित नई टेक्नोलॉजी और अन्वेषण के जरिए अर्थव्यवस्था की तरक्की के परचम विश्व में फहराए हुए है, वहीं दुश्मनी का भाव रखने वाले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गधों के भरोसे टिकी हुई है। भारत को परमाणु बम की धमकी देने वाली पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और रोजगार गधों के भरोसे चल रही है। गधों की तादाद पाकिस्तान में बढ़ रही है। यह बढ़ती हुई तादाद पाकिस्तान के रोजगार के लिए प्राणवायु बनी हुई है। भारत जहां अपनी अर्थव्यवस्था में लगातार छलांग लगा हुए विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है।

पाकिस्तान आतंकी पालने, गरीबी, कंगाली के लिए विश्व में बदनाम है। गरीबी की हालत यह है कि पाकिस्तान को कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। इस हालत में गधे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का सहारा बने हुए हैं। पाकिस्तान में गधा पालन प्रमुख मवेशी पालन बना हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तान में हर साल गधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पाकिस्तान में हाल ही में साल 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। सर्वे में कई आंकड़े सामने आए, लेकिन चुंबक की तरह सबसे ज्यादा ध्यान खींचा गधों की आबादी के आंकड़ों ने। पाकिस्तान में गधों की संख्या लगभग 1 लाख बढ़ी है। कुल गधों की संख्या अब 59 लाख के आस-पास बताई जा रही है।

सर्वे में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान में गधों की संख्या में तो इजाफा हुआ है, लेकिन जीडीपीके निर्धारित लक्ष्य पीछे रह गए हैं। दुनिया में गधों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी पाकिस्तान में है, जो इन जानवरों को चीन को निर्यात करके पैसा कमाने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने 11 जून को 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। सर्वे के अनुसार पिछले कुछ वर्षों के दौरान भार ढोने वाले वाले गधों की आबादी देश में लगातार बढ़ी है। साल 2019-2020 में पाकिस्तान में गधों की संख्या 55 लाख के आसपास थी। 2020-21 में ये बढ़कर 56 लाख हो गई। 2021-22 में देश में 57 लाख गधे थे। वहीं 2022-23 में इनकी संख्या 58 लाख थी। पशुपालन पाकिस्तान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। देश में 80 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार पशुधन उत्पादन का काम करते हैं। गधों के आंकड़ों से इतर इकोनॉमिक सर्वे में पाकिस्तान की जीडीपी के आंकड़े भी बताए गए। रिपोर्ट के अनुसार सर्वे से पता चला कि पाकिस्तान 2023-24 वित्तीय वर्ष के अपने ग्रोथ रेट के लक्ष्य से पिछड़ गया। देश ने जीडीपी में 2.38 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की है, जबकि टारगेट 3.5 प्रतिशत ग्रोथ का था।

रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसा इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की खराब प्रदर्शन के कारण हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है जिसने 6.25 प्रतिशत की वृद्धि की है, जबकि लक्ष्य 3.5 प्रतिशत का रखा गया था। औद्योगिक क्षेत्र में ग्रोथ 1.21 प्रतिशत रही जबकि सर्विस सेक्टर ने 1.21 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की। कृषि क्षेत्र में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली, जो कि पिछले 19 सालों में सबसे अधिक है। देश में राजकोषीय घाटा 3.7 प्रतिशत दर्ज किया गया। ये पिछले साल के बराबर रहा। वहीं व्यापार घाटा 4.2 प्रतिशत बना रहा। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो पिछले वर्ष के 1 लाख 24 हजार रुपये की तुलना में ये लगभग 10 हजार रुपये बढ़ी है। ये अब 1 लाख 34 हजार रुपये हो गई है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार घाटे में चल रहे सरकारी उद्यमों को अपने नियंत्रण से बाहर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार राष्ट्रीय विमान सेवा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का निजीकरण करने का प्लान बना रही है। पीईएस में जारी आंकड़ों से पता चलता है कि बोझ ढोने वाले जानवरों में घोड़े और खच्चरों की संख्या में पिछले पांच वर्षों में कोई खास बदलाव नहीं आया है, तथा यह क्रमशः चार लाख और दो लाख है। गधे कई पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में अर्थव्यवस्था इन जानवरों के साथ गहरे से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब द्वारा जारी किए गए इस सर्वेक्षण में अन्य पशुधन का भी ब्यौरा दिया गया है। देश में ऊंटों की संख्या जो पिछले चार वर्षों से स्थिर थी, अब बढ़ गई है। इनकी संख्या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 11 लाख से बढ़कर 12 लाख हो गई है। पशुपालन पाकिस्तान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 80 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार पशुधन उत्पादन में लगे हुए हैं।

पाकिस्तान के सीनेटर अब्दुल कादिर का कहना है कि चीनी राजदूत ने पाकिस्तान से कई बार मांस का निर्यात करने को कहा है। अपने सुझाव में सीनेटर मिर्जा अफ्रीदी का कहना है कि चूंकी अफगानिस्तान में जानवर काफी सस्ते हैं इसलिए पाकिस्तान वहां से इनका आयात कर सकता है और फिर इन जानवरों के मांस को चीन को निर्यात कर सकता है। हालांकि वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कमिटी को जानकारी दी कि जानवरों में लंपी त्वचा रोग के फैलने की वजह से अफगानिस्तान से उनके आयात पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही अगर जानवरों के निर्यात की बात करें, तो स्टैंडिंग कमिटी ने पांच निर्यात सेक्टर से बिजली सब्सिडी हटाए जाने को लेकर चिंता व्यक्त की है। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने सीनेट स्टैंडिंग कमिटी को बताया है कि चीन पाकिस्तान से गधों का आयात करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। चीन मांस के निर्यात के लिए एक बड़ा बाजार है।

बाल मजदूरी का मामला...

सोम डिस्टीलरीज की कंपनी का लाइसेंस किया सस्पेंड

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कार्यालय से देर शाम प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी कन्हैया अतुलकर को सस्पेंड किए जाने के समाचार प्रसारित हुए परंतु रायसेन कलेक्टर की ओर से इस समाचार की पुष्टि नहीं की गई। प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी का प्रतिवेदन कार्रवाई के तत्काल बाद और कार्यालय के बंद होने से पहले का है यानी सस्पेंड किए जाने के समाचार प्रसारित होने से पहले का है। बाल आयोग के अध्यक्ष ने जिन 39 बच्चों को मुक्त करने का दावा किया था वह प्रशासन के पास नहीं हैं, जबकि कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी। कलेक्टर के प्रतिनिधि अधिकारी ADM और SDM 5 घंटे बाद पहुंचे जबकि ऑफिस से घटनास्थल की दूरी सिर्फ 20 किलोमीटर थी। रायसेन के कलेक्टर ने बाल आयोग के अध्यक्ष के बयान और कार्रवाई का समर्थन भी नहीं किया है।

डॉ. मोहन यादव की सरकार ने सोम डिस्टलरी पर बड़ी कार्रवाई की है। बाल मजदूरी मामले में कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। फैक्ट्री में 59 नाबालिग बच्चे शराब बनाते मिले थे। सीएम की नाराजगी के बाद जिला आबकारी अधिकारी, तीन आबकारी SI और एक श्रम निरीक्षक पहले ही नप चुके हैं। 15 जून को रायसेन जिले के सेहतगंज में शराब बनाने वाली कंपनी सोम डिस्टलरी से 59 बच्चे काम करते मिले थे। गैर सरकारी संस्था 'बचपन बचाओ' की शिकायत पर बाल संरक्षण आयोग की टीम ने बच्चों का रेस्क्यू किया था। बताया गया था कि बाल मजूदरों को स्कूल बस के माध्यम से फैक्ट्री में लाया जाता था और कम पैसे देकर 15-15 घंटे तक काम कराया जाता था। इन बाल मजदूरों के हाथ केमिकल से गलने लगे थे। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सीएम के एक्शन मोड में आते ही प्रभारी जिला आबकारी आधिकारी कन्हैयालाल अतुलकर, मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड, सेहतगंज को निलंबित किया गया था। साथ ही जिले के तीन आबकारी उप निरीक्षक प्रीति शैलेंद्र उइके, शैफाली वर्मा और मुकेश कुमार को सस्पेंड किया गया था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। फिलहाल सोम डिसलरी 20 दिन के लिए सील की गई है।

अपराधी को सजा और पीड़ित को न्याय दिलाने में मध्यप्रदेश कभी पीछे नहीं रहेगाः मुख्यमंत्री : मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि, अपराधी को सजा और पीड़ित को न्याय दिलाने में मध्यप्रदेश कभी नहीं रहेगा पीछे"। मध्यप्रदेश वह राज्य है, जिसकी देश में मिसाल दी जाती है, ऐसे में यहां अगर कोई अपराध करेगा, तो वह बख्शा नहीं जाएगा। रायसेन जिले में मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड ने नियमों को ताक पर रख कर बालश्रम का घोर अपराध किया है, इसलिए उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले इस मामले से जुड़े लापरवाह अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। यहां उल्लेख करना अनिवार्य है कि इससे पहले बाल आयोग द्वारा मुक्त कराए गए बच्चों को अचानक गायब कर दिया गया था। बाद में उनके बयान करवाए गए जिसमें बाल आयोग की कार्रवाई को मिथ्या बताया गया था। यहां तक की प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी के प्रतिवेदन में भी, बाल आयोग की कार्रवाई को फर्जी बताया गया था।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा है : सिन्हा

उपराज्यपाल ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा, आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है और इसने हमारे पड़ोसी (आतंक के निर्यातक को) हताश कर दिया है। हालिया आतंकी घटनाएं हमारे दुश्मन की हताशा का संकेत हैं। सिन्हा ने कहा कि उनके प्रशासन का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया करना है।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद अपनी आखिरी सांस ले रहा है और हालिया आतंकवादी घटनाएं दुश्मन की हताशा का संकेत हैं। रियासी जिले के तलवाड़ा में सहायक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में जम्मू-कश्मीर पुलिस के 16वें बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बैच की पासिंग आउट परेड में सिन्हा ने कहा, हमें आतंकवादियों और उन्हें आश्रय देने वाले उनके सहयोगियों का पता लगाना चाहिए। कुल 860 कांस्टेबल ने प्रशिक्षण पूरा होने पर परेड में भाग लिया। उन्हें अपने कर्तव्यों का निष्ठा एवं ईमानदारी से पालन करने की शपथ दिलाई गई।

उपराज्यपाल ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा, आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है और इसने हमारे पड़ोसी (आतंक के निर्यातक को) हताश कर दिया है। हालिया आतंकी घटनाएं हमारे दुश्मन की हताशा का संकेत हैं। सिन्हा ने कहा कि उनके प्रशासन का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया करना है। सिन्हा ने कहा, मुझे जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर बहुत भरोसा है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हमेशा उच्च स्तर की पेशेवर उत्कृष्टता दिखाई है।

उन्होंने कहा, हम पुलिस बल के आधुनिकीकरण और पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कैडेटों को सम्मानित भी किया और उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वालों को पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किये। पुलिस महानिदेशक आरआर स्वैन ने भी भर्ती हुए सभी नए कांस्टेबल को शुभकामनाएं दीं और उनसे ईमानदारी से काम करने और लोगों की सेवा के प्रति खुद को समर्पित करने के लिए कहा।

अखिल भारतीय हिंदू सेवादल के द्वारा हमारा देश हमारा अभिमान पत्रिका को अच्छी खबरों के प्रकाशन के लिए और संपादक मनोज चतुर्वेदी के स्पष्ट पत्रकारिता के लिए शील्ड देकर सम्मानित किया गया।

मोदी सरकार का बड़ा फैसला

अब सरोगेसी से मां बनने वाली महिला कर्मचारी भी ले सकेंगी मैटर्निटी लीव

सरोगेसी के मामले में, सरोगेट मां, साथ ही दो से कम जीवित बच्चों वाली मां को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, दोनों में से किसी एक या दोनों के मामले में उनमें से सरकारी कर्मचारी हैं।' यह परिवर्तन यह सुनिश्चित करता है कि जो महिलाएं सरोगेसी का विकल्प चुनती हैं, वे प्राकृतिक रूप से बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं के समान ही मातृत्व लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

केंद्र सरकार ने सरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा करने वाली महिला सरकारी कर्मचारियों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देने के लिए अपने नियमों में संशोधन किया है। यह कदम 50 साल पुराने विनियमन में एक महत्वपूर्ण संशोधन का प्रतीक है जो पहले सरोगेसी मामलों के लिए मातृत्व लाभ को संबोधित नहीं करता था। संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुसार, 'सरोगेसी के मामले में, सरोगेट मां, साथ ही दो से कम जीवित बच्चों वाली मां को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, दोनों में

से किसी एक या दोनों के मामले में उनमें से सरकारी कर्मचारी हैं।' यह परिवर्तन यह सुनिश्चित करता है कि जो महिलाएं सरोगेसी का विकल्प चुनती हैं, वे प्राकृतिक रूप से बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं के समान ही मातृत्व लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

संशोधनों में 'कमीशनिंग पिता' के प्रावधान भी शामिल हैं, जो उसे बच्चे की डिलीवरी की तारीख से छह महीने के भीतर 15 दिनों के पितृत्व अवकाश की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, 'कमीशनिंग मां' अब नए नियमों के तहत चाइल्डकैअर अवकाश का लाभ उठा सकती हैं। कार्मिक मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरोगेट मदर का तात्पर्य उस महिला से है जो कमीशनिंग मां की ओर से बच्चे को पालती है। इसी प्रकार, कमीशनिंग पिता को सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे के इच्छुक पिता के रूप में परिभाषित किया गया है। मौजूदा नियमों के तहत, महिला और एकल पुरुष दोनों सरकारी कर्मचारी अपने पूरे सेवा कार्यकाल के दौरान 730 दिनों तक चाइल्डकैअर अवकाश ले सकते हैं। इस छुट्टी का उपयोग उनके दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल, शिक्षा और बीमारी जैसी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

शपथ लेते ही कंगना ने दी विपक्ष को चुनौती, कहा- सिर्फ चिल्लम चिल्ली करेंगे या कुछ...

कंगना रनौत दिन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनाओं को दोहराती नजर आईं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उनसे नारों के बजाय सार को प्राथमिकता देने और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर अपनी पहली जीत हासिल करने वाली अभिनेत्री-राजनेता कंगना रनौत ने सोमवार को लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ली। अपने शपथ ग्रहण के बाद, रानौत ने विपक्षी इंडिया गुट को चुनौती देते हुए कहा, 'देखते हैं वे मेज पर क्या लाते हैं।' उन्होंने कहा कि जैसा कि पीएम मोदी ने कहा, पूरे देश को उम्मीद है कि विपक्ष अधिक जिम्मेदार होगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा देखते हैं, सिर्फ चिल्लम चिल्ली करेंगे या कुछ मूल्यवान वे मेज पर लाएंगे।

कंगना रनौत दिन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनाओं को दोहराती नजर आईं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उनसे नारों के बजाय सार को प्राथमिकता देने और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ''देश की जनता को विपक्ष से अच्छे कदम की उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि विपक्ष लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए देश के आम नागरिकों की

उम्मीदों पर खरा उतरेगा।"

इस महीने की शुरुआत में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में लौटने के बाद अपना लगातार तीसरा कार्यकाल शुरू किया। अपने मंत्रिपरिषद के साथ, उन्होंने 9 जून को शपथ ली, जो लोकसभा सदस्य के रूप में उनका तीसरा कार्यकाल है। मोदी ने वाराणसी सीट बरकरार रखी, जो 2014 से उनके पास है। सदन के नेता के रूप में, वह पद की शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति थे।

नाटो प्रमुख ने चीन को दी चेतावनी, कहा-

यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन करने पर परिणाम भुगतने होंगे

नाटो ने रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन करने के लिए परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। नाटो महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि रूस की मदद करके चीन यूरोप में सबसे बड़े सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है। नाटो प्रमुख ने सोमवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस का समर्थन करने के कारण पश्चिमी देशों को चीन पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को लगातार हथियारों की आपूर्ति ही इस युद्ध का अंत कर सकती है। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने अगले महीने होने वाली नाटो की 75वीं वर्षगांठ शिखर सम्मेलन की आधारशिला रखने के लिए वाशिंगटन का दौरा किया। जुलाई के शिखर सम्मेलन का उद्देश्य यूक्रेन के लिए समर्थन का एक निर्णायक दीर्घकालिक संदेश भेजना है। क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडन को यूक्रेन के लिए पश्चिमी समर्थन पर संदेह करने वाले डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ एक कठिन पुनर्मिलन लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। बाइडन के साथ बैठक से पहले बोलते हुए स्टोलटेनबर्ग ने चीन पर आरोप लगाया कि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह रूस के रक्षा उद्योग के पुनर्निर्माण के लिए चीन एक प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन है। स्टोल्टेनबर्ग ने विल्सन सेंटर में कहा, 'राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह धारणा बनाने की कोशिश की है कि वह प्रतिबंधों से बचने और व्यापार को चालू रखने के लिए इस संघर्ष में पीछे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि चीन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़े सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही, वह

पश्चिम के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। बीजिंग दोनों तरीकों को नहीं अपना सकता है। जब तक चीन अपना रुख नहीं बदलता तक पश्चिम को उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। चीन को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।''
वहीं चीन का कहना है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के खिलाफ नहीं है। ना ही चीन किसी को गलत तरीके से सहायता दे रहा है। बीजिंग ने स्विट्जरलैंड में यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की द्वारा आयोजित सप्ताहांत शिखर सम्मेलन से दूरी बनाई थी, जिसमें किसी भी शांति के लिए रूस द्वारा यूक्रेनी क्षेत्र छोड़ने की कीव की मांगों की पुष्टि की गई थी।

द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने वाले पूर्व सैनिक ने 100 साल की उम्र में 96 वर्षीय प्रेमिका से की शादी

टेरेंस और स्वेर्लिन ने फ्रांस में नॉरमैंडी के डी-डे समुद्र तट पर स्थित एक 'टाउन हॉल' में शादी की। यह वही स्थान है जहां छह जून, 1944 को मित्र देशों के विमानों केउतरने के बाद भीषण लड़ाई हुई थी जिससे यूरोप को एडोल्फ हिटलर के अत्याचार से मुक्ति दिलाने में मदद मिली। कैरेंटन-लेस-मरैस। द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने वाले अमेरिका के पूर्व सैनिक हारोल्ड टेरेंस ने 100 साल की उम्र में अपनी 96 वर्षीय प्रेमिका जीन स्वेर्लिन से शादी की। टेरेंस और स्वेर्लिन ने फ्रांस में नॉरमैंडी के डी-डे समुद्र तट पर स्थित एक 'टाउन हॉल' में शादी की। यह वही स्थान है जहां छह जून, 1944 को मित्र देशों के विमानों केउतरने के बाद भीषण लड़ाई हुई थी जिससे यूरोप को एडोल्फ हिटलर के अत्याचार से मुक्ति दिलाने में मदद मिली।

टेरेंस और स्वेर्लिन के विवाह समारोह में शामिल हुए कुछ लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय की पोशाक पहनी हुई थीं। जीन स्वेर्लिन ने गुलाबी रंग की पोशाक पहनी थी। वहीं, टेरेंस ने हल्के नीले रंग के सूट पहना। टेरेंस ने इसे ''अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन'' बताया और स्वेर्लिन ने कहा, ''प्यार केवल युवाओं के लिए नहीं हैं।'' नवविवाहित दंपती को शनिवार रात को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ राजकीय रात्रिभोज के लिए एलिसी पैलेस में आमंत्रित किया गया था।

इंदौर को मिली ऊर्जा मंत्री की बड़ी सौगात...

3 माह में 10 ग्रिड तैयार, 50 मेगावाट बिजली वितरण की क्षमता बढ़ी...

गर्मी में बिजली वितरण और व्यवस्था में बाधा पहुंचने के कारण आलोचना झेल रही विद्युत वितरण कंपनी अब बिजली वितरण का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में लगी है। केंद्र सरकार द्वारा अनुदानित रिवेम्प्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) का प्रभावी क्रियान्वय कर मार्च से मई माह के दौरान पश्चिम मप्र में 10 नए ग्रिड तैयार कर लिए गए हैं।

इनसे बिजली वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। इन 33/11 केवी नए ग्रिडों से बिजली वितरण क्षमता में 50 एमवीए का विस्तार हो गया है। अन्य कार्य भी कराए गए है। विशेषकर 555 किमी की विद्युत लाइनों का कार्य कराया गया है। इन सभी कार्यों की कुल लागत करीब 106 करोड़ रुपये हैं। **ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के आदेश :** मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के आदेशानुसार अधोसंरचना के कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे है।लक्ष्य है कि कृषि, घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की अधिक से अधिक मदद हो सके। इंदौर शहर में दो नई ग्रिड से वितरण शुरू हो गया है।खंडवा रोड के बिलावली, इंदौर ग्रामीण के राजोदा में नए बने ग्रिडों को हाल ही में चार्ज किया गया है। इसी तरह कुम्हार खेड़ा, तिवाड़िया, गेरू बेदी, खेड़ा पहाडी, शिवना, जीवन खेड़ी, जोलाना, मोहम्मदखेड़ा में भी 33/11 केवी के नए ग्रिड तीन माह के दौरान पूर्णतः तैयार हुए एवं बिजली वितरण प्रारंभ हुआ है। इंदौर के साथ अन्य जिलों में 100

कैपिसिटर बैंक लगाए गए है।

उच्च दाब 33 केवी लाइन का विभक्तिकरण एवं मिलान का कार्य 30 किमी क्षेत्र में किया गया है। मिक्स फीडरों का विभक्तिकरण कार्य 4 स्थानों पर किया गया है। 30 स्थानों के ट्रांसफार्मरों का मिक्स उपयोग से पृथक किया गया है। 850 स्थानों पर वोल्टेज समस्या समाधान के लिए अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए है। प्रबंध निदेशक ने बताया कि 150 किमी में नई 11 केवी लाइन स्थापित की गई है। इसी तरह 11 केवी/33 केवी लाइनों के तार ज्यादा क्षमता वाले लगाए गए है, इनकी लंबाई 200 किमी है। इसी के साथ 175 किमी की निम्न दाब लाइन का रिनोवेशन कार्य किया गया है।नए इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ी हुई मांग के दबाव और आने वाले समय में भी लाभ मिलेगा और आपूर्ति सुगम हो सकेगी।

भगवान महाकाल के भक्तों के लिए खुशखबरी, अब 3 महीने पहले करा सकेंगे भस्म आरती की बुकिंग...

ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में एक जून से भस्म आरती दर्शन के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत मंदिर समिति अब एक माह पहले अनुमति जारी कर रही है। समिति ने अब तक एक से 31 जुलाई के लिए 9135 लोगों को अनुमति जारी कर दी है। अब खाली रह गईं 3242 सीटों पर अनुमति के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल श्रद्धालुओं को सूचना भेजी जा रही है।

मंदिर प्रशासन के अनुसार, जुलाई माह के लिए प्रतीक्षा सूची में करीब छह हजार श्रद्धालु हैं। महाकाल मंदिर समिति प्रतिदिन 400 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन अनुमति जारी करती है। इसके अनुसार, एक से 31 जुलाई तक 12400 भक्तों को ऑनलाइन अनुमति दी जानी है। समिति प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर अनुमति जारी कर रही है। भस्म आरती की व्यवस्था के प्रभारी और मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने बताया कि मंदिर समिति ने जुलाई माह के लिए नई बुकिंग बंद कर दी है। इस माह के लिए केवल वेटिंग सूची में मौजूद श्रद्धालुओं को अनुमति जारी की जा रही है। श्रद्धालु अब अगस्त, सितंबर

व अक्टूबर माह के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। 31 जुलाई को अगस्त माह की अनुमति जारी कर दी जाएगी।

24 घंटे में प्राप्त करना होगा पास : भक्तों को भस्म आरती बुकिंग होने की सूचना भेजी जा रही है, उन्हें 24 घंटे के अंदर 200 रुपये शुल्क जमा करके ऑनलाइन पास प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर श्रद्धालु ऐसा नहीं करते हैं, तो उस सीट को प्रतीक्षा सूची में शामिल श्रद्धालुओं को जारी कर दिया जाएगा।

नगर निगम ने की नेप्रा कम्पनी को झटका देने की तैयारी...

सूखे कचरे का सेग्रीगेशन करने वाली कंपनी के ठेके की अवधि कम होगी

इंदौर नगर निगम के द्वारा महापौर पुष्यमित्र भार्गव की इच्छा के अनुसार नेप्रा कम्पनी को झटका देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस कंपनी के द्वारा नेमावर रोड पर स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में सूखे कचरे का सेग्रीगेशन करने का काम किया जाता है। इस कंपनी के कामकाज की बढ़ी हुई अवधि को घटाया जाएगा। नेप्रा को जो ठेका दिया गया था उस ठेके की अवधि 2026 तक है। इस अवधि के समाप्त होने की समय सीमा आने से पहले ही नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा इस ठेके की अवधि को बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया। यह काम भी करीब 2 साल पहले ही हो गया था। महापौर पुष्यमित्र भार्गव को पिछले दिनों इस बारे में जानकारी हासिल हुई। यह जानकारी मिलने पर महापौर के द्वारा इस पर आपत्ति ली गई।

अपनी मन- मर्जी से काम किया गया : महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि पहले से दिए हुए ठेके की अवधि जब समाप्त होने आई है तब ही कामकाज के आधार पर ठेके की की अवधि को बढ़ाने का काम किया जाता है। नगर निगम के पूर्व के अधिकारियों के द्वारा इस तथ्य को नजर अंदाज करते हुए अपनी मन- मर्जी से काम किया गया। इन अधिकारियों ने ठेकेदार को उपकृत करने के लिए ठेका समाप्त होने की अवधि करीब आए बगैर

ही ठेके की अवधि को बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया।

स्मार्ट सिटी कंपनी की ओर से प्रक्रिया शुरु

पिछले दिनों महापौर के द्वारा स्मार्ट सिटी कं पनी के अध्यक्ष कलेक्टर आशीष सिंह को एक पत्र लिखकर नेप्रा को ठेके की अवधि जो बढ़ाई गई है उसे समाप्त करने के लिए कहा गया था। इस दिशा में स्मार्ट सिटी कंपनी की ओर से प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इस कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि ऐसा कोई संभव नहीं है कि एकदम से एक आदेश जारी करें और बढ़ाई गई अवधि को समाप्त कर दें। इसके लिए पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। अब इस प्रक्रिया के पालन की कार्रवाई शुरू हो गई है। महापौर की इच्छा के अनुसार नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी के द्वारा इस ठेकेदार एजेंसी के ठेके की बढ़ी हुई अवधि को समाप्त करने का काम शुरू किया जा रहा है।

पैसे की वसूली के लिए भी कार्रवाई शुरू

इसके साथ ही इस ठेकेदार एजेंसी से पैसे की वसूली करने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कंपनी को इंदौर नगर निगम को जो राशि चुकाना है उसमें से काफी राशि बकाया हो गई है। इस बकाया राशि की वसूली करने के लिए नोंो- टेस देने राशि की गणना करने जैसे प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं। आने वाले समय में इस कं पनी से राशि की वसूली करने का काम किया जाएगा।

कान्ह-सरस्वती के आसपास कच्चे अतिक्रमण हटाने के निर्देश...

कलेक्टर आशीष सिंह ने कान्ह और सरस्वती नदी के आसपास कच्चे अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हटाए जाने वाले परिवारों के लोगों के लिए रहने की आवश्यक व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को कहा है। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में टीएल बैठक कलेक्ट्रेट में हुई। कलेक्टर ने हुकुमचंद मिल अंतर्गत राशि भुगतान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पात्रताधारी की मृत्यु हो गई है और मुआवजे के भुगतान में किसी तरह का विवाद ना हो ऐसे प्रकरणों में भुगतान की कार्यवाही समय सीमा में की जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि कान्ह और सरस्वती नदी के आसपास कच्चे अतिक्रमण कतारओं को नोटिस देते हुए उन्हें हटाने की कार्रवाई समय सीमा में सुनिश्चित की जाए। हटाए जाने वाले परिवारों के रहने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए।

सेवा सेतु एप के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधित निर्देश देते हुए अधिक से अधिक दानदाताओं को इससे जोड़ने की बात कही। भिक्षावृत्ति मुक्त इन्दौर अभियान के तहत नियमित फालोअप के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले में कार्यों को 15 अगस्त तक शत प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए। योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सचिव एवं रोजगार सहायक की संयुक्त बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। नेहरू स्टेडियम नगर निगम को अलॉटमेंट की कार्रवाई हेतु आवश्यक कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मूसाखेडी और मल्हार आश्रम में सीएम राइज स्कूल के निर्माण में बाधक अतिक्रमण को हटाते हुए निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। खजराना क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण संबंधित निर्देश दिए। मेरोद अनाज मंडी के लिए नोटिफिकेशन की कार्रवाई करते हुए एफआरए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।

डीडीए पशुपालन को बिचौली में मुर्गी शेड निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य बजट में शामिल किए जाएंगे शिक्षकों के सुझाव - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

शिक्षक होते हैं मित्र और मार्गदर्शक... उनकी राष्ट्रनिर्माण में अहम भूमिका

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षित और सक्षम नागरिक ही राष्ट्र की प्रगति का आधार होते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना और संस्कारों का समावेश कर उन्हें कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा धौलपुर जिले के बाड़ी स्थित ग्राम बिजोली में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रदेश महासमिति अधिवेशन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपने शिष्य का मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत होता है। विद्यार्थी स्कूल में जो कुछ सीखते हैं वह उनके जीवन को दिशा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में शिक्षक का महत्व सर्वोपरि रहा है। हमारी संस्कृति में गुरु-शिष्य परम्परा का विशेष स्थान हैं। कबीर दासजी ने तो गुरु गोविन्द दोउ खड़े... दोहे के माध्यम से गुरु की महत्ता ईश्वर से भी अधिक बताई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में सरकारी स्कूलों के बनुयादी ढांचे को मजबूत करने, स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने तथा शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक की मदद से उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी वंचित वर्गों को शिक्षा मुहैया करवाने के लिए अंतरिम बजट में अल्प आय वर्ग, लघु/सीमांत/बंटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के बच्चों को के.जी. से पी.जी. तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया है।

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए अपने आगामी बजट में शिक्षकों से उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं। सर्वश्रेष्ठ सुझावों को सरकार बजट में शामिल करेगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार हो रहे हैं। विद्यार्थियों में रचनात्मकता और समस्या समाधान का कौशल विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लाई है। यह शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करेगी और शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुखी बनाने तथा विद्यार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। इस नीति के सफल क्रियान्वयन से भारत एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा।

श्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आज देश में 21 आईआईएम, 23 आईआईटी, 22 एम्स हैं। पिछले 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी लगभग दोगुनी हो गई है। हमारे प्रमुख संस्थानों के कैम्पस विदेशों में भी खुल रहे हैं। अबूधाबी में आईआईटी दिल्ली तथा तंजानिया में आईआईटी मद्रास का कैम्पस शुरू हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक संघ का भी दायित्व है कि वे शिक्षकों के हितों के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तकनीकी विकास के साथ ही शिक्षण विधियों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। श्री शर्मा ने कहा कि शिक्षकों की नागरिक होने के साथ ही शिक्षक के रूप में समाज के प्रति दोहरी जिम्मेदारी है। वे अपने आस-पास के प्रत्येक वंचित और जरूरतमंद को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

श्री शर्मा ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें याद करते हुए कहा कि उनका जीवन राष्ट्र के लिए पूरी तरह समर्पित था। डॉ. मुखर्जी ने कश्मीर मुद्दे पर राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखते हुए तत्कालीन कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री श्री अमित शाह ने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए कश्मीर से धारा 370 हटाई।

कार्यक्रम को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक श्री निंबाराम ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र को मजबूत करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा पद्धति में राष्ट्रीयता का समावेश आवश्यक है, जिससे विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम की भावना विकसित हो। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर, गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम, राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कपूर सहित अन्य पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में शिक्षक तथा आमजन उपस्थित रहे।

अपने ही बनाए नियमों को तोड़ रहे हैं पाक के पीएम और उनके मंत्री

इसे पाकिस्तान की विडंबना ही कहें कि जहां आम लोगों को एक्स का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है, वहीं प्रधानमंत्री खुद और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य सुबह-शाम एक्स का उपयोग कर अपने ही नियम को तोड़ रहे हैं। असैन्य तानाशाही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है।

बोलने की आजादी, जुझारू व हर तरह के सेंसरशिप से आजाद मीडिया, असहमति को सहन करने की ताकत, असंतोष को दबाना-ये सभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे हैं, जिनके बारे में हम दुनिया भर में पढ़-सुन रहे हैं। हर जगह शासक और ताकतवर लोग मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं खबरों को प्रकाशित एवं प्रसारित करने की अनुमति देते हैं, जो उन्हें पसंद हों। दक्षिण एशिया के देश दुनिया के अन्य देशों से अलग नहीं हैं और इस हफ्ते मैं अमर उजाला के पाठकों का ध्यान इस खबर की ओर दिलाना चाहूंगी कि पाकिस्तान की मुख्य पार्टियां यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हो गई हैं कि एक ऐसा कानून बनाया जाए, ताकि मीडिया की आवाज को और दबाया जा सके।

हालांकि पाकिस्तानी मीडिया को चुप कराने संबंधी खबरों में सबसे निराशाजनक खबर दिवंगत बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से आई है, जिसने पंजाब प्रांत की पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) की मरियम नवाज सरकार के नए विवादास्पद पंजाब मानहानि विधेयक, 2024 को पारित कराने में साथ दिया है, ताकि उन आक्रोशित नागरिकों को शांत किया जा सके, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। अतीत में जनरल जिया उल हक जैसे सैन्य तानाशाहों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी और विरोध करने वालों को सार्वजनिक रूप से कोड़े तक मारे थे। आज भी मेरे एक बुजुर्ग सहकर्मी नासिर जैदी जीवित हैं, जो बताते हैं कि कैसे तानाशाह ने उन्हें स्वतंत्र रूप से लिखने की हिम्मत करने के लिए कोड़ों से पीटा था। आज असैन्य तानाशाही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। यही नहीं, अब पत्रकारों के गायब होने और उनकी हत्या का खतरनाक चलन भी दिख रहा है।

इससे पहले दुनिया भर के तानाशाहों की तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कुछ महीने पहले पूरे पाकिस्तान में एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब लोगों को वीपीएन इंस्टाल करना पड़ता था, जो सिस्टम को अनब्लॉक करने में मदद करता है, ताकि उपयोगकर्ता ट्वीट कर सकें। इनमें से कुछ वीपीएन मुफ्त हैं, जबकि कुछ अन्य के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है, तभी एक्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जहां आम लोगों को एक्स का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है, वहीं प्रधानमंत्री खुद और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सुबह-शाम एक्स का उपयोग कर अपने ही नियम को तोड़ रहे हैं। इस हफ्ते हम सबको इस बात पर हंसी आई कि एक्स को ब्लॉक किए जाने के बावजूद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ ने भारतीय प्रधानमंत्री को आम चुनाव में जीत की बधाई ट्वीट करके दी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके जवाब दिया।

इस पाखंड को सबने समझ लिया कि पाकिस्तान के राजनेता कैसे अपने ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अब पंजाब प्रांत की सरकार ने पंजाब मानहानि विधेयक, 2024 के लिए आधिकारिक रूप से गजट अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे विवादास्पद कहा जाता है। नए कानून का उद्देश्य यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं से निपटना है, जिससे 'फर्जी खबर' फैलाने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सके।

इस बात से हर कोई सहमत है कि सोशल मीडिया पर जो कुछ पोस्ट किया जाता है, उनमें से कुछ नफरत से भरा और अस्वीकार्य होता है। लेकिन उन अकाउंट को बंद करने के बजाय, जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आप पूरे नेटवर्क को बंद नहीं कर सकते। पत्रकार समुदाय ने इस विधेयक का जमकर विरोध किया है। गैर-लोकतांत्रिक बताते हुए इसकी निंदा की है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से भी प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने के कारण कड़ी आपत्ति जताई गई है। अंग्रेजी दैनिक द डॉन ने संपादकीय में लिखा है- 'ये घटनाक्रम इस बात की याद दिलाते हैं कि हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसे आम नागरिक अभी तक पूरी तरह समझ नहीं सके हैं। यहां चिंता यह नहीं है कि नागरिकों को जो कुछ भी वे कहना या उपभोग करना चाहते हैं, उन्हें उसकी अनुमति दी जानी चाहिए, आखिरकार नागरिक होने के नाते वे भी देश के कानून से बंधे हैं। बल्कि डर यह है कि इन हथकंडों का इस्तेमाल पुलिस और सत्ता से असहमत केवल चुनिंदा लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जाएगा।'

इस हफ्ते की दूसरी चौंकाने वाली खबर यह है कि शहबाज शरीफ सरकार अब इंटरनेट फायरवॉल बना रही है, जिसे कथित तौर पर अधिकारियों ने गुप्त रूप से लागू करना शुरू कर दिया है, जो उन्हें पाकिस्तानी उपयोगकर्ताओं द्वारा इंटरनेट पर पोस्ट की जाने वाली या देखी जाने वाली हर चीज पर जासूसी करने की अनुमति देगा। यह इंटरनेट फायरवॉल ग्रेट फायरवॉल की तरह है, जिसका उपयोग चीनी अधिकारी अपने नागरिकों पर नजर रखने के लिए करते हैं। यह इंटरनेट फायरवॉल इंटरनेट पुलिस की तरह काम करेगा।

प्रकृति एवं पर्यावरण में जहर घोलने से बढ़ी
जानलेवा गर्मी

> इस बार बढ़ती गर्मी ने सारे रेकॉर्ड तोड़ दिये हैं जो हमारे लिए चौंकाने से ज्यादा गंभीर चिंता की बात है। राजधानी दिल्ली के एक इलाके में अधिकतम पारा 52.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो देश के इतिहास का सबसे ज्यादा तापमान है।

लोकसभा चुनाव के प्रचार की गर्मी भले ही समाप्त हो गयी हो लेकिन प्रकृति से जुड़ी गर्मी सौ-डेढ़ सौ वर्षों का रिकार्ड तोड़ते हुए कहर बरपा रही है। दिल्ली का पारा 50 डिग्री से तो ज्यादा ही रहा है। देश के 17 से अधिक शहरों में तापमान उच्चतम स्तर पर चल रहा है। यह एक तरह का प्राकृतिक आपातकाल है। हीटवेव या यों कहें कि लू के थपेड़ों ने जनजीवन को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। लू या हीटवेव या तापघात के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में मौत के समाचार भी आ रहे हैं। तस्वीर का एक पहलू यह है कि अभी तक सही मायने में हमारे देश में हीटवेव को डिजास्टर मैनेजमेंट में पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि शहरों में हीट आइलैंड बन रहे हैं, जिसके लिए मुख्य रूप से सीमेंट-तारकोल और कृत्रिम वातानुकूलित (एसीवाली) जीवनशैली जिम्मेदार है। कंक्रीट और तारकोल के जंगलों का विस्तार करने को जब तक हम अपनी जरूरत समझते रहेंगे तब तक हरे-भरे जंगलों को कटने से कोई नहीं रोक सकेगा। दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर देश जब तक जीडीपी से विकास को मापेगा, बेहिसाब औद्योगीकरण एवं शहरीकरण की होड़ रहेगी, तब तक पर्यावरण असंतुलन एवं गर्मी का प्रकोप ऐसे ही विनाश का कारण बनता रहेगा।

इस बार बढ़ती गर्मी ने सारे रेकॉर्ड तोड़ दिये हैं जो हमारे लिए चौंकाने से ज्यादा गंभीर चिंता की बात है। राजधानी दिल्ली के एक इलाके में अधिकतम पारा 52.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो देश के इतिहास का सबसे ज्यादा तापमान है। राजस्थान के चुरु और फलोदी आदि का पारा तो 50 के आसपास या ऊपर ही चल रहा है। जैसलमेर आदि स्थानों पर गर्मी इतने तेज है कि धरती तवे की तरह तप रही है, लोगों ने पापड़ सेक कर या आमलेट बनाते हुए दृश्य सोशल मीडिया पर दिखाये हैं। पानी की कमी, बिजली कटौती और गर्म लू के कारण बीमारी के हालात गंभीर होते जा रहे है। इतनी तेज गर्मी में पेयजल की उपलब्धता, बिजली की आपूर्ति व ट्रिपिंग की समस्या से निजात पाना मुश्किल हो रहा है। सवाल यह है कि इस भीषण लू या यों कहें कि हीटवेव के लिए बहुत कुछ हम और हमारा विकास का नजरिया भी जिम्मेदार है। आज शहरीकरण और विकास के नाम पर प्रकृति को विकृत करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। पेड़ों की खासतौर से छायादार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई एवं गांवों में हो या शहरों में आंख मींचकर कंक्रिट के जंगल खड़े करने की होड़ के दुष्परिणाम प्रकृति एवं पर्यावरण की विकरालता

के रूप में सामने हैं। जल संग्रहण के परंपरागत स्रोतों को नष्ट करने में भी हमने कोई गुरेज नहीं किया। अब विकास एवं सुविधाओं और प्रकृति के बीच सामंजस्य की ओर ध्यान देना होगा नहीं तो आने वाले साल और अधिक चुनौती भरे होंगे। कंक्रिट के जंगलों से लेकर हमारे दैनिक उपयोग के अधिकांश साधन एवं विकास की भ्रामक सोच तापमान को बढ़ाने वाले ही हैं।

विडंबना यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की दस्तक देने के बावजूद विकसित व संपन्न देश पर्यावरण संतुलन के प्रयास करने तथा आर्थिक सहयोग देने से बच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मौसम की मार से कोई विकसित व संपन्न देश बचा हो, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के क्रूर दोहन से औद्योगिक लक्ष्य पूरे करने वाले ये देश अब विकासशील देशों को नसीहत दे रहे हैं। निश्चित रूप से बढ़ता तापमान उन लोगों के लिये बेहद कष्टकारी है, जो पहले ही जीवनशैली से जुड़े रोगों एवं समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता असाध्य रोगों की वजह से चूक रही है। ऐसा ही संकट वृद्धों के लिये भी है, जो बेहतर चिकित्सा सुविधाओं व सामाजिक सुरक्षा के अभाव में जीवनयापन कर रहे हैं। वैसे एक तथ्य यह भी है कि मौसम के चरम पर आने, यानी अब चाहे बाढ़ हो, शीत लहर हो या फिर लू हो, मरने वालों में अधिकांश गरीब व कामगार तबके के लोग ही होते हैं। जिनका जीवन गर्मी में बाहर निकले बिना या काम किये बिना चल नहीं सकता। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि उन्हें मौसम नहीं बल्कि गरीबी मारती है।

जलवायु परिवर्तन का असर अब ज्यादा स्पष्ट तौर पर दिखने लगा है। अगर गर्मी पड़ रही है तो पिछले कई दशक के रिकॉर्ड तोड़ रही है। अगर बारिश हो रही है तो कुछ घंटों में ही पूरे मॉनसून की बरसात के बराबर पानी गिर रहा है। सर्दी भी साल-दर-साल नए रिकॉर्ड बना रही है। कुल मिलाकर हर मौसम अब अप्रत्याशित क्रूरतम रुख दिखा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, अल नीनो और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की दोहरी मार के कारण धरती के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे धरती पर मौजूद सभी जीव-जंतुओं, वनस्पति और इंसानों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अनेक लोगों की भीषण गर्मी में जान चली गयी, बिहार की स्कूली छात्राएं बड़ी संख्या में बेहोश हो गयी। इन जटिल स्थितियों को देखते हुए गर्मी के मौसम में काम के घंटों का निर्धारण एवं स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की अवधि मौसम की अनुकूलता के अनुरूप ही होनी चाहिए। आसन्न संकट को महसूस करते हुए दीर्घकालीन रणनीति, इस चुनौती से निपटने के लिये बनाने की जरूरत है।

दुनियाभर में अगले 20 साल के भीतर कूलिंग सिस्टम्स यानी एयरकंडीशन की मांग में कई गुना बढ़ी है। सुविधावादी जीवनशैली एवं तथाकथित आधुनिकता ने पर्यावरण के असंतुलन को बेतहाशा बढ़ाया है। तापमान में भी साल-दर-साल बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जहां तापमान ने नए रिकॉर्ड्स बनाने शुरू कर दिए हैं वहीं, भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। सरकारों को नीतिगत फैसला लेकर बदलते मौसम की चुनौतियों को गंभीरता से लेना होगा। समय रहते बचाव के लिये नीतिगत फैसले नहीं लिए गए तो एक बड़ी आबादी के जीवन पर संकट मंडराएगा। यह संकट तीखी गर्मी से होने वाली बीमारियों व लू से होने वाली मौतें ही नहीं होंगी, बल्कि हमारी कृषि एवं खाद्य सुरक्षा शृंखला भी प्रभावित होगी। हालिया अध्ययन बता रहे हैं कि मौसमी तीव्रता से फसलों की उत्पादकता में भी कमी आई है। दरअसल, मौसम की यह तल्खी केवल भारत ही नहीं ,वैश्विक स्तर पर नजर आ रही है। एशिया के अलावा यूरोप व अमेरिकी देशों में भी तापमान में अप्रत्याशित बदलाव नजर आ रहा है।

सरकारों को मानना होगा कि वैसे तो प्रकृति किसी तरह का भेदभाव नहीं करती मगर सामाजिक असमानता के चलते वंचित समाज इसकी बड़ी कीमत चुकाता है। सरकार रेड अलर्ट व ऑरेंज अलर्ट की सूचना देकर अपने दायित्वों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। खासकर ऐसे समय में जब हरियाणा व राजस्थान में पारा पचास पार करके गंभीर चुनौती का संकेत दे रहा है। स्कूल-कालेजों के संचालन, दोपहर की तीखी गर्मी के बीच कामगारों व बाजार के समय के निर्धारण को लेकर देश में एकरूपता का फैसला लेने की जरूरत है। कुछ जगह धारा 144 लागू की गई है, जो इस संकट का समाधान कदापि नहीं है। कभी संवेदनशील भारतीय समाज के संपन्न लोग सार्वजनिक स्थलों में प्याऊ की व्यवस्था करते थे। लेकिन आज संकट यह है कि पानी व शीतल पेय के कारोबारी मुनाफे के लिये सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति को बाधित करने की फिराक में रहते हैं। सरकारें भी जल के नाम पर राजनीति करती है। दिल्ली के अनेक इलाकों में बढ़ती गर्मी के साथ जल आपूर्ति एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हमारे राजनीतिज्ञ, जिन्हें सिर्फ वोट की प्यास है और वे अपनी इस स्वार्थ की प्यास को पानी से बुझाना चाहते हैं। विभिन्न प्रांतों के बीच का यह विवाद आज हमारे लोकतांत्रिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर रहा है, जनजीवन से खिलवाड़ कर रहा है। जीवनदायक वस्तुएं प्रभु ने मुफ्त में दे रखी है। पानी, हवा एवं प्यार और आज वे ही विवादास्पद, दूषित और झूठी हो गयी हैं। इस तरह की तुच्छ एवं स्वार्थ की राजनीति करने वाले नेता क्या गर्मी एवं जल-समस्याओं का समाधान दे पायेंगे?

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में फिर हासिल की अपनी खोई हुई जमीन!

कांग्रेस के लिए रायबरेली से ज्यादा बड़ी जीत अमेठी है। शर्मा, केएल जैसा कि उन्हें कहा जाता है, एक लो-प्रोफ़ाइल नेता हैं। लेकिन आज वह विशाल हत्यारे को परास्त करने के लिए गौरवान्वित है। लोकसभा में वह साथी सांसद के तौर पर राहुल गांधी के बगल में बैठेंगे।

राहुल गांधी ने रायबरेली से और गांधी परिवार के सहयोगी किशोकी लाल शर्मा ने अमेठी से जीत हासिल की है। परिवार इसे एक मीठे प्रतिशोध के रूप में देखता है। स्मृति ईरानी 2019 में राहुल गांधी से यह सीट छीन ली थी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गांधी परिवार को कभी यह भूलने नहीं दिया कि उनकी विरासत को नुकसान पहुंचा है। सूत्रों का कहना है कि जब यह तय करने का समय आया था कि 2024 में उनके सामने कौन चुनाव लड़ेगा, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ अंदरूनी सूत्रों से कहा थाः "एक गैर-गांधी उन्हें हराएगा। पार्टी के एक कार्यकर्ता को उन्हें हराना चाहिए।"

इससे पता चलता है कि अमेठी और रायबरेली के करीबी सहयोगी और प्रबंधक किशोरी लाल शर्मा को ईरानी का मुकाबला करने के लिए क्यों चुना गया था। रायबरेली की जीत वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि राहुल गांधी के लिए कई कारक काम कर सकते थे। निस्संदेह, एक मजबूत इंदिरा गांधी विरासत है, जो लगभग बरकरार है। फिर, सोनिया गांधी के बाहर निकलने से, जहां उन्हें सद्भावना प्राप्त है, उनके बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करना समझ में आता है। और निश्चित रूप से, अमेठी की तरह, भाजपा ने कोई मजबूत चेहरा नहीं उतारा है। कांग्रेस के लिए रायबरेली से ज्यादा बड़ी जीत अमेठी है। शर्मा, केएल जैसा कि उन्हें कहा जाता है, एक लो-प्रोफ़ाइल नेता हैं। लेकिन आज वह विशाल हत्यारे को परास्त करने के लिए गौरवान्वित है। लोकसभा में वह साथी सांसद के तौर पर राहुल गांधी के बगल में बैठेंगे। और हर बार जब वह बैठेंगे, तो यह कांग्रेस के लिए पीएम पर हमला करने और उन्हें याद दिलाने का क्षण होगा कि परिवार अपने क्षेत्र में व्यवसाय में वापस आ गया है। कांग्रेस ने कैसे बनाई अमेठी में जीत? यह आसान नहीं था। हालाँकि केएल को चुना गया था, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को, जो गांधी की उम्मीदवारी के प्रति आशान्वित थे, यह समझाना कठिन था कि केएल का समर्थन किया जाना चाहिए।

लेकिन यह भी तथ्य है कि ईरानी को पार्टी कैडर से कुछ असहयोग का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बारे में वह शिकायत कर रही थीं, यही कारण है कि उनके लिए आगे बढ़ना कठिन था। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह को बीच में आकर रोड शो करना पड़ा। जाहिर है, यह पर्याप्त नहीं था। रायबरेली में जीत के साथ सिरदर्द भी जुड़ा है। नियमों के मुताबिक गांधी सिर्फ एक सीट ही अपने पास रख सकते हैं. क्या वह रायबरेली छोड़ देंगे?

सामाजिक कलंक है बालश्रम..?

12 जून के दिन 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' की पहल पर 'विश्व बालश्रम निषेध दिवस' मनाने का आरंभ हुआ

'वैश्विक समस्या है बाल श्रम? किसी भी मुल्क के माथे पर सामाजिक कलंक भी है, फिर चाहें वह देश विकसित हो या विकासशील? आज से 19 वर्ष पहले यानी सन-2002 को इस बुराई के विरुद्ध प्रतिवर्ष 12 जून के दिन 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' की पहल पर 'विश्व बालश्रम निषेध दिवस' मनाने का आरंभ हुआ। इस दिवस का मकसद चाइल्ड लेबर के सभी रूपों को रोकने के लिए जनमानस को जागरूकता करना था। जागरूकता को ध्यान में रखकर ही 2024 की थीम 'अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें' बाल श्रम समाप्त करें, निर्धारित की गई है।

आंकड़ों की माने तो बालश्रम एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर काबिज है। यहां कुल 7 फीसदी बच्चे विभिन्न किस्म की मजदूरी में संलिप्त है। यही कारण है कि 62 मिलियन बच्चों की बड़ी आबादी आज भी शिक्षा से महरूम है। रोकथाम के लिहाज से प्रयासों में कमी नहीं है, प्रयास बहुतेरे किए जाते हैं कि बच्चों को बाल श्रम की धधकती भट्टियों से आजाद करवाया जाएं। लेकिन परिवारों के मध्य संघर्ष, संकट और आर्थिक मजबूरियां उन्हें बाल श्रम करने को विवश करती हैं।

बाल श्रम रोकने में सरकारी व सामाजिक दोनों के प्रयास नाकाफी न रहें, सभी को ईमानदारी से इस दायित्व में आहुति देनी चाहिए। कानूनों की कमी नहीं है, कई कानून सक्रिय हैं। बाल श्रम अधिनियम-1986 के तहत ढाबों, घरों, होटलों में बाल श्रम करवाना दंडनीय अपराध है। बावजूद इसके लोग बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं। बच्चों को वह अपने प्रतिष्ठिनों में इसलिए काम दे देते हैं क्योंकि उन्हें कम मजदूरी देनी पड़ती है। लेकिन वह यह भूल बैठते हैं कि वह कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। बाल मजदूरी रोकने के लिए 1979 में बनी गुरुपाद स्वामी समिति ने बेहतरीन काम किया था। उसके बाद अलग मंत्रालय, आयोग, संस्थान और समितियां बनीं, लेकिन बात फिर वहीं आकर रुक जाती है कि जब तक आमजन की सहभागिता नहीं होगी, सरकारी प्रयास भी नाकाफी साबित होंगे।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विगत कई दशकों से बाल श्रम को समाप्त करने में ईमानदारी से प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहा है। बावजूद इसके संपूर्ण विश्व में आज भी करीब 160 मिलियन बच्चे बाल श्रम की भट्टी में तप रहे हैं। दुनिया भर में करीब दस में से एक बच्चा आज भी किसी न किसी रूप में मजदूरी करने को मजबूर है। बाल श्रम से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहताशा प्रयास हो रहे हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा लगातार कार्यान्वित शिक्षा, कला और मीडिया के माध्यम से बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लेकिन फिर भी बाल श्रम की समस्या थमने के बजाय और बढ़ रही है। हिंदी फिल्म 'बूट पॉलिश' का एक गाना है कि 'नन्हें मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी' के बोल न सिर्फ बालश्रम की भट्टियों में धधकते बचपन के प्रति संवेदना जगाते हैं, बल्कि हुकूमतों के लिए बाल समस्याओं पर अंकुश न लगाने व उनसे जुड़े उत्पीड़न और अपराध के प्रति घोर निराशा भी व्यक्त करते हैं।

बाल मजदूरी वैश्विक समस्या का रूप ले चुकी है। इसलिए सिर्फ सरकार-सिस्टम पर सवाल उठाने से अब काम नहीं चलने वाला? समाधान के विकल्प सभी को मिलकर खोजने होंगे? सड़कों पर भीख मांगते बच्चे, ईट भट्टों पर काम करते नौनिहाल, विभिन्न अपराधों में लिप्त बच्चे व शिक्षा से महरूम बच्चों को देखकर मुंह मोड़ने के बजाय है, हुकूमतों को चेताना होगा। बच्चों से मुंह फेरना

ही हमारा सबसे बड़ा अपराध है। हमारी चुप्पी ही बालश्रम जैसे कृत्य को बढ़ावा देती है। ऐसे बच्चों के बचपन की तुलना थोड़ी देर के लिए हम अपने बच्चों से करें, तो फर्क अपने आप महसूस कर सकेंगे। ऐसा करने से अपने भीतर बदनसीब बच्चों के प्रति संवेदना जगेगी और उनसे जुड़े जुल्मों के खिलाफ अवाज उठाने का संबल मिलेगा। आंखों के सामने किसी बच्चे का बचपन खो जाना, हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म वाली बात है।

इस सामाजिक बुराई से समाज को वाकिफ हो जाना चाहिए कि बाल श्रम रोकना केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, प्रत्येक इंसान का मानवीय दायित्व भी है। ये सच है कि समस्या किसी एक के बूते सुलझने वाली नहीं? इसके लिए सामाजिक चेतना, जनजागरण और जागरूकता की जरूरत है। बाल मजदूरी और बाल अपराध को रोकने के लिए महिला बाल मंत्रालय, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग व निपसिड सहित इस क्षेत्र में कार्यरत तमाम संस्थाएं कार्यरत हैं। गैर सरकारी संगठन और एनजीओ हमेशा रोकथाम की दिशा में हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके लिए सबसे पहले सामाजिक स्तर पर बाल श्रमिकों के प्रति आम लोगों के जेहन में संवेदना जगानी होगी और बाल श्रम के खिलाफ मन में लड़ाई की प्रवृति पैदा करनी होगी। ताजा आंकड़े बताते हैं कि बीते एकाध दशकों से एशिया में सबसे ज्यादा बाल तस्करी हिंदुस्तान में हुई हैं। जबकि, ये सिलसिला रूका नहीं, बल्कि और तेज हुआ है।

बाल मजदूरों के बढ़ने के कुछ कारण और भी हैं। पिछड़े राज्यों में बाल तस्करों का बड़ा गैंग सक्रिय है, जो मासूम बच्चों को किडनैप करके उन्हें कुछ समय बाद भीख मंगवाने या मजदूरी में लगा देते हैं। कुछ बच्चों को अपराध की दुनिया में भी उतार देते हैं। बाल मजदूरी व बाल तस्करी दोनों कृत्यों में एक बड़ा गैंग सक्रिय होकर अंजाम देता है। नेशनल क्राइम ब्यूरों के आंकड़े बताते हैं कि तस्कर गिरोह समूचे हिंदुस्तान में रोजाना सैकड़ों बच्चे किडनेप करते हैं जिन्हें बाद में भीख मंगवाने, मजूदरी, बाल अपराध और बाल श्रम की आग में झोंकते हैं। सड़क, बाजार व अन्य जगहों पर की जाने वाली स्नैचिंग की ज्यातर घटनाओं को कम उम्र के बच्चे ही अंजाम देते हैं। उन्हें बाकायदा पहले प्रशिक्षण दिया जाता है। उद्योग, कल-कारखाने व कंपनियों वाले बच्चों से मजदूरी इसलिए भी कराते हैं क्योंकि इसके एवज में उन्हें कुछ देना नहीं पड़ता, बिना भुगतान के वह बच्चों कुछ थोड़ा खाना खिलाकर ही उनसे शारीरिक कार्य करवा लेते हैं। आज का दिन खास है, बाल श्रम रोकने के लिए? सभी को संकल्पित होना चाहिए इस लड़ाई में? कहीं कोई बच्चा मजदूरी करता दिखे, उससे उसका कारण जानना चाहिए। अगर लगे उसे जबरदस्ती काम पर लगाया गया है, तो आरोपियों के खिलाफ कानूनी कारवाही भी करवानी चाहिए।

राजनाथ सिंह ने संभाला रक्षा मंत्रालय का पदभार, आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर...

राजनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने मुझे फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। हमारी प्राथमिकताएं एक ही होंगी, देश की सुरक्षा। हम एक मजबूत और 'आत्मनिर्भर' भारत विकसित करना चाहते हैं।

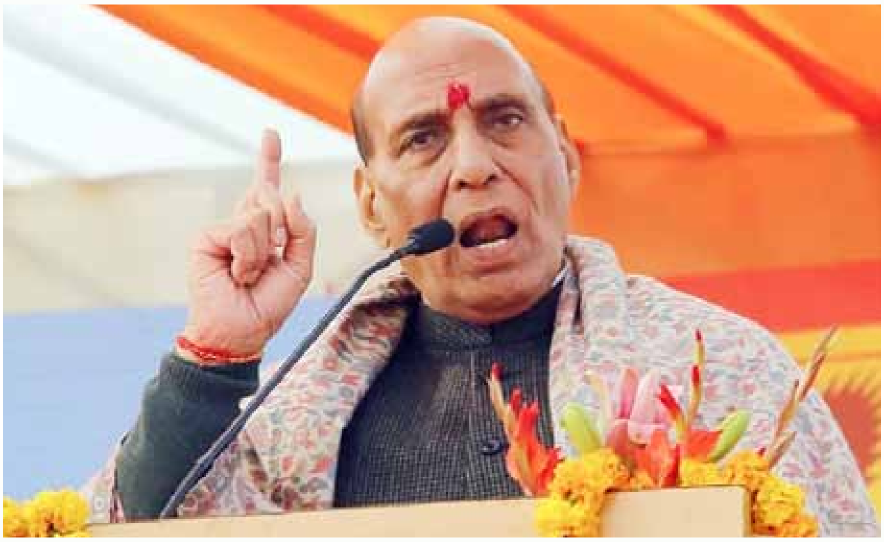

केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने गुरुवार को रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला, ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा विनिर्माण के साथ एक मजबूत, 'आत्मनिर्भर' सरकार विकसित करना होगी। राष्ट्रीय राजधानी में साउथ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाले सिंह ने कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी और अगले पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

राजनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने मुझे फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। हमारी प्राथमिकताएं एक ही होंगी, देश की सुरक्षा। हम एक मजबूत और 'आत्मनिर्भर' भारत विकसित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हमने 21,000 करोड़ रुपये से अधिक के रक्षा उपकरण निर्यात किए हैं। हमारा लक्ष्य अगले पांच में इस आंकड़े को 50,000 करोड़ रुपये तक ले जाना है। सिंह ने कहा कि हमें अपनी तीन सशस्त्र सेनाओं, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना पर गर्व है।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने 1 जून, 2019 को पहली बार रक्षा मंत्रालय के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी। 10 जुलाई, 1951 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में जन्मे सिंह ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातकोत्तर किया और पेशे से शिक्षक थे। उन्होंने 1977-1980 और 2001-2003 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। वह 1991 से 1992 तक उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रहे, जबकि 1999 से 2000 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में भूतल परिवहन मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

बाद में, वह 2000-2002 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2003 में, उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 1994-1999 और फिर 2003-2008 में दो कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए चुने गए। 2009 में, वह 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 7 अक्टूबर 2009 को नैतिकता समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। 27 मई 2014 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में राजनाथ सिंह को गृह मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उनकी शादी सावित्री सिंह से हुई है और उनके दो बेटे हैं। झारखंड के रांची से सांसद संजय सेठ को रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार दिया गया है।

18वीं लोकसभा के चुनावों के जनादेश के क्या मायने

जहां तक विदेश नीति की बात है इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले दस सालों में भारत अब दुनिया के देशों के सामने चौधरी की भूमिका निभाने लगा है। आज कोई भी देश चाहे वह कितना भी बड़ा, संपन्न और शक्तिशाली हो पर भारत को इग्नोर करने की गलती नहीं कर सकता।

18वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि मतदाता के मन को समझना इतना आसान नहीं हैं। इसी तरह से एक्जिट पोल के परिणामों और धरातलीय परिणामों में अंतर से साफ हो जाता है कि मतदाता खुलता भी नहीं है तो किसके पक्ष में मतदान करके आया है उसे वह मुखर होकर बताता भी नहीं है। चुनाव परिणामों से सट्टा बाजार की भी पोल खुल कर रह गई है। ऐसे में सवाल यह हो जाता है कि मतदाता इस जनादेश के माध्यम से आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव परिणामों से यह तो साफ हो गया है कि मतदाता ने एनडीए को तीसरी बार सरकार चलाने या यों कहें कि कंटिन्यूटी का अवसर दे दिया है क्योंकि एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। ऐसा नहीं है कि परिणाम के बाद किसी बाहरी दल के सहयोग की आवश्यकता हो। बहुमत के 272 की तुलना में एनडीए को 293 सीटें मिली हैं वहीं पिछले दो चुनावों की तरह इस बार भाजपा को अकेले स्पष्ट बहुमत के आंकड़ें से दूर अवश्य रखा है पर सबसे बड़े दल के रुप में भाजपा सामने आई है। देखा जाए तो 10 साल बाद किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इससे यह भी तो स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता विरोधी लहर उतनी नहीं रही जितनी दस साल के शासन के बाद सामान्यतः आ जाती है पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा आदि के माध्यम से मतदाता ने अपनी नाराजगी जाहिर करने में किसी तरह का संकोच भी नहीं किया है। दरअसल जनआंकाक्षाओं और सरकार की परफारमेंस के बीच अंतर को पाटने में सरकार पूरी तरह से सफल नहीं रही। हांलाकि परफारमेंस के पेरामीटर्स या यों कहें कि मापदण्ड बदलते रहते हैं। एक बात यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह मेंडेट केन्द्र सरकार की वर्तमान नीतियों का नकार नहीं हैं अपितु मतदाता सरकार द्वारा नेपथ्य में ड़ाले हुए विषयों को सामने लाकर आगे बढ़ने की दिषा में दिया गया संदेश है। और साफ है कि सरकार की प्राथमिकता में इन विषयों को लेना ही होगा।

दरअसल जनता कहीं ना कहीं संतुलन चाहती हैं। सरकारों को जहां एग्रेसिव होना अच्छा लगता हैं वहीं जनता कहीं ना कहीं डिलीवरी सिस्टम को लेकर भी चिंतित रहती है। केवल उज्जवल और एग्रेसिव छवि, सफल विदेश नीति, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद, धर्म, आर्थिक विकास या यों कहें कि इकोनोमिक ग्रोथ के साथ ही बहुत से ऐसे कारक है जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया का सबस बड़ा और सफलतम लोकतंत्र हमारे यहां है।

लोकतांत्रिक देषों में सर्वाधिक राजनीतिक दलों वाला भी हमारा ही देश है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था व चुनाव व्यवस्था की सारी दुनिया कायल है। पर इसके साथ ही अब आमजन का मनोभाव यह है कि राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए ना कि मण्डी बाजार जैसी एक दूसरे पर छिंटाकशी के हालात। वास्तविकता तो यह है कि प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा तो रही ही नहीं है अपितु दिन प्रतिदिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना ही एकमात्र काम रह गया। मानों या ना मानों पर आज हालात यह हो गए हैं कि राजनीतिक शालिनता तो रही ही नहीं। दूसरी बात धर्म की करें तो उत्तर प्रदेष में अयोध्या की सीट पर बीजेपी उम्मीद्वार की हार और यूपी के परिणाम बीजेपी के लिए घोर निराशाजनक होने से साफ संकेत हैं कि केवल श्रीराम लला या धर्म के नाम पर ज्यादा दिन नहीं चला जा सकता। लोगों का मानना है कि अब राम मंदिर बन गया वह सबके सामने हैं तो अब उसे जनमानस की आस्था का केन्द्र रहने दो नाकि उसे राजनीतिक रुप से भुनाना। हिन्दी बेल्ट के परिणाम इसे साफ कर देते हैं। लोग आतंकवादी गतिविधियों व असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम को तो उचित मानते हैं पर अब इसमें धर्म का प्रयोग कुछ अति ही लगने लगा है।

एक अन्य बिंदु आर्थिक एजेण्डा को लेकर है। कहीं भी मतदाता ने आर्थिक एजेण्डें को नकारा नहीं हैं। पर लोग अब महंगाई से त्रस्त हो रहे हैं तो बाजार पर सरकार के नियंत्रण कम होने से परेशान है। जनमानस जहां आर्थिक क्षेत्र में हाई ग्रोथ चाहने लगा है तो सबसे बड़ी समस्या रोजगार के अवसरों को लेकर है। पक्ष व विपक्ष सभी का प्रिय मुद्दा नौकरियां है। सरकार जहां कहती है कि लाखों की संख्या में नौकरी के अवसर विकसित किए हैं वहीं विपक्ष नौकरियां नहीं मिलने की बात करता रहा है।

इन चुनावों में भी हिंदी बेल्ट में नौकरियों की कमी का अण्डर करंट अवश्य रहा है। इसलिए नौकरियों के अवसर विकसित करने के साथ ही नौकरियां उपलब्ध कराने और उसका प्रोपेगेंडा करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आम आदमी का जीवनयापन आसानी से हो सके, इसके लिए सरकार को विजिलेंट रहना ही होगा। इसी तरह से आधारभूत संरचनाओं के विस्तार पर जोर देना होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, सड़क आदि क्षेत्रों में सरकार को अपने एजेण्डें को आगे बढ़ाना ही काफी है। आमजन शांति, प्रेम और स्नेह का वातावरण, तेजी से समग्र विकास, विदेशों में गौरव और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार चाहता है। रोजगार की सहज उपलब्धता और बाजार पर सरकार की नियंत्रण होने से जीवनयापन और अधिक आसान हो सकता है।

कौन हैं अन्नपूर्णा देवी जिन पर पीएम नरेन्द्र मोदी ने जताया है भरोसा...

लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा से अपनी अमेठी सीट हारने के बाद ईरानी को नए मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। पचपन वर्षीय देवी केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में दो महिला कैबिनेट मंत्रियों में से एक हैं। 30 सदस्यीय कैबिनेट में दूसरी महिला मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं।

झारखंड से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद अन्नपूर्णा देवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में स्मृति ईरानी की जगह लेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा से अपनी अमेठी सीट हारने के बाद ईरानी को नए मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। पचपन वर्षीय देवी केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में दो महिला कैबिनेट मंत्रियों में से एक हैं। 30 सदस्यीय कैबिनेट में दूसरी महिला मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं।

सौंपी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी

कौन हैं अन्नपूर्णा देवी? : झारखंड की कोडरमा लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार निर्वाचित देवी ने 2021 के बाद पिछली मोदी सरकार में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया है। देवी और रांची के सांसद संजय सेठ आदिवासी बहुल झारखंड से पीएम मोदी कैबिनेट में दो मंत्री हैं। देवी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ थीं, जब तक कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गईं। 2024 के आम चुनाव में उन्होंने झारखंड में सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल की। देवी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के उम्मीदवार विनोद सिंह को 3,77,014 वोटों के अंतर से हराया।

सांसद के रूप में देवी का यह दूसरा कार्यकाल है। 2019 में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को 4.55 लाख वोटों से हराया। देवी 1998 में अपने पति, राजद विधायक रमेश यादव की मृत्यु के बाद राजनीति में कूद गईं। देवी ने उपचुनाव में चुनाव लड़ा और जीतकर तत्कालीन संयुक्त बिहार विधान सभा की सदस्य बनीं। वह अविभाजित बिहार की राजद सरकार में खान और भूविज्ञान राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। 2000 में, दक्षिणी बिहार को नया राज्य झारखंड बनाने के लिए सौंप दिया गया। देवी ने 2005 और 2014 के बीच दो कार्यकाल के लिए झारखंड विधानसभा में विधायक के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2012 में झारखंड में सिंचाई, महिला और बाल कल्याण और पंजीकरण मंत्री के रूप में कार्य किया। भाजपा में शामिल होने से पहले, देवी झारखंड में राजद प्रमुख थीं। भाजपा पार्टी के भीतर उनका उत्थान झारखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के चेहरे के रूप में उनके राजनीतिक महत्व का प्रमाण है। पिछली जनगणना के अनुसार, ओबीसी समुदाय झारखंड की आबादी का 45 प्रतिशत से अधिक है।

बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराये जाने चाहिए : मंत्रालय

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को स्कूलों को जारी परामर्श में कहा कि मासिक धर्म से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए छात्राओं को 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान आवश्यक विराम लेने की अनुमति दी जानी चाहिए तथा सभी परीक्षा केंद्रों पर मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। मंत्रालय ने इस बात पर गौर किया कि लड़की के समग्र कल्याण के लिए मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन जरूरी है और यह उसके शैक्षणिक प्रदर्शन के रास्ते में नहीं आना चाहिए।

मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी स्कूलों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा, ''कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर लड़कियों को परीक्षा के दौरान आवश्यक स्वच्छता उत्पाद उपलब्ध हो सकें।'' इसने कहा, ''छात्राओं को मासिक धर्म से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने, असुविधा को कम करने और परीक्षा के दौरान ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक विराम लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा, छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

दक्षिण भारत : भाजपा का दबदबा बढ़ा तो खिड़की खुली किंतु दरवाजा बाकी

भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण की 130 सीटों में से 29 सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव ने साबित कर दिया कि दक्षिण में भाजपा का दबदबा बढ़ रहा है और आने वाले समय में दक्षिण भारतीय राजनीतिक समीकरण भाजपा की राजनीति के साथ एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं।

भारत का बहुप्रतीक्षित आम चुनाव संपन्न हो गया है और भाजपा के नेतृत्व में राजग गठबंधन सरकार बन रही है। नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हालांकि उत्तर भारत में भाजपा को सीटों का भारी नुकसान हुआ, पर दक्षिण भारत में दिलचस्प वोटिंग पैटर्न उभरकर सामने आए हैं, जो वहां भाजपा की चुनावी बढ़त से स्पष्ट है। बेशक दक्षिण में मिली बढ़त उत्तर भारत में हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, पर इस चुनाव में भाजपा के संबंध में दक्षिण की मतदान प्रवृत्ति का विश्लेषण एक ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो दक्षिण में पैठ बनाने की इच्छुक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए ध्यान देने योग्य है।

लंबे समय से दक्षिणी राज्यों में भाजपा को 'उत्तर भारतीय पार्टी' माना जाता रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद कर्नाटक को छोड़कर यह दक्षिणी राज्यों में अपनी पैठ नहीं बना पाई। हालांकि 2019 में मोदी लहर में भी आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं जीत पाने के बाद भाजपा दक्षिण के प्रति गंभीर हो गई। इन तीनों राज्यों में भाजपा की हार के पीछे कई कारण थे। आंध्र में भाजपा के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी थी, क्योंकि उसने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया और जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में किसी अन्य पार्टी के लिए राज्य के चुनावी मैदान में उतरने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। तमिलनाडु में पारंपरिक रूप से द्रविड़ पार्टियों की राजनीति हावी रही है। यहां तक कि केरल में भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति भी उल्टी पड़ गई और भाजपा द्वारा उठाए गए सबरीमाला मुद्दे का ज्यादातर लाभ केरल कांग्रेस को मिला।

मगर 2024 के आम चुनाव में चीजें बदल गईं। दक्षिण भारत की 130 सीटों में से भाजपा ने 29 सीटें हासिल कीं, जिनमें से तीन आंध्र प्रदेश में, 17 कर्नाटक में, आठ तेलंगाना में और एक सीट केरल में है। आंध्र प्रदेश में पार्टी का वोट शेयर 2019 के 0.98 फीसदी से बढ़कर अब 11.28 फीसदी हो गया है। यह पूर्व राजग सहयोगी एवं तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ समझौते के कारण हुआ, जो अब केंद्र में 'किंग मेकर' बन गए हैं।

आंध्र में भाजपा की वापसी का कारण उसके दूसरे सहयोगी और जनसेना पार्टी के फिल्म स्टार पवन कल्याण द्वारा हासिल भारी युवा वोट भी हैं। आंध्र प्रदेश से सटे तेलंगाना में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन आम चुनाव में यह पूरी ताकत के साथ उभर कर सामने आई है। भाजपा ने तेलंगाना की छह में से तीन सीटें हासिल कीं, इसने बीआरएस को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। बूथ स्तर पर अपना स्वयं का पार्टी कैडर तैयार करने के लगातार प्रयासों का नतीजा है कि भाजपा का वोट शेयर 2019 के 19.65 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 35.08 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा तेलंगाना के किसानों से कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं करने का लाभ भी भाजपा को मिला।

भाजपा को तमिलनाडु से काफी उम्मीदें थीं

'देवताओं का अपना देश' कहे जाने वाले केरल में खाता खोलने का भाजपा का लंबे समय का सपना पूरा हो गया, क्योंकि पार्टी के प्रत्याशी ने त्रिशूर निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। पार्टी ने कट्टर हिंदुत्व के अपने एजेंडे से विकास की तरफ अपना रुख मोड़ दिया, जिससे उसका वोट शेयर 2019 के 13 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 16.68 प्रतिशत हो गया। भाजपा को तमिलनाडु से काफी उम्मीदें थीं, क्योंकि उसके युवा राज्य प्रमुख अन्नामलाई पूर्व आईपीएस हैं और पार्टी ने उन्हें खुली छूट दे रखी है। लेकिन कद्दावर नेताओं के बार-बार दौरे, भाजपा की केंद्रीय इकाई द्वारा तमिल संस्कृति एवं परंपरा पर जोर दिए जाने तथा 'कच्चातिवु' मुद्दे को उठाने के बावजूद पार्टी वहां सीट नहीं जीत सकी। हालांकि 2019 के 3.66 फीसदी के मुकाबले उसका वोट शेयर बढ़कर 2024 में 11.24 फीसदी जरूर हो गया, जो कि तीन गुना ज्यादा है।

बदलाव का पहिया घूमा

व्यक्तिगत आस्था व राजनीतिक व्यवहार में अंतर करना जान गए हैं मतदाता...

वर्ष 2024 के जनादेश में सबके लिए कुछ न कुछ है, पर सबसे बड़ा श्रेय राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी एवं शरद पवार को जाता है। इन लोगों की एकजुटता ने 'इंडिया' गठबंधन को भारी ताकत दी। लेकिन नरेंद्र मोदी, भाजपा, राजग और बड़बोले मीडिया के एक वर्ग को स्तब्ध कराने के बाद विपक्षी दलों को आत्मचिंतन करके यह सोचना चाहिए कि 'क्या होता अगर' उन्होंने कुछ और मेहनत की होती!

कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन को निश्चित रूप से इस लोकसभा चुनाव में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चूके हुए अवसरों पर पछतावा हो रहा होगा, जहां वे मौन या रणनीतिक गठबंधन नहीं कर सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 'इंडिया' गठबंधन का हिस्सा थे, तो उन्होंने भुवनेश्वर का दौरा करके नवीन पटनायक से 'इंडिया' गठबंधन में शामिल होने का आग्रह किया था, पर नीतीश कुमार के स्वयं राजग का हिस्सा बनने के बाद बीजद के साथ बात आगे नहीं बढ़ सकी। जब नतीजे आए तो भाजपा-राजग ने राज्य में भारी संख्या में सीटें हासिल कर लीं, जिससे वे बहुमत के करीब पहुंच गए।

1980 के दशक से ही गठबंधन राजनीति में आंध्र प्रदेश और तेदेपा ने ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 1984 में तेदेपा लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी। अभिनेता से राजनेता बने चंद्रबाबू नायडू के श्वसुर एनटी रामाराव राष्ट्रीय मोर्चा के संयोजक बने थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह को 1989 में प्रधानमंत्री बनने में मदद की थी। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा-वाम मोर्चा सरकार को भाजपा बाहर से समर्थन कर रही थी। वर्ष 1996 में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, तो चंद्रबाबू ने किंगमेकर की भूमिका निभाई, जब एचडी देवगौड़ा एवं आईके गुजराल प्रधानमंत्री बने। इस उथल-पुथल भरे दौर में दो बार नायडू को प्रधानमंत्री पद की पेशकश की गई, लेकिन दोनों बार उन्होंने इन्कार कर दिया। मसलन, आंध्र प्रदेश में मुश्किल से एक प्रतिशत वोट शेयर वाली भाजपा ने तेलुगू देशम पार्टी और जन सेना को अपने साथ जोड़कर बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके विपरीत, जगन मोहन रेड्डी के शुरुआती वर्षों में कांग्रेस से जुड़े होने के बावजूद 'इंडिया' गठबंधन को कोई दोस्त नहीं मिला। जगन रेड्डी के साथ कांग्रेस के अलगाव की अलग कहानी है। जगन से समझौते या पहल करने के बजाय कांग्रेस नेतृत्व ने उनकी बहन शर्मिला को राज्य में पार्टी प्रमुख के रूप में आगे बढ़ाया। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का वोट प्रतिशत मामूली रहा होगा, जो संसदीय चुनाव में वाईएसआरसीपी को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। भाजपा और राजग को इसका सीधा लाभ मिला। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का चक्र तेजी से घूमा। अखिलेश यादव 2024 के सबसे बड़े स्टार हैं। अयोध्या में भाजपा उम्मीदवार की हार बताती है कि मतदाता व्यक्तिगत आस्था और राजनीतिक व्यवहार के बीच अंतर करना जानते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की भूमिका का विशेष रूप से उल्लेख करना जरूरी है। खरगे ने सहयोगियों एवं संभावित सहयोगियों से बातचीत करने के लिए अथक परिश्रम किया। दूसरी ओर, भाजपा ने कई रणनीतिक गलतियां कीं। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया और कई अन्य राज्यों में क्षेत्रीय क्षत्रपों को हाशिये पर रखने की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसके अलावा अंतिम समय में उम्मीदवारों के चयन में बदलाव तथा चुनाव प्रचार में ध्रुवीकरण ने नुकसान पहुंचाया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर अत्यधिक निर्भरता ऐसी चीज है, जो भाजपा को लंबे समय तक परेशान करेगी। इस साल अक्तूबर में हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों की संभावना भाजपा के लिए दुःस्वप्न पैदा कर सकती है।

भोपाल में सम्पन्न हुआ अखिल भारतीय हिन्दू सेवादल का कार्यक्रम

हिन्दू संस्कृति के नये अध्याय का 'शुभारंभ' के साथ साथ हिंदू एकता और हिंदुओ को एक करके हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर चर्चा भी हुई।

भारतीय संस्कृति का इतिहास हमारे ज्ञान देने के उद्देश्य से विशाल जन चेतना हिंदू सम्मेलन दिनांक 23 जून 2024 दिन रविवार, गुफा मंदिर मानस भवन हॉल (लालघाटी, भोपाल)मैं महामंडलेश्वर सन रक्षक रामप्रिय दस की उपस्थिति मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज भारद्वाज की अध्यक्षता में संपन्न किया गया इसमें राष्ट्रीय महामंत्री एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मनोज चतुर्वेदी उपस्थित थे तथा डॉक्टर राज कुमार मालवीय भी उपस्थित थे!! बही इस कार्यक्रम मैं संरक्षक महा मंडलेश्वर रामप्रिय दास जी ने कहा की समस्त हिंदुओ को एक होकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आना होगा नही आगे चलकर सनातन धर्म को समाप्त करने बाली आसुरी शक्ति वाले अन्य पार्टियां ,और धर्म वाले अपने सर यन्त्र मैं सफल हो जायेंगे। इस विराट हिंदू सम्मेलन को हमारे देश से सनातन धर्म के प्रवक्ता एवं धर्म गुरुओं की गरिमामयी उपस्थित में सम्पन्न हुआ...

जिसमें कई शहरों से आए हुए संगठन के सम्मानीय सदस्यों ने अपनी उपस्थिती दर्ज कराई.. जिसमें साधु, संतजन एवम् समाज में रह रहे सनातन धर्म के वरिष्ठ जनों ने अपनी वाणी से उदबोधित किया...एवम् हमारी सनातन की युवा पीढी को अपनी सनातन संस्कृति एवं संस्कारों को महत्व देने की बात की... कार्यक्रम में सम्मिलित हुईं भोपाल की महापौर श्रीमति मालती राय जी... वार्ड 20 की पार्षद श्रीमति पूजा शर्मा जी एवम् वार्ड 21 की पार्षद श्रीमति विनीता सोनी जी और वार्ड 07 की पार्षद श्रीमति प्रियंका भी सम्मिलित हुईं.... संबोधन में कहा गया कि प्रकृति अपना स्वभाव व परिवर्तन कितना भी कर ले परन्तु मूल स्वभाव कभी नहीं बदलती...

हमारी संस्कृति का जो विलोपन हो रहा है, इसकी स्थापना पुनः करनी होगी. जिसका शुभारंभ आज दिनाँक23/06/2024 से शुरु हुआ.. कार्यक्रम की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती उषा गुप्ता जी आयोजन कर्ता कु. कनिष्का गुप्ता,सह संयोजक श्रीमति शशि शर्मा, आदि उपस्थित थी बही दूसरी ओर अनिल जैन, नवीन स्वामी,मंजीत गोस्वामी,रवि परिहार,सुनीता कुशवाह उपस्थित थे।

अखिल भारतीय हिन्दू सेवा दल
आवाहन

कनिष्का गुप्ता
(आयोजक)

अखिल भारतीय हिन्दू सेवा दल
आवाहन
हिन्दू संस्कृति के नये अध्याय का
भव्य शुभारंभ

आवाहन
हिन्दू संस्कृति के नये अध्याय का
उमा गुप्ता
कनिष्का गुप्ता
(आयोजक)
भव्य शुभारंभ
राष्ट्रीय कार्यकारिणी

30 जून तक 208 करोड़ वसूलने का लक्ष्य, अब तक 65 करोड़ भी नहीं मिले

ई-पोर्टल में हुई गड़बड़ी का खामियाजा इंदौर नगर निगम को भुगतना पड़ रहा है। नगर निगम ने 30 जून तक संपत्तिकर के 180 करोड़, जलकर के 17 करोड़ और कचरा संग्रहण शुल्क के 11 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य रखा है, लेकिन हालत यह है कि अब तक इन तीनों करों को मिलाकर 65 करोड़ रुपये की भी वसूली नहीं हुई है।

वित्तीय संकट से गुजर रहा निगम : वित्तीय संकटों से गुजर रहे नगर निगम ने राज्य शासन से 30 जून से पहले लोक अदालत आयोजित करने की अनुमति मांगी है। निगम के अधिकारियों लोक अदालत में 50 से 60 करोड़ रुपये की वसूली होने की उम्मीद है। निगम ने खुद भी अपने दम पर मैदान में उतरकर बकाया कर वसूली की मुहिम शुरू कर दी है। ई-पालिका पोर्टल 21 दिसंबर 2023 को हैक हो गया था। नगर निगम में संपत्ति कर, जलकर, कचरा संग्रहण कर, लायसेंस शुल्क जैसे सभी शुल्क ई-पोर्टल के माध्यम से ही जमा होते हैं। ई-पालिका पोर्टल के हैक होने की वजह से कई दिनों तक निगम का कामकाज बंद रहा। हाल ही में पोर्टल चालू तो हो गया, लेकिन अब भी इसमें पुराना रिकार्ड नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि कर जमा करने के लिए पहुंच रहे लोगों को पुरानी रसीदें दिखाना पड़ रही हैं।

लक्ष्य से 65 फीसदी कम कर वसूली

नगर निगम के अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष अब तक संपत्ति कर के रूप में लगभग 50 करोड़ रुपये की वसूली ही हो सकी है। यह लक्ष्य से करीब 65 प्रतिशत कम है। जलकर और कचरा संग्रहण की स्थिति भी ऐसी ही है। 207 करोड़ रुपये की वसूली के लक्ष्य के एवज में अब तक 65 करोड़ रुपये भी वसूले नहीं जा सके हैं। हमने राज्य शासन से लोक अदालत की अनुमति मांगी है। लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले मामलों में छूट का प्रावधान होता है। नगर निगम भी लोक अदालत में कर जमा कराने वालों को विशेष छूट देता है। इस वर्ष फरवरी और मई में लोक अदालतें आयोजित तो हुई थीं, लेकिन ई-पोर्टल के काम नहीं करने की वजह से नगर निगम को इन दोनों ही लोक अदालतों का कोई लाभ नहीं मिल सका था।

इंदौर को मिली बड़ी सौगात

तीन माह में 10 ग्रिड तैयार, 50 मेगावाट बिजली वितरण क्षमता बढ़ी

गर्मी में बिजली वितरण और व्यवस्था में बाधा पहुंचने के कारण आलोचना झेल रही विद्युत वितरण कंपनी अब बिजली वितरण का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में लगी है। केंद्र सरकार द्वारा अनुदानित रिवेम्प्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) का प्रभावी क्रियान्वय कर मार्च से मई माह के दौरान पश्चिम मप्र में 10 नए ग्रिड तैयार कर लिए गए हैं। इनसे बिजली वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। इन 33/11 केवी नए ग्रिडों से बिजली वितरण क्षमता में 50 एमवीए का विस्तार हो गया है। अन्य कार्य भी कराए गए है। विशेषकर 555 किमी की विद्युत लाइनों का कार्य कराया गया है। इन सभी कार्यों की कुल लागत करीब 106 करोड़ रुपये हैं।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के आदेश : मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के आदेशानुसार अधोसंरचना के कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे है।लक्ष्य है कि कृषि, घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की अधिक से अधिक मदद हो सके। इंदौर शहर में दो नई ग्रिड से वितरण शुरू हो गया है।खंडवा रोड के बिलावली, इंदौर ग्रामीण के राजोदा में नए बने ग्रिडों को हाल ही में चार्ज किया गया है।

बिजली वितरण प्रारंभ हुआ

इसी तरह कुम्हार खेड़ा, तिवाड़िया, गेरू बेदी, खेड़ा पहाडी, शिवना, जीवन खेड़ी, जोलाना, मोहम्मदखेड़ा में भी 33/11 केवी के नए ग्रिड तीन माह के दौरान पूर्णतः तैयार हुए एवं बिजली वितरण प्रारंभ हुआ है। इंदौर के साथ अन्य जिलों में 100 कैपिसिटर बैंक लगाए गए है। उच्च दाब 33 केवी लाइन का विभक्तिकरण एवं मिलान का कार्य 30 किमी क्षेत्र में किया गया है। मिक्स फीडरों का विभक्तिकरण कार्य 4 स्थानों पर किया गया है। 30 स्थानों के ट्रांसफार्मरों का मिक्स उपयोग से पृथक किया गया है।

850 स्थानों पर वोल्टेज समस्या समाधान के लिए अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए है। प्रबंध निदेशक ने बताया कि 150 किमी में नई 11 केवी लाइन स्थापित की गई है। इसी तरह 11 केवी/33 केवी लाइनों के तार ज्यादा क्षमता वाले लगाए गए है, इनकी लंबाई 200 किमी है। इसी के साथ 175 किमी की निम्न दाब लाइन का रिनोवेशन कार्य किया गया है।नए इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ी हुई मांग के दबाव और आने वाले समय में भी लाभ मिलेगा और आपूर्ति सुगम हो सकेगी।

32 साल बाद भी जारी है संघर्ष...

हुकमचंद मिल : 3210 मजदूर अब भी भटक रहे पैसों के इंतजार में

हुकमचंद मिल के मजदूर और उनके स्वजन का संघर्ष 32 वर्ष बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मजदूरों के पक्ष में मप्र गृह निर्माण मंडल ने दिसंबर 2023 में ही 218 करोड़ रुपये परिसमापक के खाते में जमा करा दिए थे, बावजूद इसके मिल के मजदूर अपने ही पैसे के लिए भटक रहे हैं। मिल के 5895 मजदूरों को भुगता न होना है। इनमें से सिर्फ 2685 मजदूरों को ही अब तक भुगतान मिला है। शेष 3210 अपने हक के लिए भटक रहे हैं। कभी अधूरे दस्तावेजों के नाम पर तो कभी अनुमति नहीं होने के नाम पर उनका भुगतान अटक रहा है। 12 दिसंबर 1991 को मिल प्रबंधन ने हुकमचंद मिल बंद करने का फैसला लिया था। उस वक्त मिल में काम कर रहे 5895 मजदूरों ने 32 वर्ष तक अपने हक की लड़ाई न्यायालयों में लड़ी। वर्ष 2007 में मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मिल के मजदूरों के पक्ष में फैसला लेते हुए उनके बकाया वेतन व अन्य देनदारियों का भुगतान करने का आदेश दिया था। यह भुगतान मिल की जमीन को बेचकर किया जाना था, लेकिन मिल की जमीन बिक ही नहीं सकी। करीब 10 माह पहले नगर निगम इंदौर और मप्र गृह निर्माण मंडल ने संयुक्त रुप से मिल की जमीन पर आवासीय और व्यवसायिक काम्प्लेक्स लाने की योजना तैयार की। अनुबंधों की शर्तों के मुताबिक मिल की देनदारियों की जिम्मेदारी मप्र गृह निर्माण मंडल की है। मंडल ने 20 दिसंबर को मिल के मजदूरों के पक्ष में 218 करोड़ रुपये की राशि परिसमापक के खाते में जमा करा भी दी। हाई कोर्ट द्वारा गठित समिति की जांच के बाद मजदूरों को यह राशि वितरित की जाना है। प्रत्येक मजदूर को तीन लाख से लेकर पांच लाख रुपये तक का भुगतान होना है। मजदूर नेता नरेंद्र श्रीवंश ने बताया कि अब भी ढाई हजार से ज्यादा मजदूर हैं जिन्हें भुगतान होना शेष है।

2,100 की मौत हो चुकी

अपने हक के पैसों के इंतजार में कुल 5,895 श्रमिकों में से 2100 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। करीब 2000 श्रमिक या तो लकवाग्रस्त हैं या फिर अन्य किसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं। ज्यादातर श्रमिक आर्थिक रूप से बुरी हालत में हैं। उनके घर राशन की भी दिक्कत है। कई परिवारों में बेटे-बेटियों की शादी तक नहीं हो सकी है। सैकड़ों श्रमिकों ने खटिया पकड़ ली है और कई ऐसे हैं जो पैसा न मिलने से परेशान होकर आत्महत्या भी कर चुके हैं।

सिर्फ आश्वासन मिला

श्रमिकों को अब तक मुंबई स्थित डीआरटी, शासन, नेता सभी से केवल आश्वासन ही मिला है। सभी आकर उनकी समस्याओं को तो सुनते हैं लेकिन हल करने में कोई पहल नहीं करते। श्रमिक मालवा मिल चौराहा स्थित संत रविदास सेतु पर धरना भी दे चुके हैं।

छात्रों की चिंताओं को किया जायेगा दूर, गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं-शिक्षामंत्री प्रधान

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट विवाद पर कहा छात्रों की चिंताओं को निष्पक्षता और समानता के साथ दूर किया जायेगा। इसके साथ ही उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि NEET परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट विवाद को लेकर कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यदि कोई खामी पाई गई तो एनटीए में जवाबदेही तय की जाएगी। प्रधान ने 'टॉपर्स' की संख्या में वृद्धि पर कहा कि एनसीईआरटी के तर्कसंगत पाठ्यक्रम के अनुसार एनईईटी पाठ्यक्रम कम किया गया, प्रश्न राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुरूप किए गए। उन्होंने आगे कहा कि कट-ऑफ, सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है, जिससे प्रतिस्पर्धा अभी अधिक हो गई है।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट विवाद पर कहा छात्रों की चिंताओं को निष्पक्षता और समानता के साथ दूर किया जायेगा। इसके साथ ही उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि NEET परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। मैं परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। उन्होंने आगे लिखा कि इस मामले से जुड़े तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, सरकार उसे पूरा करेगी। NEET की काउन्सलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और अब इस दिशा में भ्रमित हुए बिना आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

उच्चतम न्यायालय ने नीट-यूजी, 2024 में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र एवं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से जवाब मांगा। नीट-यूजी को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने सीबीआई और बिहार सरकार से भी दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। पीठ हितेन सिंह कश्यप द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

...क्या अग्निवीर योजना बनेगी मोदी 3.0 के गले की फांस ?

इन राज्यों ने बना लिया 'इज्जत' का सवाल

एनडीए में साथी पार्टी जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर काफी विरोध हुआ था। चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला है। इस पर पुनर्विचार की जरूरत है।

18वें लोकसभा चुनाव में अग्निपथ योजना प्रमुख मुद्दा बन कर उभरी। 2022 में योजना के लागू होने के बाद से ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस योजना को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमलावर रहे। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और यूपी में भाजपा की सीटें घटने की वजह अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं की नाराजगी भी है। वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भले ही भाजपा ने सभी सीट ली हों, लेकिन 2019 के मुकाबले वोट शेयर घट गया है। लेकिन क्या मोदी 3.0 में सरकार इस योजना को वापस लेगी? एनडीए के घटक दलों में शामिल जेडीयू ने सरकार बनने से पहले ही इस योजना को लेकर अपनी आवाज मुखर कर दी है। जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इस योजना को लेकर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो सकती है।

14 जून 2022 में संसद में बहुमत वाली मोदी सरकार ने जब अग्निपथ योजना को लागू किया था, उसके बाद से ही युवाओं में नाराजगी बढ़ गई। आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने इस योजना का जमकर विरोध किया था। रेलें रोकी गईं, वाहन फूंके गए, सड़कों पर खूब प्रदर्शन हुए, करोड़ों की संपत्ति की संपत्ति खाक हुई, लेकिन सरकार इस योजना को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुई। सेना के रिटायर्ड अफसरों ने भी इस योजना को लेकर सरकार की जमकर आलोचना की, लेकिन सरकार ने अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया। राहुल गांधी ने इस योजना को न केवल विधानसभा चुनावों बल्कि लोकसभा चुनावों में प्रमुख मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में वादा किया कि सरकार बनने पर वे इस योजना को हटा देंगे।

जेडीयू ने कहा, योजना पर पुनर्विचार की जरूरत

अब जब लोकसभा चुनावों में भाजपा बहुमत से कम सीटें मिली हैं और उसे जेडीयू और टीडीपी के सहारे सरकार बनानी पड़ रही है, तो यह योजना एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गई है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर काफी विरोध हुआ था। चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला है। इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। जो सुरक्षाकर्मी सेना में तैनात थे, जब अग्निवीर योजना चलाई गई, तो बड़े तबके में असंतोष था। मेरा

मानना है कि उनके परिवार ने चुनाव में विरोध किया। इस योजना पर नए तरीके से विचार करने की जरूरत है। इसकी वजह बिहार विधानसभा चुनाव को माना जा रहा है, जो अगले साल अक्तूबर-नवंबर में प्रस्तावित हैं। जब यह योजना आई थी तो बिहार में सैन्य भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने काफी बवाल किया था, हालांकि उस समय तो नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनके इस बयान को काफी माना जा रहा है।

वापस आए पुरानी योजना : वहीं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दुहून का कहना है कि इस योजना में कई तरह की समस्याएं हैं और इसे किसी भी तरह से बदलकर ठीक नहीं किया जा सकता। इस योजना को खत्म किया जाना जरूरी है और इसकी जगह पुरानी, टाइम टेस्टेड योजना को वापस लाया जाना चाहिए। जो हमारे सुरक्षा बलों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।

योजना को लेकर अफसरों ने सरकार को बनाया मूर्ख!

रिटायर्ड मेजर जनरल सीएम सेठ भी इस योजना को लेकर खुश नहीं हैं। वह कहते हैं कि अग्निवीर योजना के तहत सेना को सबसे अधिक सैनिक देने वाले राज्यों-राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब में भाजपा को खासी चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा आने वाले विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है, तो इस योजना को रद्द कर देने में ही भलाई है। वह कहते हैं कि सेना के शीर्ष अफसरों ने इस योजना को लेकर सरकार को मूर्ख बनाया है और अब चेतने का समय है।

पंजाब में अग्निवीर योजना का विरोध

मेजर जनरल (रि.) सीएम सेठ का यह कहना काफी हद तक सही है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब, जहां भाजपा की सीटें पहले के मुकाबले घटी हैं और भाजपा को बहुमत पाने से रोक दिया है, सबसे ज्यादा सैनिक देने वाले राज्य हैं। तीनों सेनाओं में तीन लाख से अधिक सैन्य कर्मी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से हैं। इन राज्यों में पूर्व सैनिकों की संख्या लगभग 6.20 लाख है। वहीं, उनके परिवार के सदस्य भी मतदाता सूची में हैं। ऑल-इंडिया डिफेंस ब्रदरहुड के प्रदेश अध्यक्ष और रक्षा सेवा कल्याण के पूर्व निदेशक ब्रिगेडियर केएस काहलों (सेवानिवृत्त) कहते हैं, 'पंजाब के ग्रामीण इलाकों के युवा सेना में भर्ती के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन अग्निवीर योजना आने के बाद नौकरी की अनिश्चितता और रोजगार के सीमित अवसरों के चलते उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिए और पंजाब में भाजपा की सीटें जीरो हो गईं।'

हरियाणा में घटीं सीटें : हरियाणा में सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरूआत लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें कम होने की प्रमुख वजह रही है। हरियाणा में भाजपा सीटें 10 से घटकर 5 हो गईं और वोट शेयर 58.20 फीसदी से घटकर 46.11 फीसदी हो गया। हरियाणा के युवा को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के युवा अब अग्निपथ योजना के तहत होने वाली भर्ती में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। युवा अब पहले की तरह सुबह सड़कों पर दौड़ लगाते नहीं दिखाई देते। स्थानीय युवाओं के साथ-साथ बुजुर्गों को भी लगता है कि इस योजना के आने के बाद उनका सैन्य सेवा करने का सम्मान उनसे छीन लिया गया है और इसे एक अस्थायी नौकरी में बदल दिया गया है।

सेना में भर्ती के लिए मशहूर शेखावटी में लगा झटका

इस योजना की वजह से भाजपा को राजस्थान के जाट बहुल्य शेखावटी इलाके में भी करारा झटका लगा है। यहां की तीनों सीटें सीकर, चूरू और झुंझुनूं सीट कांग्रेस ने छीन ली हैं। ये तीनों जिले सेना में भर्ती के लिए मशहूर हैं। झुंझुनूं को देश को सर्वाधिक सैनिक देने वाला जिला कहा जाता है। सीकर और चूरू में भी सैनिकों और पूर्व सैनिकों की काफी तादाद है। राजस्थान में भाजपा की सीटें 24 से घटकर 14 रह गईं। दौसा के रहने वाले हनुमान कहते हैं, 'गांव से हर साल देश की सेना में किसी न किसी परिवार से युवा का चयन होता था, जिससे सभी युवा साथियों में चयन को लेकर एक अलग ही जोश हुआ करता था। लेकिन अग्निवीर योजना आने के बाद वही युवा नशे/गलत दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस बार सभी ने अग्निवीर के विरोध और किसानों के हित में मतदान किया। इसलिए वादे के अनुरूप तेजाजी महाराज के मंदिर पर पूरे गांव को उन्होंने लड्डू बटवाएं।'

हिमाचल-उत्तराखंड में घटा वोट प्रतिशत : वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें, तो भले ही भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में चारों सीटें जीत ली हों, लेकिन वोट शेयर 2019 के मुकाबले 69.70 फीसदी से घटकर 56.44 फीसदी हो गया। जबकि उत्तराखंड में पांचों सीटें जीतने के बाद भी वोट शेयर 2019 के मुकाबले 61.66 फीसदी से घट कर इस बार 56.81 फीसदी रह गया।

समिति ने की थी मुआवजा बढ़ाने की सिफारिश

करीब तीन महीने पहले रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय से सिफारिश की थी कि ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवारों को भी वही लाभ मिलना चाहिए, जो नियमित सैनिक के शहीद होने पर उनके परिवारों को मिलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने समिति को सैनिकों को मिलने वाले मुआवजे के बारे में जानकारी दी। जिसके जवाब में स्थायी समिति ने रक्षा मंत्रालय से कहा कि 'सरकार सभी हालात में सैनिकों के शहीद होने पर मुआवजे की राशि 10 लाख रुपये तक बढ़ाने पर विचार करे। किसी भी श्रेणी के तहत न्यूनतम मुआवजा राशि 35 लाख रुपये और अधिकतम मुआवजा राशि 55 लाख रुपये होनी चाहिए।'

चार साल से पहले नहीं कर सकते रिटायर

इससे पहले मोदी सरकार में मंत्री रह चुके और मार्च 2010 से मई 2012 तक सेना प्रमुख का पद संभाल चुके जनरल वीके सिंह ने एक साक्षात्कार में कहा था कि अग्निवीरों के पहले बैच के चार साल की सेवा पूरी होने पर अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को जबरन रिटायर नहीं किया जा सकता है और चार साल की सेवा के बाद कुछ बदलाव किए जा सकते हैं।

सरकार भी भांप रही है इस विरोध को

हालांकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष जिस तरह से इसे मुद्दा बना रहा था, तो मोदी सरकार भी इसे भांप रही थी। जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो स्कीम को रिव्यू कर उसमें बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कीम के तहत भर्ती हुए अग्निवीर उनकी जिम्मेदारी हैं। इससे पहले मार्च में भी एक समिट के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे ही संकेत दिए थे। इसके बाद छठवें चरण के चुनाव से पहले सेना के सूत्रों की तरफ से खबर आई कि रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स (डीएमए) ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से अग्निवीरों पर एक आंतरिक सर्वे करा रही है, जिसमें अग्निवीरों से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका मकसद भर्ती प्रक्रिया पर योजना के असर को जानना है। सरकार की तरफ से संकेत दिए गए कि इस योजना के परमानेंट किए जाने वाले अग्निवीरों की संख्या को 25 से बढ़ा कर 50 फीसदी किया जा सकता है।

समाजवादी पार्टी की साइकिल पर कब तक सवारी करेगी कांग्रेस

कांग्रेस की यह महत्वाकांक्षा भविष्य में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है, क्योंकि तब एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश होगी, जहां से दोनों दलों के बीच सियासी तलवार खींचना निश्चित है।

आम चुनाव में उत्तर प्रदेश से जो नतीजे आये उससे एनडीए गठबंधन का खेल मुश्किल गया, वहीं इंडी गठबंधन को बड़ी सफलता मिली है। इसके चर्चे भी खूब हो रहे हैं। इससे पहले 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में राहुल-अखिलेश का साथ आना और 2019 के लोकसभा चुनाव के समय मायावती-अखिलेश के एकजुट होने की नाकामयाब पटकथा लिखी जा चुकी थी, इसलिए इस बार भी राहुल-अखिलेश की जोड़ी से किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बार तो राहुल-अखिलेश ने चमत्कार दिखाते हुए बीजेपी से आगे-पीछे का सारा हिसाब एक ही बार में बराबर कर लिया। इसके मुख्य किरदार सपा प्रमुख अखिलेश यादव है,जिन्होंने न केवल समाजवादी पार्टी को शानदार जीत दिलाई बल्कि कांग्रेस को भी यूपी में एक बार फिर से उभरने का मौका दिया, जिसकी वजह से नवगठित मोदी सरकार की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं लग रही है। परंतु सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस गठबंधन का भविष्य कितना लम्बा है। ऐसा इसलिये पूछा जा रहा है क्योंकि चुनाव नतीजे आये कुछ ही दिन नहीं हुए हैं और गांधी परिवार और कांग्रेस यूपी को लेकर नई रणनीति बनाने लगी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की साइकिल पर चढ़कर उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस यदि जल्द सपा की साइकि से उतर कर यूपी की राजनीति में अपना पुराना मुकाम हासिल करने की कोशिश करें तो किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए।

कांग्रेस की यह महत्वाकांक्षा भविष्य में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है, क्योंकि तब एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश होगी, जहां से दोनों दलों के बीच सियासी तलवार खींचना निश्चित है। यह सब कब शुरू होगा यह तो निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है लेकिन धीरे धीरे दोनों दलों के बीच दूरियां बढ़ाना शुरू होगी जो अंत में विस्फोटक रूप धारण कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है वह कभी कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक हुआ करता था। कांग्रेस इसे फिर से हासिल करना चाहती है। इस बात के संकेत मिलना भी शुरू हो गए हैं. कहां जा रहा है की यूपी में कांग्रेस को पुरानी प्रतिष्ठा लौटाने के लिए राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी के समझाने पर रायबरेली से ही सांसद बने रहने को तैयार हो गए हैं।

लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस की पहली बैठक और परिवार के साथ रायशुमारी के बाद उन्होंने यह फैसला किया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, राहुल दोनों सीटों में से कौन सी सीट चुनें, उनकी इस दुविधा को सोनिया गांधी ने दूर कर दिया है। सोनिया ने राहुल को समझाया कि यूपी कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए उन्हें रायबरेली अपने पास रखना चाहिए। यह भी कहा जा रहा है कि प्रियंका दोबारा यूपी प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने इस पद को छोड़ दिया था। राहुल के सीट छोड़ने पर प्रियंका वायनाड से उपचुनाव लड़ सकती हैं। गांधी परिवार इसके जरिए उत्तर के साथ दक्षिण में पकड़ मजबूत रखना चाहता है।

राहुल के रायबरेली में बने रहने की सहमति के पीछे मां सोनिया की वह भावुक अपील भी है, जिसमें उन्होंने कहा था, 'आपको बेटा सौंप रही हूं।' राहुल ने भी चुनाव नतीजे आने के पहले ही दिन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका संकेत दिया था। उन्होंने यूपी को स्पेशल थैंक्यू बोला था।पार्टी के एक सीनियर लीडर ने बताया कि रायबरेली की जीत इस लिहाज से भी बड़ी है कि परिवार ने अमेठी की खोई सीट भी हासिल कर ली है। रायबरेली में राहुल को वायनाड से बड़ी जीत मिली। ऐसे में वह रायबरेली छोड़ेंगे तो यूपी में गलत राजनैतिक मैसेज जाएगा। नेहरू-गांधी परिवार का दशकों पुराना यूपी से रिश्ता भी कमजोर हो जायेगा। क्योंकि गांधी परिवार के मुखिया ने हमेशा यूपी से ही राजनीति की। पिता राजीव गांधी अमेठी और परदादा जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से चुनाव लड़ते रहे हैं। रायबरेली सीट उनकी मां, दादी इंदिरा और दादा फिरोज गांधी की सीट है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

ऋण वसूली के लिए बैंक लुकआउट सर्कुलर नहीं जारी कर सकते...

अदालत ने कर्ज चुकाने में विफल रहने वाली कंपनी के पूर्व निदेशक के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि विदेश यात्रा की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए एलओसी एक बड़ी बाधा है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ही बाध्यकारी कारणों को छोड़कर विदेश जाने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बैंक कर्ज वसूली से जुड़े एक मामले में बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि बैंक कर्ज वसूली के लिए बैंक लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) नहीं जारी कर सकते जब तक कि धोखाधड़ी या धन की हेराफेरी का कोई आरोप न हो। अदालत ने कर्ज चुकाने में विफल रहने वाली कंपनी के पूर्व निदेशक के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि विदेश यात्रा की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए एलओसी एक बड़ी बाधा है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ही बाध्यकारी कारणों को छोड़कर विदेश जाने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने 28 मई को पारित एक फैसले में ये बातें कहीं। अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है और न ही उन पर कोई आरोप है कि उसने गबन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अदालत ने कहा कि बैंक ने याचिकाकर्ता के साथ-साथ उनकी कंपनी के खिलाफ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) कानून और दिवाला व ऋण शोधन अक्षमता संहिता जैसे विभिन्न कानूनों के तहत पहले ही कदम उठा दिए हैं। याचिकाकर्ता जो कंपनी के निदेशकों में से एक था ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए 69 करोड़ रुपये के क्रेडिट की गारंटी दी थी। बाद में उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया और एक अन्य इकाई में शामिल हो गए। कंपनी द्वारा कर्ज नहीं चुका पाने के बाद बैंक ने विभिन्न कानूनों के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की और याचिकाकर्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का अनुरोध किया।

अदालत ने कहा कि हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विदेश यात्रा के अधिकार की गारंटी है और इसे मनमाने और अवैध तरीके से नहीं छीना जा सकता है। अदालत ने कहा, 'लेकिन अब बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां बैंक बिना किसी आपराधिक कार्यवाही के केवल धन की वसूली के उपाय के रूप में लुक आउट सर्कुलर जारी करने पर जोर दे रहे हैं।' अदालत ने कहा कि बैंक ऋण चूक के प्रत्येक मामले में एलओसी का सहारा नहीं लिया जा सकता क्योंकि नागरिकों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने आदेश दिया, 'उपरोक्त बातों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द किया जाता है।'

हवाई किराये की समीक्षा करेगी सरकार

विमानन मंत्री बोले- आम आदमी के लिए हवाई यात्रा सुलभ बनाएंगे

देश के विमानन क्षेत्र में देश में तेजी से विकास हो रहा है और देश के एयरलाइन रिकॉर्ड नए विमान ऑर्डर दे रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार है, लेकिन घरेलू वाहकों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े व्यवधानों से जूझना पड़ता है, जिससे विमान डिलीवरी में देरी होती है, जिससे हवाई किराए में वृद्धि होती है।

नई सरकार के शपथ ग्रहण बाद मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों की कमान थाम ली है। सरकार के मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों में काम करना भी शुरू कर दिया है। इस बीच नए नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि देश में वर्तमान हवाई किराये की समीक्षा की जाएगी। कहा कि वे बढ़ते किराए के मुद्दे से निपटकर हवाई यात्रा को आम आदमी के लिए और अधिक सुलभ बनाना चाहते हैं।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने हवाई किराए में उतार-चढ़ाव के बारे में बात करते हुए कहा कि वे हवाई मार्ग को नया रेलवे बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हवाई किराए को नियंत्रण में रखने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर अभी फैसला नहीं किया गया है, लेकिन उनका इरादा आम आदमी के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाना है। हम आवश्यक कदम उठाने के लिए एक नीतिगत बैठक करने जा रहे हैं। नायडू ने कहा पिछले दस वर्षों में बहुत कुछ हुआ है, सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है। लेकिन कोविड जैसे कई बाहरी कारकों से यह प्रभावित हुआ है। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार है, लेकिन घरेलू वाहकों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े व्यवधानों से जूझना पड़ता है, जिससे विमान डिलीवरी में देरी होती है, जिससे हवाई किराए में वृद्धि होती है। एक भारतीय संसदीय पैनल ने फरवरी में प्रस्ताव दिया था कि सरकार को हवाई किराए में अचानक उछाल को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए। दूसरी ओर एयलाइन्स का तर्क है कि किराए आपूर्ति और मांग से संचालित होते हैं। नई सरकार में विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, 'टिकटों की कीमतें किसी भी कारण से बढ़ी हों... मैं वास्तव में इस मुद्दे पर गहराई से विचार करना चाहता हूं (और) उन्हें इस देश के लोगों के लिए थोड़ा और अधिक सुलभ कैसे बनाया जाए इस पर कार्य कर रहा हूं।'

साधारण किसान परिवार से निकलकर देश की सत्ता के केंद्र तक पहुंचे सिंह

गृह और रक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण मंत्रालय संभालने वाले राजनाथ सिंह को मोदी 3.0 में भी रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वस्त नेताओं में शामिल राजनाथ ने ही 2013 में एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उनका नाम आगे बढ़ाया था।

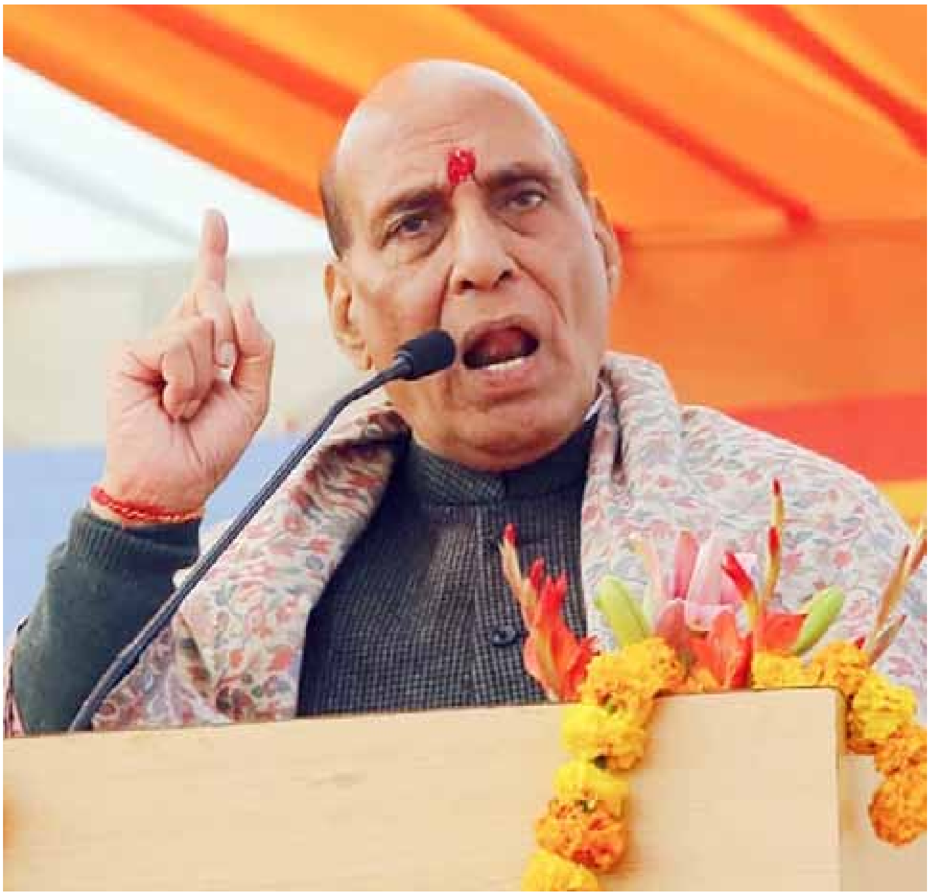

मोदी सरकार के पहले दोनों कार्यकाल में गृह और रक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण मंत्रालय संभालने वाले राजनाथ सिंह को मोदी 3.0 में भी रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वस्त नेताओं में शामिल राजनाथ ने ही 2013 में एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उनका नाम आगे बढ़ाया था। सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी जब भी विदेशी दौरों पर जाते हैं तो देश के मुखिया के रूप में राजनाथ सिंह को ही जिम्मेदारी सौंपते हैं। सिंह लगातार तीसरी बार लखनऊ से सांसद चुनकर लोकसभा में पहुँचे हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के भभुआरा गांव में हुआ था। किसान परिवार में जन्मे राजनाथ सिंह ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की और केबी पोस्ट-ग्रेजुएट कॉलेज मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में भौतिकी के व्याख्याता के रूप में कार्य किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश के सबसे वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं में से एक हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के छात्र कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने 1974 में राजनीति में प्रवेश किया और 1977 में वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक चुने गए।

वह 1988 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए चुने गए और 1991 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बने। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए, जैसे नकल विरोधी अधिनियम, पाठ्यक्रम में वैदिक गणित को शामिल करना तथा इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के विभिन्न विकृत अंशों को सही करना। मार्च 1997 में जब वे भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष बने, तो उन्होंने पार्टी के आधार को बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने में अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने राजनीतिक संकट के दौरान दो बार भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अक्टूबर 2000 में वे भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इससे पहले नवंबर 1999 में वे श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री बने।

2003 में राजनाथ सिंह केन्द्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बने। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने एनएचडीपी (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम) की शुरुआत की, जो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक स्वप्निल प्रोजेक्ट था। केंद्रीय कृषि मंत्री और तत्पश्चात खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के रूप में उन्होंने किसान कॉल सेंटर और कृषि आय बीमा योजना जैसी युगांतकारी परियोजनाओं का नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाद में विभिन्न विभागों के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी भूमिका में, उन्होंने देश की लोकतांत्रिक संरचना को मजबूत करने के लिए काम किया और लोगों, विशेषकर समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित रहे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूरे देश का दौरा किया। जिसके तहत कई राज्यों का दौरा किया गया। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, किसानों की शिकायतों और यूपीए सरकार द्वारा अपनाई गई सनकी अल्पसंख्यकवाद जैसे जनहित के मुद्दों पर जोर दिया। 2014 में वे नरेन्द्र मोदी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री बने और 2019 में देश के रक्षा मंत्री बनाए गए। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने विभिन्न विभागों और क्षेत्रीय अभियानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। भारतीय सेना में सैन्य पुलिस के कोर में महिलाओं को सिपाही के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव उनके द्वारा लिया गया था और कुल 1,700 महिला सैन्यकर्मियों की भर्ती का निर्णय भी उनके नेतृत्व में लिया गया था। रक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद से ही एसएससी में महिला अधिकारियों का कार्यकाल 10 से बढ़ाकर 14 वर्ष करने और सेना में उनकी पदोन्नति की संभावनाओं को बेहतर बनाने जैसे कदम उठाए गए हैं। रक्षा मंत्री के रूप में, वे भारतीय सशस्त्र बलों में 'नारी शक्ति' को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

उत्तरप्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! स्थानांतरण नीति मंजूरी

कैबिनेट बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 41 को मंजूरी दे दी गई। वेतन वृद्धि को लेकर आए प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। 1 दिन पूर्व रिटायर होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। उप्र में सीएम ने सरकार के कर्मचारियों के लिए 24-25 के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी।

यह निर्णय यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। दरअसल, कैबिनेट बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 41 को मंजूरी दे दी गई। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों की जानकारी देते हुए घोषणा की कि कैबिनेट ने 2024-25 के लिए स्थानांतरण नीति का समर्थन किया है। यह नीति पिछले वर्ष की नीति के प्रावधानों के अनुरूप है।

नई स्थानांतरण नीति 2024-25

नई नीति के मुताबिक मंडल में सात साल और जिले में तीन साल सेवा देने वाले ग्रुप ए और बी के अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। नीति में कहा गया है कि समूह ए और बी में 20 प्रतिशत तक अधिकारियों और समूह सी और डी में 10 प्रतिशत तक कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा सकता है। समूह सी और डी के लिए, नीति सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अधिकारियों को पहले स्थानांतरित करने को प्राथमिकता देती है। ग्रुप सी और डी के 10 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों का ट्रांसफर करना जरूरी होने पर मंत्रालय की मंजूरी जरूरी होगी। इसी तरह ग्रुप ए और बी के 20 फीसदी से अधिक अधिकारियों के तबादले के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी होगी।

उन्होंने कहा कि समूह सी और डी के स्थानांतरण पूरी तरह से मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से प्रबंधित किए जाएंगे। यह प्रणाली स्थानांतरण के बाद कार्यभार सौंपने और लेने की ऑनलाइन व्यवस्था की सुविधा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यह सेवा पुस्तिकाओं और अधिकारियों के वेतन के डिजिटलीकरण की अनुमति देता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि, 34 जिलों के आठ आकांक्षी जिलों और 100 आकांक्षी विकास खंडों के लिए मौजूदा प्रणाली के तहत, इन क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इस अवसर पर कैबिनेट ने राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपहार की भी घोषणा की। घोषणा के मुताबिक, 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी से प्रस्तावित वेतन बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अब तक जो व्यवस्था थी, उसके मुताबिक 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी से लागू होने वाली वेतन बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल पाता था। कैबिनेट की मंजूरी से न केवल ऐसे कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की सुविधा होगी बल्कि उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद न्यायिक कर्मचारी पहले से ही इसका लाभ उठा रहे हैं और अब इस नीति से अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी फायदा होगा।

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के नामों में संशोधन किया जाएगा : योगी सरकार ने राज्य के 5 विश्वविद्यालयों के नाम में भी मामूली संशोधन किया है, जिसमें महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आज़मगढ़, मां शाकुंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर, मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मिर्ज़ापुर, मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर से 'राज्य' शब्द हटा दिया गया है। और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद।उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम बदलकर गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कर दिया गया है।

2 नए निजी विश्वविद्यालयों को एलओआई

उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विद्यार्थियों के हित में उच्च शिक्षा के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकारी विश्वविद्यालयों के साथ-साथ निजी विश्वविद्यालयों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में दो नए निजी विश्वविद्यालयों को आशय पत्र देने का प्रस्ताव पारित किया गया है. इनमें से एक है एचआरआईटी गाजियाबाद और दूसरी है फ्यूचर यूनिवर्सिटी, बरेली। उन्होंने कहा कि दोनों ने अपने सभी मानक पूरे किये हैं।

20 पार्टियां मिलकर जितना लाई... बीजेपी अकेले ही उससे ऊपर आई

बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे नरेंद्र मोदी के संबोधन में ऊर्जी में कोई कमी दिखाई नहीं दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम ऐसे ही बड़े फैसले लेते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1962 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार तीसरी बार सत्ता में आ रही है।

नरेंद्र मोदी के सत्ता के शिखर पर कदमताल करने की कहानी लिखे जाने के बाद दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय तो जैसे अपने सबसे बड़े स्टार के लिए पलकें बिछाए बैठा था। यह तो तय है कि मोदी तो मोदी हैं और मोदी जैसा कोई नहीं। एनडीए को तीसरी बार मिली इस सफलता के मैन ऑफ द मैच नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों की जोड़ी पूरे देश में ऐसी दौड़ी की क्या बिहार क्या ओडिशा क्या आंध्रा एक-एक कर सारे प्रदेश भाजपा की झोली में आकर गिरने लगे। जिसके बाद नरेंद्र मोदी का भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसा स्वागत तो बनता है। पुष्पहार, बंदनवार, तोरण द्वार, फूलों की बौछार और मुद्रा कुछ ऐसी की तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।

बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे नरेंद्र मोदी के संबोधन में ऊर्जी में कोई कमी दिखाई नहीं दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम ऐसे ही बड़े फैसले लेते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1962 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार तीसरी बार सत्ता में आ रही है। इसके साथ ही सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए। 400 पार का नारा देने वाला एनडीए 290 सीटों पर आकर रूक गया। वहीं एनडीए को कड़ी टक्कर देने वाला इंडिया गठबंधन उसे 234 सीटें मिली। विपक्ष इसे अपनी जबरदस्त सफलता मान रहा है। उसे लग रहा है कि वो मीद को हटाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन सच्चाई ये है कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। सरकार बनाने के लिए 272 का आंकड़ा पार करना होता है जो 13 दले मिलकर भी हासिल नहीं कर पाई है। वहीं बीजेपी अपने दम पर 234 सीटें हासिल कर पाई है।

वहीं एनडीए को मिलाकर ये आंकड़ा बहुमत से कहीं अधिक यानी 290 के आंकड़े के करीब हो जाता है। बीजेपी ने अकेले ही 234 सीटें जीती हैं जो कि 20 पार्टियों की कुल सीटों से ज्यादा हैं। 2024 के चुनाव में मोदी लहर की सेज पर सवार बीजेपी की गाड़ी ऐसी सरपट दौड़ी की देश की सबसे पुरानी पार्टी राजनीति का फिर से मोदी को हराने का दावा सपना बनकर रह गया। हालांकि कुछ क्षेत्रीय चेहरे ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने राज्यों में मोदी लहर को थाम लिया। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे ने अपने राज्यों में बीजेपी को मनमाफिक प्रदर्शन करने से रोक दिया।

सबका साथ सबका विश्वास वाला परिणाम

इसे भारत का एक अनोखा चुनाव भी कहा जा रहा है क्यों बीजेपी जश्न मना रही है क्योंकि वे सरकार बनाएंगे। कांग्रेस जश्न मना रही है क्योंकि वे 100 सीटें पार कर रहे हैं। सपा, राजद जश्न मना रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना समर्थन वापस मिल गया है। एनसीपी-एसपी और एसएस-यूबीटी खुश हैं क्योंकि उन्होंने सब दिखा दिया कि वे बॉस हैं। टीएमसी खुश है क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी की सीटों को बढ़ा लिया। आम जनता भी खुश हैं क्योंकि उन्होंने जिस भी पार्टी का अनुसरण कर रहे हैं थे उन्हें मनमाफिक सफलता हासिल हुई। इससे पहले कभी भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अपने मुख्यालय में एक साथ जीत का जश्न मनाते नहीं देखा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव आयोग पर भी अब तक कोई भी ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप नहीं लगा रहा है।

14-20 में क्लीन स्विप, बीजेपी की आंधी में कांग्रेस ने कैसे झंडा लहराया!

कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को छोड़कर अधिकांश नए लोगों को मैदान में उतारा। वैभव जोधपुर से 2019 का चुनाव हार गए थे। जानकारों का मानना है कि सहयोगियों को तीन सीटें देने का फैसला चूरू, सीकर और बांसवाड़ा में काम भी आया। कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया, जहां उसने 2023 के विधानसभा चुनावों में अपनी ताकत भी साबित की। किसान मुद्दों ने शेखवाटी क्षेत्र में काम किया। पूर्वी राजस्थान में संविधान से जुड़ी चिंताएं कांग्रेस के लिए काम आईं।

2014 और 2019 के राष्ट्रीय चुनावों में राज्य में कोई भी सीट जीतने में नाकाम रहने के बाद कांग्रेस ने राजस्थान में लोकसभा चुनावों में महत्वपूर्ण वापसी की है। वह राज्य की 25 सीटों में से आठ पर आगे चल रही है जबकि उसके सहयोगी तीन पर आगे हैं। भाजपा ने एक सीट जीत ली है और 13 अन्य पर आगे चल रही है। विशेषज्ञों ने कांग्रेस के बदलाव के कारणों में बेहतर उम्मीदवार चयन को श्रेय दिया। पार्टी किसानों के गुस्से को भुनाने के अलावा आंतरिक संघर्षों से उबरने और एकजुट मोर्चा पेश करने में कामयाब रही। कांग्रेस ने संविधान में संभावित बदलावों और आरक्षण कोटा के खतरों के बारे में चिंताएं उठाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों से समर्थन जुटाया।

कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को छोड़कर अधिकांश नए लोगों को मैदान में उतारा। वैभव जोधपुर से 2019 का चुनाव हार गए थे। जानकारों का मानना है कि सहयोगियों को तीन सीटें देने का फैसला चूरू, सीकर और बांसवाड़ा में काम भी आया। कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया, जहां उसने 2023 के विधानसभा चुनावों में अपनी ताकत भी साबित की। किसान मुद्दों ने शेखवाटी क्षेत्र में काम किया। पूर्वी राजस्थान में संविधान से जुड़ी चिंताएं कांग्रेस के लिए काम आईं। जाति-आधारित और धार्मिक ध्रुवीकरण इस चुनाव में काम नहीं आया। ऐसे नतीजे का एक और बड़ा कारण कम मतदान और भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी को भी बताया जा रहा है। एक अन्य विशेषज्ञ नारायण बारेथ ने कहा कि बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और धर्मनिरपेक्षता बड़े मुद्दे हैं और लोगों ने ध्रुवीकरण को खारिज कर दिया है।

राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और समझ गए कि भाजपा झूठों की पार्टी है। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने विधानसभा चुनावों में गलती की है और अब उन्होंने इसे सुधार लिया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का कोई सवाल ही नहीं है। गहलोत ने कहा कि भाजपा को न तो 370 और न ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को 400 सीटें मिलीं और ऐसे में मोदी को अब प्रधानमंत्री पद से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी के नाम पर बीजेपी स्पष्ट बहुमत हासिल करने में नाकाम रही है. उन्होंने कहा कि मोदी ने दावा किया कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 सीटें पार करेगी।

हाईकोर्ट लू से हुई मौत पर सख्त

हीट वेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की जरूरत...

न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड की एकल पीठ ने कहा है कि अब समय आ गया है कि गर्मी और शीतलहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। उन्होंने राज्य सरकार को लू के कारण मरने वाले लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने का आदेश दिया, साथ ही राज्य के मुख्य सचिव को इसके तहत तैयार किए गए 'हीट एक्शन प्लान' के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तत्काल और उचित कदम उठाने के लिए विभिन्न विभागों की समितियों का गठन करने का भी निर्देश दिया।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य में भीषण गर्मी और लू के कारण हुई मौतों का स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि लू और शीत लहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि राजस्थान सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में चल रही लू की स्थिति के कारण अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है और कहा कि हीटस्ट्रोक के कारण होने वाली मौतों में वृद्धि की मीडिया रिपोर्ट तथ्यों से परे हैं। न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड की एकल पीठ ने कहा है कि अब समय आ गया है कि गर्मी और शीतलहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। उन्होंने राज्य सरकार को लू के कारण मरने वाले लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने का आदेश दिया, साथ ही राज्य के मुख्य सचिव को इसके तहत तैयार किए गए 'हीट एक्शन प्लान' के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तत्काल और उचित कदम उठाने के लिए विभिन्न विभागों की समितियों का गठन करने का भी निर्देश दिया।

देश भर में अत्यधिक गर्मी और शीत लहर के कारण बड़ी संख्या में होने वाली मौतों को देखते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (संक्षेप में एनडीएमए) ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। अदालतों ने कहा कि 'हीटवेव और कोल्डवेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में अधिकारियों के कदमों और कार्य योजनाओं का उल्लेख करते हुए, अदालत ने कहा कि ऐसी कार्य योजनाओं का मसौदा तैयार करने के बावजूद, कल्याणकारी राज्य जनता को ऐसी भीषण गर्मी की स्थिति से बचाने के लिए प्रभावी ढंग से कदम नहीं उठाता है।

शाह और शिवराज से भी बडी जीत हासिल की लालवानी...

एकतरफा हुए चुनाव में कई कीर्तिमान स्थापित हुए, सबसे ज्यादा वोट व जीत इंदौर के नाम...

18 वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम इंदौर के लिए हमेशा यादगार रहेगा। चुनाव प्रारंभ होने से लेकर समाप्त होने तक इंदौर में कई तरह की राजनैतिक घटनाएं देखने को मिली है। इंदौर का चुनाव परिणाम एक तरफा रहा। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर कई रिकार्ड बने है। मौजूदा सांसदऔर भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी ने पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट हासिल करके नया कीर्तिमान स्थापित किया। यहीं नहीं अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को भी पीछे छोड़ते हुए लालावानी ने यह 12 लाख से भी अधिक मतों से जीता। अमित शाह और शिवराजसिंह चौहान 10 - 10 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते है। जहां तक नोटा का सवाल है तो उसने भी पूरे देश में सर्वाधिक मत लाकर अनोखा कीर्तिमान बनाया है।

लालवानी को कुल डले करीब 15.63 लाख वोट में से 79 फीसदी वोट मिले और उनको कुल वोट 12 लाख 26 हजार 751 मिले। वहीं दूसरे नंबर पर रहे बीएसपी के संजय सोलंकी को 51 हजार 659 वोट मिले। नोटा क्योंकि चुनाव आयोग नियमानुसार निकट प्रतिद्वंद्वी नहीं माना जाता है इसलिए लालवानी की जीत बीएसपी से तय होगी न कि नोटा से जो 11.71 लाख वोट बनती है। नोटा को 13.94 फीसदी वोट मिले हैं। वहीं बीएसपी का वोट प्रतिशत करीब 3.29 फीसदी रहा है। उन्होंने निकट प्रतिद्वंद्वी बीएसपी के संजय सोलंकी को 10 लाख 8 हजार 77 वोट से हरा दिया। लालवानी को कुल 12 लाख 26 हजार 751 वोट मिले। हालांकि, बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर नोटा रहा है, जिसने 2 लाख 18 हजार 674 वोट हासिल किए हैं। यह भी नोटा का अभी तक का सबसे ज्यादा वोट पाने का रिकार्ड है। अभी तक यह रिकार्ड बिहार की गोपालगंज सीट पर 51 हजार 666 वोट का था, जो साल 2019 में बना था।

कांग्रेस का साल 2019 में वोट बैंक 32 फीसदी था और बीजेपी का 65 फीसदी। इस बार कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी अक्षय बम के ऐनवक्त पर बीजेपी में जाने के बाद कोई प्रत्याशी नहीं था। उनका वोट बैंक 14 फीसदी छिटककर बीजेपी के साथ गया और वहीं तीन फीसदी बीएसपी के पास गया तो नोटा ने 14 फीसदी वोट बैंक कांग्रेस का ले लिया। बीते चुनाव में बीएसपी को मात्र 0.30 फीसदी वोट मिले थे जो साढे हजार से ज्यादा था और नोटा को 0.50 फीसदी जो पांच हजार वोट का था।

- पिछले चुनाव में लालवानी को कुल 1068569 वोट मिले थे, लेकिन इस चुनाव मे इससे भी ज्यादा 12 लाख 26 हजार 751 वो वोट मिले है।
- पूरे देश में शंकर लालवानी पहले ऐसे प्रत्याशी बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किये और जीत का इतिहास बनाने जा रहे हैं।
- इंदौर में कुल 15 लाख 58 हजार 432 वोट गिरे थे.
- शंकर के दो रिकार्ड के अलावा दो और नए रिकार्ड बने है। बसपा के संजय सोलंकी 51 हजार 659 वोट प्राप्त किए । वे इंदौर के सभी निर्दलीय प्रत्याशियों में सबसे ऊपर रहे । यह पहला अवसर है की मध्य प्रदेश में किसी भी स्तर के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को आज तक इतने वोट नहीं मिले है।

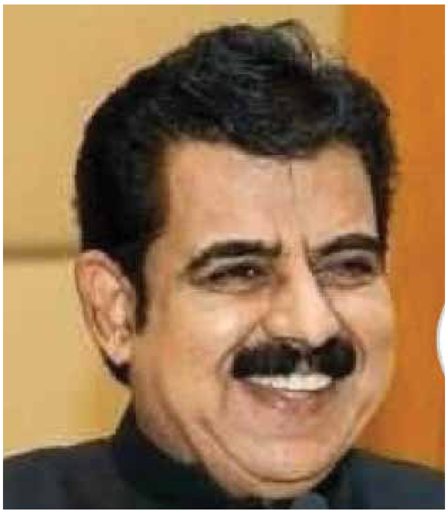

- वैसे भी मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी जैसे बसपा, सपा का कोई वजूद नहीं है। इसके बावजूद भी बसपा के प्रत्याशी संजय सोलंकी ने 51000 वोट प्राप्त कर पार्टी का एक रिकार्ड बनाया है।
- इसी प्रकार 14000 से ज्यादा वोट लाकर अखिल भारतीय परिवार पार्टी के प्रत्याशी पवन कुमार दूसरे स्थान पर रहे।
- दूसरी तरफ नोटा ने पुरे देश मे यह अनोखा कीर्तिमान बनाया है। उसने 2 लाख 18 हजार 674 वोट हासिल किए है।
- नोटा लागू होने के बाद पुरे देश मे किसी भी चुनाव मे यह पहला अवसर है जब उसे इतनी बड़ी संख्या में मत मिले हैं.। इससे पहले नोटा को सर्वाधिक मत 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के गोपालगंज मे 51660 वोट मिले थे। स्वच्छता में नंबर वन शहर इंदौर ने नोटा मे भी पूरे देश में नंबर वन हासिल कर लिया है।

केंद्रीय मंत्री छगन भुजबल ने की जाति जनगणना की मांग

महाराष्ट्र के मंत्री और वरिष्ठ ओबीसी नेता छगन भुजबल ने मराठों को ओबीसी समुदाय के लिए कोटे से आरक्षण देने की बात का विरोध किया है। दो ओबीसी कार्यकर्ता भी मराठों के आरक्षण की मांग के बाद अनशन पर बैठे हैं। अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों के सरकारी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद वरिष्ठ ओबीसी नेता ने स्पष्ट किया कि मराठों को ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य में जातीय जनगणना की जानी चाहिए।

13 जून से दो ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हेक और नवनाथ वाघमारे अनशन पर बैठे हुए हैं। सोमवार को सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने दोनों से मुलाकात की। उन्होंने दोनों से अनशन खत्म करने का आग्रह किया, साथ की पानी पीने के लिए अनुरोध किया। लेकिन दोनों आंदोलनकारियों ने इससे इंकार कर दिया। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे मराठों के लिए आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इससे ओबीसी कोटा प्रभावित नहीं होना चाहिए। वहीं वरिष्ठ ओबीसी नेता और महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय के लिए कोटे से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य में जाति जनगणना की अपनी मांग दोहराई। भुजबल ने कहा, 'मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन आरक्षण को लेकर पिछले चार आयोग ने यही कहा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे नकार दिया है।'

राज्य मंत्री ने मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे के विरोध का हवाला देते हुए कहा कि अब फिर से ओबीसी (कोटा) से आरक्षण की मांग हो रही है। भुजबल ने कहा कि राज्य में जाति आधारित जनगणना से ओबीसी समुदाय को अधिक धन मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। हड़ताली ओबीसी कार्यकर्ता राज्य सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें कुनबी को मराठा समुदाय के सदस्यों के 'ऋषि सोयारे' (रक्त संबंधी) के रूप में मान्यता दी गई है। भुजबल ने आगे कहा कि उन्होंने राज्य विधानसभा को दिखाया है कि किस तरह कुनबी रिकॉर्ड में हेराफेरी की जा रही है।

अवैध कॉलोनाईजेशन को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नये दिशा-निर्देश जारी...

अवैध कॉलोनी बसाने वालों के साथ अब प्लाट बेचने वालों के विरूद्ध भी की जाएगी कार्रवाई

अवैध कॉलोनाईजेशन पर रोक लगाई जाने के लिए कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने जिले के सभी एसडीएम और अन्य राजस्व अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये है। कलेक्टर आशीष सिंह ने इन निर्देशों को कडाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।

अवैध कॉलोनाईजेशन पर सख्ती से रोक लगाई जायेगी। अवैध कॉलोनी बसाने वालों के साथ ही अवैध कॉलोनी में प्लाट बेचने वालों के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी। अवैध कॉलोनाईजेशन पर रोक लगाई जाने के लिए कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने जिले के सभी एसडीएम और अन्य राजस्व अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये है। कलेक्टर आशीष सिंह ने इन निर्देशों को कडाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।

उक्त दिशा-निर्देशों की जानकारी देने के लिए कलेक्टर श्री सिंह की अध्यक्षता में सभी एसडीएम और संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना लोवंशी, रोशन राय, राजेन्द्र सिंह रघुवंशी तथा श्रीमती निशा डामोर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने निर्देश दिये कि इंदौर जिले में यह सुनिश्चित किया जाये कि कहीं भी अवैध कॉलोनी की बसाहट नहीं हो।

अवैध कॉलोनी बसाने वालों के साथ ही नागरिकों को अवैध प्लाट बेचने वाले ब्रोकरर्स सहित अन्य लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाये। यह ध्यान रखें कि अवैध कॉलोनी में नागरिकों के बसने के पूर्व ही उक्त कार्रवाई की जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि कृषि भूमि को छोटे-छोटे प्लाटों के रूप में विक्रय नहीं होने दे। कृषि भूमि के छोटे-छोटे प्लाटों के रूप में विक्रय/नामांतरण पर तत्काल रोक लगाई जाये। प्रायः यह देखा जाता है कि कृषि भू-स्वामियों द्वारा कृषि भूमि को छोटे-छोटे प्लाटों के रूप में विभाजित कर विक्रय कर दिया जाता है। इससे यह प्लाट एक अवैध कॉलोनी के रूप में हो जाते हैं। इससे प्लाट धारकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है और बड़ी समस्या सामने आती है। श्री आशीष सिंह ने निर्देश दिये कि एक एकड़ से कम भूमि का पंजीयन प्लाट के रूप में नहीं किया जाये।

कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिये कि विकास अनुमति एवं टीएनसीपी अभिन्यास का इन्द्राज खसरों में अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने कहा कि प्रायः यह देखने में आता है कि जगह-जगह रास्तों में ब्रोकरों आदि द्वारा होर्डिंग/गुमटियां/केनोपी आदि लगाकर आम जनता को भ्रमित करते हुए अवैध प्लाटों का विक्रय किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि इस प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगाये। ऐसे लोगों से विकास अनुमति एवं रेरा की अनुमति भी देखे। यह नहीं पाये जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाये। रेरा में पंजीकृत एजेन्ट द्वारा ही कॉलोनियों के प्लाटों के द्वारा ही बुकिंग की जा सकती है। नवीन विकास अनुमतियों में रेरा नियमों एवं ग्राम पंचायत नियम 2014 के प्रावधानों का भी सख्ती से पालन कराया जाये। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने निर्देश दिये कि राजस्व अधिकारी यह भी देखे कि किसी भी कॉलोनियों में रास्ते संबंधी विवाद नहीं हो। कॉलोनियों एवं ग्रामीणों के मध्य रास्ते संबंधी विवाद का युक्तियुक्त निपटारा किया जाये। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि टीएण्डसीपी यह सुनिश्चित करें कि विगत तीन वर्षों में स्वीकृत अभिन्यासों की प्रतियां संबंधित तहसीलदारों को उपलब्ध कराये जिससे की इसकी एंट्री खसरा अभिलेखों में की जा सकें।

गृहक्षेत्र में ही असंतोष, कार्यकर्ता बोले- पटवारी की दूसरी हार...

आम चुनाव में पूरे प्रदेश में हुई करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के प्रति उनके गृह क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में ही असंतोष पनपने लगा है। इंदौर से कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एक ही चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी की यह दूसरी हार है।

पहले अपने ही घर की सीट पर पटवारी कांग्रेस को उम्मीदवार विहीन होने से नहीं रोक पाए और अब उन्हीं के कार्यकाल में इंदौर में न केवल भाजपा की सबसे बड़ी जीत हुई बल्कि प्रदेश से कांग्रेस की संसद में भागीदारी भी शून्य हो गई।ऐसे में आगे इंदौर से प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव की मांग बुलंद होने लगे तो हैरानी नहीं होगी।कांग्रेसी कार्यकर्ता पटवारी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

आरोप लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को संगठन का समर्थन नहीं मिला। इंदौर से घोषित उम्मीदवार अक्षयकांति बम को भी संगठन का सहयोग नहीं मिला। डमी उम्मीदवार का फार्म दाखिल करने की जिम्मेदारी भी पटवारी ने अपने करीबी लोगों को दी उसमें भी वे फेल हो गए।

शिकायत पत्र दिल्ली भेजा जाएगा : नोटा के पक्ष में कांग्रेस के परंपरागत वोट भी नहीं डलवा सके। और तो और आखिरी समय यानी मतगणना में भी प्रदेश अध्यक्ष की विधानसभा क्षेत्र की टेबल ही सूनी रही। इन सभी बिंदुओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने शिकायतें दिल्ली भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस के आधे वोटर भी नहीं निकले उम्मीदवार नहीं होने के बाद कांग्रेस ने नोटा को समर्थन देने का ऐलान किया।

इसके बाद अब जब परिणामों का आंकलन किया जा रहा है तो इंदौर में कांग्रेस के परंपरागत वोट भी नहीं डल सके। दरअसल नोटा को कुल 2 लाख 18 हजार से कुछ ज्यादा वोट मिले। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अनुसार कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वोटों की कुल संख्या करीब सात लाख थी। बीते लोकसभा में पंकज संघवी को भी पांच लाख से ज्यादा वोट मिले थे।

यानी नोटा के समर्थन में कांग्रेस अपने परंपरागत वोटरों में से आधे वोटरों को बाहर नहीं निकाल सकी। कांग्रेस का चुनाव मैनेजमेंट भी फेल हो गया। मतदान वाले दिन न तो कांग्रेसी कार्यकर्ता बूथों में दिखे न टेबलें लगी। मतगणना वाले दिन भी निर्दलीय उम्मीदवार के नाम से पास बनवाकर अन्य विधानसभा की टेबलों पर तो कांग्रेसी पहुंचे लेकिन राऊ विधानसभा की टेबलें खाली रही। बम को नहीं किया सहयोगइस बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम चिट्ठी लिखी है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार को पाला बदल के पीछे भी प्रदेश अध्यक्ष की लापरवाही जिम्मेदार है। कार्यकर्ता पहले मांग कर रहे थे कि इंदौर से खुद पटवारी को चुनाव लड़ना चाहिए लेकिन वे मैदान में नहीं आए।

इसके बाद घोषित उम्मीदवार अक्षय बम की मांग पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय से स्टार प्रचारकों की सूची भी तय नहीं हो सकी। एक बार सचिन पायलट इंदौर एयरपोर्ट पर घंटों बैठे रहे। बम ने तब प्रदेश अध्यक्ष से मांग की कि खाली समय का लाभ उठाकर इंदौर में उनकी नुक्कड़ सभा ही करवा दी जाए। इसके बावजूद पटवारी ने पायलेट से तब के कांग्रेस उम्मीदवार की मुलाकात तय नहीं करवाई।

कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बीच प्रदेश में संगठन की अंदरुनी गुटबाजी भी साफ नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के गृह क्षेत्र वाले धार और रतलाम की सीटों पर भी कांग्रेस कुछ भी नहीं कर सकी। धार सीट पर भी दो लाख वोटों से ज्यादा की हार कांग्रेस को मिली। रतलाम सीट पर भी दो लाख से ज्यादा की हार कांग्रेस के हिस्से आई। ऐसे में अब कांग्रेस आलाकमान के सामने सवाल खड़ा हो रहा है कि बदलाव भी होता है तो आखिर कौन होगा जो संगठन को खड़ा कर सके और प्रदेश में नेतृत्व भी दे सके।

मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, एक एकड़ में दो की जगह पांच बोरी तक यूरिया डाल रहे किसान...

यूरिया का अत्यधिक इस्तेमाल करना भी खतरनाक है...

खेती में यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल से साल दर साल मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है। जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जिंक की कमी वर्तमान में फसल उत्पादन प्रभावित होने के साथ मानव स्वास्थ्य पर विपरीत असर पडऩे की चेतावनी भी दे रही है। किसानों का असंतुलित खाद डालने का लोभ सब पर भारी है। ये तथ्य मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की एक रिपोर्ट में हुआ है।

इस पर कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने चिंता जाहिर करते हुए किसानों को संयमित व्यवहार करने की सलाह दी है। खरीफ सीजन अगले माह 15 जून को मानसूनी बारिश के साथ शुरू हो जाएगा। जिसमें छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिले के 2.98 लाख किसान 5 लाख हैक्टेयर के रकबे में फसल लगाएंगे। इस खेती के लिए 86 हजार मीट्रिक टन खाद आ चुका है। किसानों सोसाइटी से इसका उठाव भी शुरू कर दिया है। ऐसे में किसानों को संयमित रूप से एक एकड़ में 2 से 3 बोरी यूरिया डालने की सलाह दी जा रही है। वजह साफ है कि मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यूरिया का अत्यधिक इस्तेमाल खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है।

असंतुलन से उत्पादन, लागत, मानव स्वास्थ्य प्रभावित- कृषि विभाग की मैदानी रिपोर्ट में ये तथ्य आया हैं कि जहां किसानों को मक्का समेत अन्य फसलों में एक एकड़ में दो बोरी यूरिया की जरूरत है, वे ज्यादा उत्पादन के लोभ में बेहिसाब 5-6 बोरी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पौधे की ग्रोथ समय से ज्यादा होने पर फसल लेट रही है। फसल की लागत भी दुगनी हो रही है। ये उपज जब मानव आहार बनती है तो उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है।

खरीफ में मक्का, कपास और धान प्रमुख फसल- खरीफ सीजन में पांच लाख हैक्टेयर का रकबा है। इनमें मक्का 3.60 लाख, कपास 56 हजार, धान 32 हजार, अरहर 18 हजार, सोयाबीन 13 हजार, कोदो कुटकी 10 हजार और रामतिल का रकबा 3 हजार हैक्टेयर है। इसके अलावा दूसरी फसल भी होती है।

प्रयोगशाला रिपोर्ट में जिंक की सर्वाधिक कमी- मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की 31 मार्च की स्थिति में जारी रिपोर्ट के अनुसार छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिलों के किसानों से उनके खेतों की मिट्टी के 12300 नमूने लिए गए। इनमें सबसे ज्यादा जिंक तत्व की कमी पाई गई है। शेष तत्व आयरन, मैगनीज, कापर, सल्फर और बोरान की स्थिति संतोषजनक है। कृषि अधिकारियों के मुताबिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की कमी भी बनी हुई है। जिसे किसान अनदेखा कर रहे हैं।

ये कर लें किसान तो दूर हो जाए संकट- रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि खेती में यूरिया के इस्तेमाल से केवल नाइट्रोजन और डीएपी से नाइट्रोजन, फास्फोरस की पूर्ति होती है। पोटाश, जिंक की कमी बनी रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि किसान एनपीके और जिंक का संतुलित इस्तेमाल कर लें तो मिट्टी की सेहत सुधर सकती है। फिलहाल कृषि विभाग ने अपने मैदानी कर्मचारियों को किसानों को समझाइश देने में लगाया है।

इनका कहना है...

खरीफ सीजन की मक्का समेत अन्य फसलों में यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल से हो रहे मिट्टी में हो रहे नुकसान से किसानों को अवगत कराया जा रहा है। मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जिंक की कमी सामने आई है। इससे जिले का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। फिलहाल किसानों को खाद में एनपीके व जिंक का संतुलित इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है।

-जितेन्द्र कुमार सिंह, उपसंचालक कृषि

पितरों की कृपा पाने के लिए हर शाम करें यह कार्य...

जिस घर में हमेशा सुख-समृद्धि बनी रहती हैं, वहां पितरों की कृपा होती है। अगर व्यक्ति को पितृ दोष है, तो उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही पितरों की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। वहीं, अगर पितर प्रसन्न हो, तो परिवार में खुशहाली बनी रहती है। अगर आप भी पितृ दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इन उपायों को जरूर अपनाएं।

पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं : पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ की सात बार परिक्रमा करनी चाहिए। पेड़ के नीचे दीपक में सरसों का तेल और काले तिल मिलाकर छाया दान भी करें।

पितृ दोष को खत्म करने के लिए जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्घ्य दें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, श्राद्ध, पिंडदान आदि करना बहुत शुभ होता है। अमावस्या और पितृ पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह कार्य किए जाते हैं।

पितर होंगे प्रसन्न

पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन शाम को आचमन कर स्वयं को शुद्ध करें। फिर एक मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा तेल डालकर बत्ती जलाएं और उसे छत पर दक्षिण दिशा में रख दें। पितरों से सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें। गाय के गोबर से बने दीये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं।

मानसिक शांति के लिए करें ये उपाय, ग्रह दोष से भी मिलेगा छुटकारा...

कुंडली में मौजूद हर ग्रह अपना अलग-अलग प्रभाव व्यक्ति पर डालते हैं। ग्रहों के उल्टी चाल चलने पर व्यक्ति को अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस दोष को दूर करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि दान करने से कई तरह दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी ठीक होती है। अगर कुंडली में पितृ दोष या राहु दोष हो, तो व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, सफलता हासिल नहीं कर पाता है। ऐसे में कुछ खास उपाय जरूर अपनाना चाहिए।

कष्टों से मिलेगी राहत : ज्येष्ठ का महीना बहुत गर्म माना जाता है। ऐसे में पक्षियों के लिए दाना-पानी रखने से कुंडली में राहु और शनि दोष से राहत मिलती है। कहा जाता है कि आपके द्वारा रखा गया दाना-पानी ग्रहण करने से पक्षी संतुष्ट होते हैं, इससे कष्ट दूर होते हैं। यह एक पुण्य कार्य माना जाता है।

आप कुछ कच्चे चावल के दाने भी डाल सकते हैं। कई बार लोगों की यह समस्या होती है कि उनके घर पक्षी नहीं आते हैं, लेकिन यदि आप दाना-पानी रखना शुरू करेंगे, तो कुछ ही दिनों में पक्षी आने लगेंगे। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। कोर्ट-कचहरी के मामलों से भी छुटकारा मिलता है।

इस मंदिर में सांपों की होती है पूजा, निसंतान दंपति को मिलता है संतान सुख...

हिंदू धर्म में नागों को पूजनीय माना जाता है। बता दें कि केरल के हरिपद के जंगलों में स्थित प्राचीन मन्नारसाला मंदिर नागों को समर्पित है। इस मंदिर को लेकर अपनी मान्यताएं और लोकप्रियता है। यह मंदिर विश्व स्तर पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस मंदिर में आपको नागराज और देवी नागयक्षी की अनोखी प्रतिमा देखने को मिलेगी। इस मंदिर का इतिहास भगवान परशुराम से जुड़ा है। भगवान परशुराम ने केरल की भूमि को समुद्र से प्राप्त किया और फिर इस भूमि को ब्राह्मणों को दान कर दिया। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के लिए फेमस है।

मंदिर की खासियत

आपको बता दें कि केरल के मन्नारशाला मंदिर में 1,00,000 से ज्यादा सांपों की प्रतिमाएं या छवियां स्थापित हैं। मन्नारशाला मंदिर मुख्य रूप से नागराज और उनकी अर्धांगिनी नागायक्षी देवी को समर्पित है। इस मंदिर में नागराज और देवी नागयक्षी की अनोखी प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर के दर्शन के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। मन्नारशाला मंदिर 16 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। इस मंदिर की पुजारी महिला होती है। जिनको मन्नारशाला अम्मा के नाम से जाना जाता है। मंदिर की पुजारी यानी की मुख्य पद इल्लम की सबसे वरिष्ठ महिला को दिया जाता है।

मंदिर का इतिहास

मन्नारशाला मंदिर का इतिहास भगवान श्रीहरि विष्णु के छठवें अवतार परशुराम से जुड़ा है। परशुराम को केरल का निर्माता माना जाता है। बताया जाता है कि केरल की भूमि को परशुराम ने ब्राह्मणों को दान कर दिया था। इस स्थान पर कई जहरीले सांप पाए जाते थे, जिस कारण लोगों का वहां रहना मुश्किल था। तब भगवान परशुराम ने शिव-शंकर की कठोर तपस्या कर प्रसन्न किया था।

तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको सांपों के राजा नागराज की पूजा करने की सलाह दी थी। जिससे कि मिट्टी में सांपों का जहर फैल जाए और भूमि उपजाऊ हो जाएगी। महादेव के कहे मुताबिक परशुराम भगवान ने मन्नारसला में नागराज की मूर्ति स्थापित की और फिर अनुष्ठान करने के लिए एक ब्राह्मण परिवार को नियुक्त किया। आज भी उस परिवार के लोग इस मंदिर में पूजा-अर्चना करते हैं। इन्हें इल्लम नाम से जाना जाता है।

मान्यता

मान्यता के अनुसार, जिस भी दंपति इस मंदिर में संतान की कामना लेकर जाते हैं। उसे संतान सुख प्राप्त होता है। बता दें कि मन्नारसला मंदिर में कई त्योहारों का धूमधाम से आयोजन होता है। भक्तों और पर्यटकों की मंदिर में भारी भीड़ उमड़ती है। मलयालम महीने थुलम में पड़ने वाला मन्नारसाला अयिल्यम त्योहार सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। वहीं यह पर्व सर्पबली के साथ समाप्त होता है। वहीं इस दौरान मंदिर जाने वाले निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है।

भारत के कई हिस्सों में बने हैं रावण के भव्य मंदिर...

रावण काफी ज्यादा विद्वान और बहु-विधाओं का जानकार था। जिस तरह से भगवान राम की पूजा होती है और उनके कई मंदिर बने हैं। उसी तरह भारत के कई हिस्सों में रावण को पूजनीय माना जाता है। हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण महाकाव्यों में रामायण शामिल है। इसके सभी पात्र विशेष महत्व रखते हैं और व्यक्ति को कुछ न कुछ संदेश देते हैं। भले ही रावण दुराचारी था, लेकिन दशानन काफी विद्वान और बहु-विधाओं का जानकार था।

सबसे फेमस मंदिर

बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के पास स्थित बिसरख गांव को रावण का जन्मस्थान माना जाता है। यहां पर लंकापति रावण का एक भव्य मंदिर बना है। जो रावण के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है।

दूर होंगे संकट

प्राप्त जानकारी के अनुसार, करीब एक सदी पहले इस स्थान की खुदाई में एक शिवलिंग पाया गया था। इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह वही लिंगम है। जिसकी दशानन रावण और उनके पिता पूजा किया करते थे। यही वजह है कि आज भी इस गांव में दशहरे के मौके पर कभी भी रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है।

रावण की पूजा

प्रदेश में स्थित मंदसौर में दशानन रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था। धार्मिक मान्यता के अनुसार, दशानन रावण की पत्नी मंदोदरी मंदसोर गांव की रहने वाली थी। मंदसौर के दामाद होने के कारण यहां पर भी रावण की पूजा-अर्चना की जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विदिशा गांव में भी रावण का एक बड़ा और भव्य मंदिर है।

काकीनाडा रावण मंदिर

आंध्र प्रदेश में भी दशानन रावण का एक फेमस मंदिर है। इस मंदिर को काकीनाडा रावण मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहां पर रावण की महादेव के प्रति भक्ति को दर्शाया गया है। मान्यता के अनुसार, इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की स्थापना स्वयं रावण ने की थी। वहीं यूपी के कानपुर में भी रावण का एक फेमस मंदिर है।

जिद्दी से जिद्दी पेट की चर्बी होगी दूर, इस तरह से पिएं लहसुन का पानी

गलत लाइफस्टाइल और खाने की आदते की वजह से आमतौर पर मोटापा बढ़ने लगता है। बार-बार पेट की चर्बी से हम सभी परेशान नजर आते हैं। एक बार पेट की चर्बी बढ़ जाएं तो इसे कम करने में बहुत मुश्किले आती हैं। क्या आप जानते हैं? लहसुन का पानी पीने से पेट की चर्बी कम हो जाती है।

आज के समय में फिट और हेल्थी रहना जरुरी है। भागदौड़ भारी लाइफस्टाइल के चलते गलत खानपान की वजह से पेट की चर्बी बढ़ने लगती है। पेट की चर्बी की वजह से कई बार आत्मविश्वास कम हो जाता है, वहीं खूबसूरती में भी रुकावाट बनती है। एक बार पेट चर्बी बढ़ जाए तो आसानी से नहीं खत्म होती। जिस वजह से कई बार हम सभी स्ट्रैस में आ जाते हैं, तो चिंता छोड़िए आज से ही लहसुन का पानी पीना शुरु कर दें, सेहत के साथ-साथ पेट की चर्बी भी होगी दूर।

लहसुन के पानी के फायदे

आयुर्वेद में लहसुन को सबसे बेहतरीन औषधि मानी जाती है। सेहत के लिए लहसुन का पानी पीना काफी फायदेमंद होता है। इससे मोटापे की समस्या भी दूर होती है। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, मैंगनीज, विटामिल बी6, विटामिन सी, सेलेनियम, फाइबर, कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, आयरन आदि होता है, जो वजन घटाने में मदद करता है।

सेहत को मिलते हैं लाभ

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, लहसुन का पानी सुबह के समय पीने से कई चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। इसके ने सेवन मात्र से ही कई कमाल दिखने लगते हैं। अगर आपको अपना वजन कम करना है तो लहसुन का पानी बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। खाली पेट लहसुन का पानी पीने से पेट की चर्बी को भी कम करने में मदद मिलती है।

इस तरह से पिएं लहसुन का पानी

दरअसल, लहसुन के फायदे ज्यादातर सभी जानते हैं, हालांकि कई लोग इसके सेवन का सही तरीका नहीं जानते हैं। पेट की चर्बी कम करने के लिए लहसुन को गर्म पानी में डालकर पीना चाहिए।

ओवरईटिंग से बचाव

अगर आप लहसुन का पानी पीते हैं, तो आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा और आप खुद को ओवरईटिंग से बचा पाएंगे। जब आप अनहेल्दी चीजों को कम खाएंगे तो वजन अपने आप आसानी से कम हो जाएगा। वहीं, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए लहसुन की ड्रिंक का सेवन करना सबसे बढ़िया है। लहसुन का पानी पीने से शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है।

इसका ज्यादा सेवन न करें

गर्मी के दौरान याद रखें कि लहसुन का ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको पेट में गैस बनती हैं, तो उन्हें लहसुन कम खाना चाहिए। वरना पेट से संबंधित रोगों का सामना करने पड़ सकता है।

पेट की जलन को शांत करने में कारगर ये मसाले

दिन पर दिन बढ़ती गर्मी की वजह से सभी लोगों का हाल-बेहाल है। खुद को गर्मी से बचाने के लिए हम खुद को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। खुद को ठंडा रखने के लिए तरह-तरह के ड्रिंक्स, ठंडी चीजों और न जाने क्या-क्या खाते हैं। इसके साथ ही गर्मी में ज्यादा मसाले खाने से परहेज करते हैं। जिससे कि पाचन बेहतर रह सके और हमारे शरीर का तापमान भी न बढ़ सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मसाले ऐसे भी होते हैं, जो हमारे शरीर को ठंडा रखने में सहायक होते हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको उन मसालों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी सहायता से आ अपने शरीर को ठंडा रख सकते हैं।

जीरा : खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों में जीरे का नाम सबसे ऊपर आता है। जीरा न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि यह हमारे पाचन को भी दुरुस्त रखता है और पेट को ठंडा रखता है। गर्मियों में इस मसाले का सेवन करना फायदेमंद होता है। इसको आप पानी में उबालकर भी पी सकते हैं और बॉडी डिटॉक्स में भी सहायक होता है।

इलायची : हम कई डेजर्ट्स में और माउथ फ्रेशनर की तरह इलायची का इस्तेमाल करते हैं। यह खाने की खुशबू और फ्लेवर को बढ़ाती है और गर्मियों में इसका सेवन करने से शरीर ठंडा रहता है। यह पाचन के लिए भी फायदेमंद होता है और इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज आपको ठंडा रखता है।

सौंफ : सौंफ का अधिकतर सेवन माउथ फ्रेशनर की तरह किया जाता है। यह पाचन में भी फायदेमंद होती है। गर्मियों में अक्सर लोगों को पाचन संबंधी समस्या होती है। यह इस समस्या को कम करने में सहायक होता है। साथ ही सौंफ ब्लोटिंग और गैस की समस्या को भी कम करता है।

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, जाने महत्व और पूजा विधि...

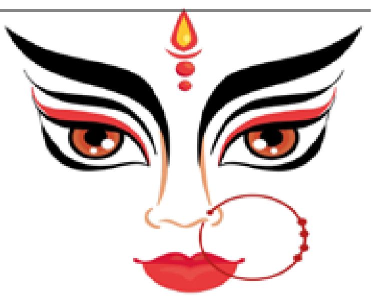

नवरात्रि पर्व शक्ति उपासना का पर्व है । ब्रह्मांड में विद्यमान प्रकृति वह शक्ति है जो जीवन की गतिविधियों में अपना योगदान देती है। आषाढ़ माह में मनाया जाने वाला यह गुप्त नवरात्रि पर्व सौभाग्य और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद लेकर आता है। इस वर्ष आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार से प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और मां दुर्गा के सभी स्वरूपों का स्मरण करना चाहिए। नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर मां का स्मरण करना चाहिए और उनके सामने तेल का दीपक प्रज्वलित करके उनकी पूजा शुरू करनी चाहिए।

साल में कितनी बार मनाई जाती है नवरात्रि?

नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। शक्ति की पूजा में कई नियमों का पालन किया जाता है। साल में चार बार नवरात्रि मनाई जाती है, जिनमें से दो बार बहुत ही विस्तार से मनाई जाती है। पहली चैत्र माह में मनाई जाने वाली चैत्रीय नवरात्रि और दूसरी आश्विन माह में मनाई जाने वाली शारदीय नवरात्रि। दूसरी दो नवरात्रि होती है जो गुप्त रूप से मनाई जाती हैं। यह नवरात्तंरी तन्त्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए सामान्य जन से अलग रह रहे लोग करते हैं। यह गुप्त नवरात्रि माघ माह और आषाढ़ माह में मनाई जाती है। मान्यता है कि इस गुप्त नवरात्रि में मां की आराधना करने से दस महाविद्याओं की सिद्धियां प्राप्त होती हैं।

कब से शुरू होगी गुप्त नवरात्रि इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई, शनिवार से शुरू होगी, जो 15 जुलाई, सोमवार तक रहेगी। यानी इस बार ये गुप्त नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिनों की होगा, ऐसा चतुर्थी तिथि की वृद्धि होने के कारण होगा।

गुप्त नवरात्रि के में होती है महाविद्या की पूजा की

गुप्त नवरात्रि एक चरण-दर-चरण प्रक्रिया है जिसमें शक्ति के सभी रंग प्रकट होते हैं। देवी काली, देवी तारा, देवी ललिता, देवी मां भुवनेश्वरी, देवी त्रिपुर भैरवी, देवी चिन्नमस्तिका, देवी मां धूमावती, देवी बगलामुक्की, देवी मातंगी और देवी कमला इस शक्ति पूजा में प्रकट होंगी। इन सभी शक्तियों की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिक साधना में की जाती है। गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं की पूजा को बहुत महत्व दिया जाता है। यह शक्ति के दस रूप हैं। प्रत्येक रूप अपने आप में पूर्ण है। इसमें ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली और उसके भीतर छिपे रहस्य शामिल हैं। महाविद्या सभी जीवित प्राणियों का पालन करती है। इन दस महाविद्याओं को तांत्रिक साधना में बहुत शक्तिशाली माना गया है।

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2024 की तिथियां

6 जुलाई, शनिवार- इस दिन से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरूआत होगी। इस दिन देवी शैलपुत्री की पूजा जाएगी।
7 जुलाई, रविवार- ये आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी।
8 जुलाई, सोमवार- आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है।
9 जुलाई, मंगलवार- ये गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि रहेगी। इस दिन देवी कूष्मांडा का विधान है।
10 जुलाई, बुधवार- इस दिन भी गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि रहेगी। इस तरह 2 दिन चतुर्थी तिथि होने से ये नवरात्रि 10 दिनों की मानी जाएगी।
11 जुलाई, गुरुवार- गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि पर देवी स्कंदमाता की पूजा की जाती है।
12 जुलाई, शुक्रवार- इस दिन गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि रहेगी। इस तिथि पर देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है।
13 जुलाई, शनिवार- आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर देवी कालरात्रि की पूजा का विधान है।
14 जुलाई, रविवार- इस दिन आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि रहेगी। इस दिन देवी महागौरी की पूजा की जाएगी।
15 जुलाई, सोमवार- ये गुप्त नवरात्रि की अंतिम दिन रहेगा। इस दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा मुख्य रूप से की जाती है।

इस तरह करें नवरात्रि में कलश स्थापना

आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि पर देवी की पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए।
स्नान आदि करके शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए पवित्र स्थान पर देवी की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर रखें
गंगा जल छिड़क कर स्थान को पवित्र करें।
देवी की विधि-विधान से पूजा प्रारंभ करने से पहले मिट्टी के पात्र में जौ के बीज बो दें
इसके उपरान्त माता की पूजा के लिए कलश स्थापित करें।
अखंड ज्योति का दिया जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ और उनके मंत्रों का पूरी श्रद्धा के साथ जप करें ।

आइसक्रीम, चिप्स और बर्गर से होता है स्ट्रोक का खतरा

सोचने-समझने की क्षमता में भी आ रही गिरावट

फ्राइज, चिप्स, बर्गर, कैंडी, सॉफ्ट ड्रिंक और आइसक्रीम जैसे अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स यानी बेहद ज्यादा प्रोसेस किए जाने वाले खाद्य पदार्थ लोगों को शारीरिक और दिमागी तौर पर बीमार बना रहे हैं। एक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि ऐसे खाद्य पदार्थों के ज्यादा सेवन से सोचने-समझने, पढ़ने, सीखने और याद रखने की क्षमता में गिरावट के साथ स्ट्रोक के खतरे बढ़ रहे हैं। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं के अध्ययन के नतीजे जर्नल न्यूरोलॉजी में प्रकाशित हुए हैं। यह अध्ययन अमेरिका में 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के 30,239 लोगों पर किया गया है। इन पर करीब ग्यारह वर्षों तक नजर रखी गई। शोधकर्ताओं ने इस बात की जांच की है कि उनका कितना भोजन बेहद ज्यादा प्रोसेस किया हुआ था। अध्ययन की शुरुआत में इन सभी लोगों में स्ट्रोक या सोचने-समझने तथा सीखने की क्षमता में गिरावट का कोई इतिहास नहीं था। अध्ययन के अंत तक 768 लोगों में संज्ञानात्मक हानि यानी सोचने समझने की क्षमता में गिरावट देखी गई जबकि 1,108 में स्ट्रोक की समस्या सामने आई।

8% बढ़ी स्ट्रोक की समस्या

शोध के अनुसार, दुनिया में करीब 14 फीसदी वयस्क और 12 फीसदी बच्चे अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स की लत के शिकार हैं। इन खाद्य पदार्थों को लेकर लोगों में जो लगाव है वह करीब-करीब शराब और तंबाकू जितना ही बढ़ चुका है। बहुत ज्यादा प्रोसेस किए खाद्य पदार्थों के सेवन में 10 फीसदी के इजाफे से याददाश्त से जुड़ी समस्याओं का खतरा 16 फीसदी तक बढ़ गया। दूसरी ओर बिना प्रोसेस किए भोजन के सेवन से जोखिम 12 फीसदी तक घट गया। इसी तरह इसका सेवन करने से स्ट्रोक का खतरा आठ फीसदी तक बढ़ गया, जबकि कम करने से स्ट्रोक का जोखिम नौ फीसदी तक घट गया।

ध्यान दें कि वे क्या खा रहे

मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉ. डब्ल्यू टेलर किम्बर्ली का कहना है कि हर व्यक्ति को न केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह क्या खा रहा है, बल्कि इस पर भी विचार करना चाहिए कि वह कैसे बनता है। इन खाद्य पदार्थों का सीमित सेवन दिमाग को स्वस्थ रखने में मददगार साबित हो सकता है।

हर साल 30 लाख मौतें

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े भी दर्शाते हैं कि हर साल जरूरत से ज्यादा नमक (सोडियम) का सेवन करने से दुनिया में 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। इसके साथ ही इसकी वजह से रक्तचाप और हृदय सम्बन्धी रोगों का खतरा भी बढ़ रहा है।

क्या होते हैं अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स

जब प्राकृतिक तरीके से प्राप्त खाद्य उत्पादों को कई लेवल पर प्रोसेस किया जाता है जिससे वह कई दिनों तक खाने योग्य बने रहें या फिर जब डीप फ्राई करके उनकी कुदरती संरचना को बदल दिया जाता है तो ऐसे खाद्य उत्पादों को अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स कहते हैं। इनमें आमतौर पर चीनी, वसा, नमक ज्यादा और प्रोटीन तथा फाइबर कम होते हैं।

कलौंजी को करें डाइट में शामिल, मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

वजन घटाने के लिए अपनी डाइट में बदलाव करना बेहद जरूरी है। इसमें आप कलौंजी को भी शामिल कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि कलौंजी में कुछ ऐसे एक्टिव इंग्रीडिएंट होते हैं जो फैट को कम करने में मदद कर सकते हैं।

भारत में मसालों के बिना हर व्यंजन अधूरा है। यूं तो हम अपनी किचन में कई तरह के मसालों का इस्तेमाल करते हैं और इसमें से एक कलौंजी भी है। इसे काला जीरा भी कहा जाता है। कलौंजी का उपयोग कई रूपों में किया जाता है जैसे कलौंजी का तेल, भुने हुए बीज, कच्चे बीज आदि। यह एक ऐसा मसाला है कि यह स्किन की कई समस्याओं से निपटने से लेकर थायरॉयड से लड़ने तक, कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें विटामिन, फाइबर, अमीनो एसिड, प्रोटीन, फैटी एसिड और कई अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको कलौंजी से मिलने वाले कुछ बेमिसाल फायदों के बारे में बता रहे हैं-

मेमोरी को करें बूस्ट

कलौंजी के बीज का सेवन करने से आपकी मेमोरी पर अच्छा असर पड़ता है। आप हर दिन कलौंजी के बीज को शहद में मिक्स करके ले सकते हैं। वहीं, आयुर्वेद में पुदीने की पत्तियों के साथ कलौंजी के बीज खाने की सलाह दी जाती है, जो याददाश्त को बढ़ाने और अल्जाइमर रोग जैसे न्यूरालॉजिकल डिसऑर्डर को रोकने में मदद कर सकते हैं।

वजन कम करने में मददगार

वजन घटाने के लिए अपनी डाइट में बदलाव करना बेहद जरूरी है। इसमें आप कलौंजी को भी शामिल कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि कलौंजी में कुछ ऐसे एक्टिव इंग्रीडिएंट होते हैं जो फैट को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसमें एंटी-ऑक्सिडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंट भी होते हैं जो वजन घटाने में भी योगदान दे सकते हैं।

उज्जैन के मंदिरों की दूर-दूर तक फैली ख्याति, दर्शन से खुल जाते हैं भाग्य...

आज हम आपको उज्जैन के पांच दिव्य मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन मंदिरों के बारे में कहा जाता है, कि यहां पर जाने भर के भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं इन मंदिरों के बारे में...

महाकालेश्वर मंदिर

उज्जैन में स्थित भगवान महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख पुराणों, महाभारत और कालिदास जी की रचनाओं में भी मिलता है। महाकालेश्वर मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि यदि दूर से भी किसी व्यक्ति को इस मंदिर के दर्शन हो जाएं और व्यक्ति मनोकामना मांगे, तो महादेव उस जातक की इच्छा जरूर पूरी करते हैं।

भारत देश में कई ऐसे फेमस और प्राचीन मंदिर हैं, जो बेहद चमत्कारी माने जाते हैं। इस मंदिरों में न सिर्फ रहस्यों का अंबार है, बल्कि माना जाता है कि मंदिर में दिव्य शक्तियों का संचार होता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना के साथ मंदिर में प्रवेश करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको उज्जैन के पांच दिव्य मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि यहां पर जाने भर के भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

देवी हरसिद्धि मंदिर

आपको बता दें कि शिप्रा नदी के पास देवी हरसिद्धि मंदिर है। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में भगवान शंकर मां गौरा के साथ विराजमान हैं। इस मंदिर में माता सती की कोहनी की पूजा-अर्चना की जाती है। वहीं मंदिर में महालक्ष्मी और महासरस्वती भी स्थापित हैं। मान्यता के मुताबिक इस मंदिर के दर्शन करने से व्यक्ति को जीवन में कभी धन-धान्य की कमी नहीं होती है।

मंगलनाथ मंदिर

उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। इस मंदिर का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। बताया जाता है कि वर्तमान समय में यह मंदिर उसी स्थान पर है, जहां पर मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। इस मंदिर के दर्शन मात्र से मंगल दोष दूर हो जाता है। वहीं मंदिर के दर्शन से कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और व्यक्ति को शुभ परिणाम मिलते हैं।

काल भैरव मंदिर

काल भैरव को भगवान शिव शंकर का रौद्र रूप माना जाता है। मुख्य रूप से तांत्रिक भगवान काल भैरव की पूजा-अर्चना करते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग भी काल भैरव की सात्विक पूजा कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति काल भैरव के मंदिर जाकर उनके दर्शन कर पूजा-अर्चना करता है, उसकी नकारात्मकता या बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं और नजर दोष भी उतर जाती है।

चौबीस खंभा माता मंदिर

उज्जैन में स्थित चौबीस खंभा माता मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। इस मंदिर यह नाम इसलिए पड़ा, क्योंकि मंदिर में चौबीस खंभे बने हुए हैं। बताया जाता है कि इस चौबीस खंभों की परिक्रमा करने के बाद यदि व्यक्ति माता रानी से कोई मनोकामना मागंता है, तो उसकी हर मन्नत पूरी होती है। वहीं यदि आपका कोई काम बिगड़ा हो या काम बन नहीं रहा हो, तो वह भी पूरा हो जाता है।

चिया सीड्स से दमकने लगेगी त्वचा, कैसे करें इस्तेमाल

चिया सीड्स एक माइल्ड एक्सफोलिएंट की तरह भी काम करता है। ऐसे में चिया सीड्स की मदद से फेस स्क्रब बनाना भी अच्छा विचार है। इसके लिए आप चिया सीड्स को पीस लें। अब इसमें नारियल तेल में मिक्स करें। चिया सीड्स के हेल्थ बेनिफिट्स किसी से छिपे नहीं हैं। यह ना केवल आपकी सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि इसे स्किन के लिए भी उतना ही लाभकारी माना जाता है। चिया सीड्स स्किन को हाइड्रेटेड बनाए रखने में मदद करते हैं। साथ ही, चिया सीड्स में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड रेडनेस को कम करने और स्किन को शांत करने में मदद कर सकते हैं। चूंकि, चिया सीड्स एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, इसलिए वे स्किन को अधिक लंबे समय तक यूथफुल बनाए रखते हैं। इससे स्किन रिजुविनेट होती है और उसकी रंगत भी बेहतर होती है। चिया सीड्स स्किन के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। आप इसे कई अलग-अलग तरीकों से अपने स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि आप चिया सीड्स से अपनी स्किन को पैम्पर किस तरह कर सकते हैं-

बनाएं फेस मास्क

चिया सीड्स को बतौर फेस मास्क अपनी स्किन पर लगाना अच्छा विचार है। इसे इस्तेमाल करने के लिए चिया सीड्स को रात भर पानी में भिगोएं। अगली सुबह इसकी जेल जैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अब इसे समान मात्रा में शहद या दही के साथ मिक्स करें और इसे फेस मास्क की तरह इस्तेमाल करें। आप चाहें तो भीगे हुए चिया सीड्स को मसले हुए केले या मसले हुए एवोकाडो के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। यह आपकी स्किन को टाइटन करेगा।

चिया सीड्स से बनाएं फेस स्क्रब

चिया सीड्स एक माइल्ड एक्सफोलिएंट की तरह भी काम करता है। ऐसे में चिया सीड्स की मदद से फेस स्क्रब बनाना भी अच्छा विचार है। इसके लिए आप चिया सीड्स को पीस लें। अब इसमें नारियल तेल में मिक्स करें। अब आप इसे बतौर फेस स्क्रब अपनी स्किन पर लगाएं और सर्कुलर मोशन में बेहद हल्के हाथों से मसाज करें।

धूप से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधना कितना सही है? हो सकती है स्किन एलर्जी

गर्मी का कहर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। गर्मी से बढ़ते तापमान के कारण लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज धूप और लू की वजह से कई लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर घर से बाहर निकलते हैं। आखिर क्या ऐसा करना कितना सही है, जानें। आग उगलने वाली गर्मी का कहर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। गर्मी के बढ़ते तापमान में आप न जाने कितने उपाय करके कॉलेज या ऑफिस जा रहे होंगे। गर्मियों के दिनों में कोई तो सनस्क्रीन का यूज करता है, तो कोई छाता लेकर चलता है। उन्हीं में कई लोग तो गमछा या स्कार्फ से मुंह ढककर जाते हैं। रास्ते में कई लोग देखने को मिलते हैं, जो किसी कपड़े से फेस को कवर करके जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मुंह पर कपड़ा बांधना कितना सही होता है? क्या ये फायदेमंद है या फिर इसके नुकसान भी है, आइए जानते हैं।

कपड़ा बांधना कितना सही है?

इन दिनों पुरुष और महिलाएं दोनों ही धूप से बचने के लिए चेहरे पर कपड़ा बांधकर बाहर निकलते हैं, ताकि टैनिंग से बचा जा सके। लेकिन क्या सचमुच में कपड़ा बांधने से आपकी स्किन टैन नहीं होगी या फिर धूप और धूल-मिट्टी से आपकी त्वचा कर नहीं पहुंच पाएगी। दरअसल, मुंह पर कपड़ा बांधने से बाहर की गंदगी कपड़े पर चिपक जाती है, जो स्किन से संबंधित कई समस्याओं को पैदा कर सकती है।

झेलनी पड़ सकती है दिक्कत

अगर आप भी लगातर कपड़े को मुंह में बांधकर घूमते हैं। ऐसे में इतने दिनों की जमी गंदगी आपके चेहरे को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे एक्ने, पिंपल्स, ऑयली स्किन, चेहरा फीका पड़ना और कई तरह की स्किन एलर्जी हो सकती है।

पसीना ला सकता है मुसीबत

अगर आप भी धूप से बचने के लिए स्कार्फ का यूज करती हैं और फिर वहीं कपड़े को बैग में रख लेती हैं। इससे स्कार्फ पर लगा पसीना सूखता नहीं है और जब आप फिर से इसका इस्तेमाल करती हैं, जिसमें फंगस लग सकती हैं, जो आपकी स्किन में एंटर कर सकता है।

कैसे करें बचाव?

इसके लिए आप धूप में जाने से पहले अच्छी तरह से सनस्क्रीन का प्रयोग करें। यह आपकी स्किन को टैनिंग से बचाएगा। जब आप घर से बाहर निकलें तो बैग में छाता लेकर निकले, जिससे आपकी त्वचा सीधे धूप के कोनटैक्ट से बचे।

बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक के लिए श्रीराम बालाजी को अपना जोड़ीदार चुना

रोहन बोपन्ना ने फ्रेंच ओपन में अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने वाले एन श्रीराम बालाजी को पेरिस ओलंपिक के लिए अपना जोड़ीदार चुना है और अखिल भारतीय टेनिस महासंघ (एआईटीए) के इस अनुभवी खिलाड़ी की पसंद पर आपत्ति जताने की संभावना नहीं है। बोपन्ना ने एआईटीए को ईमेल लिखकर अपने फैसले की जानकारी दी।

दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने फ्रेंच ओपन में अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने वाले एन श्रीराम बालाजी को पेरिस ओलंपिक के लिए अपना जोड़ीदार चुना है और अखिल भारतीय टेनिस महासंघ (एआईटीए) के इस अनुभवी खिलाड़ी की पसंद पर आपत्ति जताने की संभावना नहीं है। बोपन्ना ने एआईटीए को ईमेल लिखकर अपने फैसले की जानकारी दी। इस ईमेल को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) को भी भेजा गया है। एआईटीए ने भी इसकी पुष्टि की है। बालाजी और मैक्सिको के उनके जोड़ीदार एमए रेयेस-वारेला मार्टिनेज को सोमवार को फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल के तीसरे दौर में बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन को कड़ी चुनौती देने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा।

बालाजी ने अच्छी सर्विस करने के अलावा बेसलाइन और नेट पर अपने खेल से प्रभावित किया जिसके बाद बोपन्ना ने फैसला किया कि वह अगले महीने ओलंपिक पदक जीतने के अपने अंतिम अभियान के दौरान जब रोलां गैरो पर लौटेंगे तो कोयंबटूर का यह खिलाड़ी उनका जोड़ीदार होगा। बोपन्ना रियो खेलों के दौरान ओलंपिक पदक जीतने के करीब पहुंचे थे लेकिन उनकी और सानिया मिर्जा की जोड़ी को मिश्रित युगल के कांस्य पदक के मुकाबले में राडेक स्टेपनेक और लूसी हरादेका की चेक गणराज्य की जोड़ी के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बोपन्ना ने पेरिस से पीटीआई को बताया, ''मैंने एआईटीए को एक ईमेल भेजा है।'' बोपन्ना ने कहा कि राष्ट्रीय महासंघ से जवाब मिलने के बाद ही अपनी पसंद पर टिप्पणी करेंगे। विश्व रैंकिंग में 52वें नंबर के साथ भारत के दूसरे नंबर के युगल खिलाड़ी युकी भांबरी भी दावेदारी में थे।

युकी फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी के साथ फ्रेंच ओपन के पहले दौर से बाहर हो गए थे लेकिन इस सत्र में क्ले कोर्ट पर उन्हें सफलता मिली है। उन्होंने म्यूनिख में एटीपी 250 टूर्नामेंट जीता और इसी जोड़ीदार के साथ ल्योन में एक अन्य एटीपी 250 प्रतियोगिता में उपविजेता रहे। संपर्क किए जाने पर एआईटीए के महासचिव अनिल धूपर ने कहा कि उन्हें पेरिस ओलंपिक में 84वें नंबर के बालाजी के साथ बोपन्ना के खेलने पर कोई आपत्ति नहीं है। धूपर ने कहा, ''रोहन ने हमें लिखा है कि वह बालाजी के साथ खेलना चाहता है। बालाजी एक अच्छा खिलाड़ी है। उसने पाकिस्तान में भी अच्छा खेला है और मौकों का फायदा उठाया है। उसने मौजूदा फ्रेंच ओपन में क्ले कोर्ट पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है। बालाजी अच्छी सर्विस करने वाला खिलाड़ी है। अगर रोहन उसके साथ खेलना चाहता है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।''

उन्होंने कहा, ''फ्रेंच ओपन के समापन के बाद आईटीएफ को अंतिम सूची प्रकाशित करने दें। देखते हैं कि सुमित नागल भी इसमें जगह बना पाता है या नहीं। हम चयन समिति की बैठक करेंगे और बोपन्ना के फैसले को पैनल को बताएंगे जो अंतिम फैसला लेगा।'' चयन समिति का नेतृत्व पूर्व डेविस कप खिलाड़ी नंदन बाल कर रहे हैं जिन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे बोपन्ना का समर्थन करेंगे। बाल ने मुंबई से पीटीआई से कहा, ''मेरी निजी राय में, हमें रोहन को वह देना चाहिए जो वह चाहता है। आखिरकार, यह ओलंपिक पदक जीतने का उसका आखिरी मौका है और अगर उसे लगता है कि बालाजी के साथ खेलना बेहतर है तो वह निश्चित रूप से इस विकल्प को चुने।'' उन्होंने कहा, ''फिर भी जब भी एआईटीए बैठक बुलाएगा तो हम संयोजन पर चर्चा करेंगे।''

भारत की पूजा ने अमेरिका में बढ़ाया देश का मान

पूजा तोमर ने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में मुकाबला जीतने वाली देश की पहली मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर बनकर इतिहास रच दिया है। पूजा तोमर ने ये उपलब्धि यूएफसी लुइसविले में हासिल की, जहां उन्होंने शनिवार को स्ट्रॉ-वेट डिवीजन में ब्राजील की रेयान डॉस सैंटोस पर विभाजित निर्णय से जीत हासिल की।

भारत की पूजा तोमर ने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में मुकाबला जीतने वाली देश की पहली मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर बनकर इतिहास रच दिया है। पूजा तोमर ने ये उपलब्धि यूएफसी लुइसविले में हासिल की, जहां उन्होंने शनिवार को स्ट्रॉ-वेट डिवीजन में ब्राजील की रेयान डॉस सैंटोस पर विभाजित निर्णय से जीत हासिल की। नवोदित तोमर का मुकाबला उनके पक्ष में 30-27, 27-30, 29-28 के स्कोर के साथ समाप्त हुआ। अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद, तोमर ने आभार और गर्व व्यक्त किया।

उसने सोनी स्पोर्ट नेटवर्क को बताया कि, ये जीत मेरी जीत नहीं है। ये जीत सभी भारतीय फैंस और सबी भारतीय सेनानियों के लिए है। पहले, हर कोई सोचता था कि भारतीय सेनानी कहीं नहीं टिकते। मैंने केवल यही सोचा था कि मुझे जीतना है और दुनिया को दिखाना है कि भारतीय सेनानी हारे नहीं हैं।

उत्तर प्रदेरश के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना गांवा में जन्में तोमर पांच बार की राष्ट्रीय वुशु चैंपियन हैं और कराटे और तायक्वोंडो में भी उनकी पृष्ठभूमि है। अपने आत्मविश्वास के बावजूद, उन्होंने सुधार के क्षेत्रों को स्वीकार किया। मुझे जीत का भरोसा था, मैंने बहुत आक्रमण किया। लेकिन मैं अपना 100 प्रतिशत नहीं दे पाया। दूसरे दौर में मुझे दबाव महसूस हुआ। मुझे टेकटाउन जैसे कई कौशल में सुधार की जरूरत है।

तेजस्वी ने अपनी ताजा तस्वीरों से फैंस को कर दिया पानी-पानी...

तेजस्वी प्रकाश अपने खूबसूरत लुक से सभी को प्रभावित करने में कभी असफल नहीं होती हैं। जब भी वह सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालती हैं, तो हर कोई उनकी तस्वीरों को देखकर दंग रह जाता है...

तेजस्वी प्रकाश अपने खूबसूरत लुक से सभी को प्रभावित करने में कभी असफल नहीं होती हैं। जब भी वह सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालती हैं, तो हर कोई उनकी तस्वीरों को देखकर दंग रह जाता है। बुधवार को भी तेजस्वी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरें शेयर कीं, जो अब इंटरनेट पर आग लगा रही हैं। इन लेटेस्ट तस्वीरों में, तेजस्वी प्रकाश एक सीक्विन आउटफिट में पोज देती नजर आईं, जिसमें लंबी काली लेयर थी। उन्होंने कम से कम एक्सेसरीज के साथ गोल्डन हील्स पहनी थीं और अपने बालों को खुला रखा था। कहने की जरूरत नहीं है कि नागिन अभिनेत्री बेहद खूबसूरत लग रही थीं।

तस्वीरें शेयर किए जाने के तुरंत बाद, तेजस्वी प्रकाश के प्रशंसकों ने अभिनेत्री पर प्यार बरसाना शुरू कर दिया। एक फैन ने लिखा "हे भगवान.. हमेशा अपनी चमक बिखेरती रहने वाली तेजस्वी। दूसरे प्रशंसक ने लिखा "फुल ऑन फायर गर्ल," एक और ने लिखा "वाह...तुमने मुझे हद से ज्यादा हैरान कर दिया। ओह्ह्ह सच में प्यारी, चमकती हुई, बहुत ग्लैमरस, शानदार। आप बेदाग हैं।

तेजस्वी प्रकाश एक लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेत्री हैं, जो स्वरागिनी, रिश्ता लिखेंगे हम नया, पहरेदार पिया की और कर्ण संगिनी जैसे शो के लिए जानी जाती हैं। वह सलमान खान के बिग बॉस 15 की विजेता भी बनीं। तेजस्वी को एकता कपूर के लोकप्रिय शो नागिन के छठे सीजन में भी देखा गया था। 2022 में, तेजस्वी प्रकाश ने मन कस्तूरी रे के साथ अपनी मराठी फिल्म की शुरुआत भी की। यह संकेत माने द्वारा निर्देशित एक सस्पेंस रोमांटिक ड्रामा थी और इसमें अभिनय बेर्डे भी मुख्य भूमिका में थे। हाल ही में, तेजस्वी प्रकाश ने एक कार्यक्रम से अभिनेत्री का एक वीडियो वायरल होने के बाद भी सुर्खियां बटोरीं, जिसमें वह नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए रास्ता बनाती नजर आ रही थीं। जैसे ही सिद्दीकी बाहर निकल रहे थे और प्रकाश अंदर आ रहे थे, वह एक तरफ हट गईं और उनके जाने तक धैर्यपूर्वक इंतजार करती रहीं। वीडियो ने नेटिजेंस का ध्यान आकर्षित किया, जो उसके सम्मानजनक व्यवहार के लिए उसकी प्रशंसा कर रहे थे।

हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आसुरी शक्ति को समाप्त करने के लिए परशुराम बनना ही होगा।
विशेष चर्चा मैं बोले महामंडलेश्वर रामप्रिय दास जी। संरक्षक अखिल भारतीय हिंदू सेवादल

हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

हमारा देश हमारा अभिमान मासिक पत्रिका की प्रति बुक करने के लिए सम्पर्क करें..

मनोज चतुर्वेदी : 98266 36922, 88392 59136